MR. CHAIRMAN: No; she has not.

I think the House now allow me to proceed to the next item on the Order Paper.

ALLOTMENT OF TIME FOR CONSIDERATION AND RETURN OF THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1964

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that under rule 162(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I have allotted one hour and thirty minutes for the completion of all stages involved in the consideration and return of the Appropriation (No. 4) Bill. 1964, by the Rajya Sabha, including the consideration and passing of amendments, if any, to the Bill.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI SURENDRA MOHAN GHOSE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the following letter, elated 20th May, 1964 has been received from Shri Swrendra Mohan Ghose: —

> "I had a sudden heart attack for which I was removed to Balrampur Hospital, Lucknow. The doctors have advised complete rest, confined to bed for an indefinite period. For the present, at least for three weeks, I should remain so confined to bed in the hospital. Under these circumstances, it will not be possible for me to attend the Session of the Rajya Sabha which commences from the 27th of May. May I, therefore, request you to grant me leave of absence for the Session of the Rajya Sabha?"

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Su-rendra Mohan Ghose for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

(No hon. Member dissented.)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent granted.

STATEMENT *RE* THE MISSING AIRCRAFT ILYUSHIN-14

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI Y. B. CHAVAN) : Sir, in continuation of my statement in this House on the 3rd June, 1964 regarding the progress made in the search for the missing Ilyushin aircraft. I wish to inform the House that an army patrol has located the wrecked aircraft in an area two miles west of Tragm which is itself about 9 miles south, south-west of Banihal. Pieces of the wrecked aircraft are found scattered lying over a wide area. The body of the Tate Major-General R. S. Garewal, who was one of the passengers of the ill-fated aircraft has also been recovered from the site of the crash and identified. I am not, Sir, in possession of full details about the condition of the body. Parts of other human bodies have also been found. Nine mail bags, two beddings and a number of other articles have also been recovered. There is heavy and deep snow around the wreckage. The approach route is difficult and the weather has been inclement. These factors have impeded the salvage work. Weather permitting arrangements are being made to evacuate the body of the late Major-General Garewal by helicopter today.

THE CONSTITUTION (SEVENTEENTH AMENDMENT) BILL, 1964—*Continued*

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, संविधान में संशोधन का यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति द्वारा जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह रूप उसके पहले रूप से काफी भिन्न है । जब विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय इस दृष्टि से विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था तब यह आशंका प्रकट गई थी कि भूमि सुधारों के नाम पर उन किसानों को भी भूमि रखने के अधिकार से वंचित कर दिया जायगा जिनकी भूमि जोत

की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उन कानूनों के अन्तर्गत आती है। यह सन्तोष की बात है कि संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक में यह सुधार कर दिया है कि यदि किसान के पास जो सीलिंग के सम्बन्ध में कानून बने हैं, उनके अनुसार जो मर्यादा निश्चित की गई है उस मर्यादा के नीचे भूमि होगी तो उस भूमि का अधिग्रहण तभी किया जायेगा जबकि बाजार भाव से उन्हें उस भूमि का मूल्य पाने का अधिकार हो। मैं समझता हूं कि इस संशोधन का स्वागत किया जाना चाहिये।

भारतीय जनसंघ भूमि पर अधिकतम मर्यादा लगाने के पक्ष में है। इस प्रश्न को हम शहरों में जो सम्पत्ति है उसके साथ जोड़ कर देखने की गलती नहीं कर सकते। देश में भूमि की भूख बहुत प्रबल है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से कुछ हाथों में भूमि का एकत्रीकरण होना न उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायक होगा और न विषमता को कम करने के हमारे सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में मदद देगा। इस दृष्टि से अधिकतम जोत की मर्यादा लगाने के कानूनों का स्वागत होना चाहिये किन्तु इस संबंध में एक कठिनाई है। किसान के पास अधिक से अधिक कितनी भूमि रहे इसका निश्चय राज्य सरकारें करती हैं। इस विधेयक में इस बात की कोई गारंटी नहीं है, यदि राज्य सरकारें चाहें तो सीलिंग की मर्यादा को कम कर दें और किसानों के मन में एक अनिश्चितता उत्पन्न करें। प्रवर समिति में यह सुझाव दिया गया था कि कम से कम दस, पन्द्रह साल के लिये सीलिंग के सम्बन्ध में राज्यों में जो कानून बने हैं उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिये क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिये किसान प्रेरित हो उसके लिये जहां यह जरूरी है कि जमीन जोतने वाले को जमीन का मालिक बनाया जाय, वह अपने परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त करे और अधिकाधिक उत्पादन की वृद्धि में योग दे, वहां यह भी आवश्यक है कि किसानों के मन में एक निश्चितता का भाव पैदा किया जाय कि जिस जमीन के आज वे मालिक है वह जमीन निकट भविष्य में न तो उनसे छीनी जायगी और न उस जमीन की जोत की मर्यादा ही कम की जायगी। यह ठीक है कि ये कानून राज्यों के है लेकिन राज्यों में भी एक नीति के निर्धारण में कम से कम आज तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये जबकि सभी राज्यों में एक ही दल का शासन काम कर रहा है और शासक दल अपनी नीतियां सभी राज्यों से मनवाने की स्थिति में है। यदि हम सीलिंग सम्बन्धी कानूनों को संरक्षण देंगे—जैसा संरक्षण कि इस विधेयक के द्वारा दिया जा रहा है कि उन कानूनों को अब अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी—तो हमें इस बात का भी प्रबन्ध करना होगा कि राज्य सरकारों ने जो सीलिंग सम्बन्धी कानून इस समय बना दिये हैं उन कानूनों में निकट भविष्य में हेर फेर न किया जाये। उड़ीसा की कांग्रेस ने यह प्रस्ताव किया है कि किसान के पास अधिक से अधिक जमीन ६ एकड़ होनी चाहिये। यदि उड़ीसा की कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी के इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करेगी तो वहां के कानून को बदलना होगा। इसके फलस्वरूप किसानों के मन में अनिश्चितता पैदा होगी, भविष्य के बारे में वे आशंकावान होंगे और अनिश्चित मन से, संशकित स्थिति में, उत्पादन बढ़ाने के लिये जितना परिश्रम और साधन जटाने चाहियें उतने साधन नहीं जुटा सकेंगे। मैं मांग करता हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती जिसके अनुसार सीलिंग केसम्बन्धमें बनेहुए कानूनों को निकट भविष्य में बदला न जाय तो भी राज्य सरकारों से परामर्श करके उसे यह घोषणा करनी चाहिये कि जो सीलिंग के कानून बन गये है और उनके अन्तर्गत जितनी जमीन एक किसान को, कृषक परिवार को, मिल गई है, उसकी वह जमीन निकट भविष्य में ली नहीं जायगी। हां, दस पन्द्रह साल बाद अगर समाज की बदली हुई परिस्थिति में हम सीलिंग सम्बन्धी

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

कानूनों में पुनर्विचार करना चाहें तो हमें आपत्ति नहीं होगी । लेकिन निकट भविष्य में किसानों को पूरा आश्वासन दिया जाना चाहिये कि सीलिंग के अन्तर्गत उनके पास जितनी जमीन है उस जमीन के वे मालिक रहेंगे, उस जमीन म वे रुपया लगाएं, खेती की उन्नति के साधन अपनाएं और अपनी स्थिति भी सुधारें और देश में जो अन्न के अभाव की स्थिति है उसे भी पूरा करें । मैं आशा करता हू, केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करेगी । इस प्रश्न को हम राज्यों के ऊपर नहीं छोड़ सकते और अगर राज्यों के ऊपर छोड़ना है तो फिर यह संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी । हम राज्यों को कानूनों का संरक्षण दे रहे हैं तो हम उनसे मांग कर सकते हैं कि वे सीलिंग सम्बन्धी कानूनों के साथ खिलवाड़ नहीं करें ।

सभापति जी, इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू भी है—सीलिंग के अन्तर्गत अधिकतम मर्यादा कौनसी हो और सीलिंग लागू करते हुए जोतबन्दी लागू करते हुए, कौनसी बातें ध्यान में रखी जायं । इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने कुछ नीतियां निर्धारित की थीं । वे नीतियां राज्य सरकारों को भेजी गई जिसके अनुसार वे सीलिंग के सम्बन्ध में अपने कानूनों का निर्माण करें । लेकिन संयुक्त प्रवर समिति में हमें यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राज्यों ने सीलिंग के सम्बन्ध में अलग अलग नीतियां अपनाई । किसी राज्य में जो गन्ने के फार्म हैं उनको सीलिंग कानून के अन्तर्गत नहीं लाया गया, उन फार्मों को सीलिंग की परिधि से छोड़ दिया गया, जबकि किसी अन्य राज्य में गन्ने के फार्म जो भी सीलिंग के अन्तर्गत ले लिया गया है और हमारी संसद या सदन इस स्थिति में रख दिये गये हैं कि हम एक राज्य के उस कानून को भी संरक्षण दे रहे हैं जिसमें गन्ने के फार्म को सीलिंग में लाया गया है और दूसरे राज्यों में ऐसे कानून को संरक्षण दे रहे हैं जिसके अन्तर्गत गन्ने के फार्मों को सीलिंग के अन्तर्गत लाया नहीं गया । महाराष्ट्र से जो प्रतिनिधि संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख आए थे उन्होंने इस बात की शिकायत की । यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरा दल भी इस बात के हामी हैं कि सीलिंग का कानून सभी तरह की फसलों पर लागू होना चाहिये लेकिन अगर योजना आयोग की सिफारिश यह है कि गन्ने के फार्म, चाय के, काफी के फार्म और अच्छी तरह से एफीशियंटली रन मैकनाइज्ड फार्म सीलिंग के अन्तर्गत न आएं तो योजना आयोग को इस नीति को सभी राज्यों में मनवाना चाहिये था । लेकिन राज्यों की नीति भिन्न-भिन्न है और फिर संसद से सभी राज्य अपने कानूनों के लिये संरक्षण की मांग करते हैं तो इसमे एक राज्य के नागरिक की तुलना मे दूसरे राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव होने की अन्याय होने की आशंका है और संसद को कहा जा रहा है कि वह इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति पर अपनी मोहर लगा दे ।

[THE DEPUTY-CHAIRMAN in **the** Chair].

मैं समझता हूं कि अभी भी केन्द्रीय सरकार को, योजना आयोग को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि सीलिंग के सम्बन्ध में सभी राज्यों में एक से कानून हों, क्योंकि अगर सभी राज्यों में से एक से कानून नहीं होंगे तो उससे कठिनाइयां पैदा होंगी लोगों में एक दूसरे के विरुद्ध बातें कहने की प्रवृत्ति बल पकड़ेगी । इस दृष्टि से सभी राज्यों के कानूनों मे एकरूपता लाने की बड़ी आवश्यकता है ।

तीसरी बात यह है कि जब विधेयक सदन में पहली बार प्रस्तुत किया गया तब उसमें १२४ अधिनियम जोड़े गए थे जो नाइन्थ शिडयल मे, नवें परिशिष्ट में, रखे जाने थे । बाद में उनकी संख्या घटाई गई और यह काम जिस तरह से किया गया उससे ऐसा लगता है कि विधि मन्त्रालय ने इस बात का विचार

नहीं किया कि भूमि सुधार लागू करने के लिये किस कानन को संविधान में संरक्षण देना जरूरी है और किस कानून को संरक्षण देना जरूरी नहीं है । अगर विधि मन्त्रालय ने ठीक तरह से विचार किया होता तो पहले विधेयक में, संयुक्त प्रवर समिति को भेजने से पहले, १२४ कानूनों की लम्बी सूची न दी जाती । फिर संयुक्त प्रवर समिति में कहा गया कि अब सूची घटाई जा रही है और सूची ८८ कर दी गई । फिर एक नयी सूची कर दी गई जिसमें कहा गया कि आप ८ या ९ कानून और शामिल कर लीजिए । मैं समझता हूं, सारा काम जिस ढंग से हुआ है वह यह बताता है कि विधि मन्त्रालय में संशोधन करने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी अपने दिमाग में यह निश्चय नहीं कर पाता कि कौन से कानून संरक्षण चाहते हैं और कौन से कानूनों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है । हम यह चाहते हैं कि भूमि सुधार के काम में देरी नहीं होनी चाहिये और अगर कोई ऐसा कानून हो जिसे उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है और उससे बहुत से लोगों के प्रभावित होने की सम्भावना है तो उस कानून को संसद अपना विशेष संरक्षण दे उसके हम खिलाफ नहीं हैं । लेकिन इस विधेयक में ऐसे कानून भी शामिल कर दिए गए हैं जिनकी वैधता को न तो अभी तक चुनौती दी गई है,न जिन्हें किसी न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक रद्द किया है । हां, विधि मन्त्रालय के दिल में शंका है कि इस कानन को कभी चुनौती दी जा सकती है और जिसको कभी चुनौती दी जा सकती है उसको अभी से संरक्षण दे दिया जाय । यह सोचने का तरीका ठीक नहीं है । सीलिंग से सम्बन्धित कानूनों की एक दो धाराओं को छोड़ कर, बाकी को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वीकृति दे चुके हैं । सीलिंग लगाना, अधिकतम जोत की मर्यादा लागू करना––यह हमारे संविधान की धाराओं के खिलाफ नहीं है, यह सम्पत्ति रखने के मौलिक अधिकार के खिलाफ भी नहीं है ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में कहा जाता है है कि सम्पत्ति कमाने, उसे रखने का अधिकार मूलभूत अधिकार है और यह विधेयक उस पर प्रहार कर रहा है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि व्यक्ति को सम्पत्ति कमाने का, सम्पत्ति को रखने का अधिकार होना चाहिये और लोकतन्त्र में हम इस अधिकार को मिटा नहीं सकते । लेकिन कोई भी अधिकार बिना मर्यादा के नहीं हो सकता है । जहां हम अधिकार देते हैं वहां उसके साथ उसकी मर्यादा भी लगी हुई है । हम किसी को अनाप शनाप दौलत का अम्बार खड़ा करने की छूट नहीं देना चाहते हैं । जब समाज, विशेष रूप से उसका बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं भी अभी प्राप्त नहीं हुई तब सम्पत्ति के अधिकार पर भी हमको मर्यादा लगानी होगी । मर्यादा लगाने में मतभेद नहीं है । लेकिन मतभेद इस बात में है कि क्या बड़ी जायदाद पर मर्यादा लगाना और छोटी सी, मेहनत की कमाई को ले लेना, इन दोनों में कोई अन्तर होना चाहिये या नहीं होना चाहिये ? देशी रियासतें खत्म हो गई, जमींदारियां मिट गई, ताल्लुकेदारियां समाप्त हो गई––हमने उसका विरोध नहीं किया । विरोध करने की आवश्यकता भी नहीं थी । बदलती हुई व्यवस्था समय के अनुकूल होनी चाहिये और जो इस काल के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करेंगे वे प्रवाह को तो नहीं रोकेंगे, शायद वे उठा कर प्रवाह के किनारे फेंक दिये जायेंगे । लेकिन मुझे डर है कि कहीं छोटे किसान भी अपनी छोटी जमीनों से वंचित नहीं कर दिये जायें । क्या उसे पूरा मुआवजा मिलेगा ? गाजियाबाद के किसान मुआवजे के लिये किस तरह से संसद के दरवाजे पर सर टकराते रहे हैं, उसको हम भुला नहीं सकते । हम बड़े लोगों को उनकी पूरी जायदाद का पूरा मुआवजा नहीं दे सकते हैं । उसको तो जनहित में कम करेंगे । लेकिन छोटा किसान, छोटा दुकानदार, जो श्रमजीवी है, मेहनतकश है, वह अपनी जायदाद को कमा

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

सके, उस जायदाद का उपभोग कर सके, उस जायदाद का संरक्षण किया जाय, इस बात की पूरी व्यवस्था आवश्यक है। लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत जिस तरह के कानूनों को संरक्षण दिया गया है उससे मन में आशंका पैदा होती है। सरकार समझती है कि संविधान मे संशोधन किया जा रहा है इसलिए जो भी कानून अदालत मे जा सकते हैं, भले ही उन कानूनों का सम्बन्ध भूमि सुधार मे न हो, उन कानूनों को भी संरक्षण दे दिया जाय। उदाहरण के लिये मैसूर का एक कानून इसमें शामिल किया गया है जिसमे १२ हजार लोगों की नौकरियों को खत्म करने का सवाल है। यह ठीक है कि वे नौकरियां परम्परा से चलती आ रही हैं, बाप की जगह बेटा नियुक्त किया जाता है, बेटे की जगह पोता नियुक्त किया जाता है। स्वतन्त्र भारत में और लोकतन्त्रीय भारत मे, ऐसे जन्म के आधार पर इस प्रकार की नौकरियां चलें, उसे हम उचित नहीं समझते हैं। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस कानून को जिसे "मैसूर विलेज आफिसेज एबोलिशन ऐक्ट" कहते हैं और जिसे इस विधेयक में संरक्षण के लिए शामिल किया गया है, उस कानून का भूमि सुधार से क्या सम्बन्ध है? अगर वह कानून पास नहीं होगा, अगर संसद उस कानून को संरक्षण नहीं देगी तो हो सकता है कि १२ हजार लोगों की नौकरियां आज खत्म करना सम्भव नहीं हो। लेकिन क्या मैसूर में भूमि सुधार का काम रुक जायेगा अगर इन १२ हजार लोगों की नौकरियां बनी रहेंगी? हम उस कानून को संरक्षण कैसे दे सकते हैं क्योंकि यह तो अपवाद के लिए व्यवस्था है। संविधान मे जो मूलभूत अधिकार दिये गये है उनके अन्तर्गत उनका उपयोग करके कोई किसी कानून को चुनौती नहीं दे सकेगा। इसी चीज के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है और संविधान मे संशोधन किया जा रहा है ताकि उन कानूनों को चुनौती न दी जा सके। मगर हम इस अवसर का उपयोग उन कानूनों को इस विधेयक में शामिल करके नहीं कर सकते हैं जिन कानूनों का सम्बन्ध भूमि सुधार से नहीं है। किंतु शायद मैसूर सरकार यह सोचती है कि यह एक अच्छा मौका है, संविधान में संशोधन हो रहा है, यह कानून हमें परेशान कर रहा है, वह कानून परेशान कर रहा है।

SHRI M. GOVINDA REDDY (Mysore) : May I say a word about it? It was perhaps because some of the village officers had land grants as their remuneration that this Act has been included. That is all.

SHRI A. B. VAJPAYEE: If they had grants and if the grants are to be paid in cash.

SHRI M. GOVINDA REDDY: They were *inams.*

SHRI A. B. VAJPAYEE: Even then it is an entirely different matter. It relates only to 12,000 persons. It should not have been brought into this Bill.

SHRI M. GOVINDA REDDY: But they were by way of inams. That is why they had to be resumed.

SHRI A. B. VAJPAYEE: But I fail to understand how the process of land reforms is retarded. Even if we say that those 12,000 persons are allowed to keep their land, how is the process of land reforms retarded? It might affect to some extent.

SHRI M. GOVINDA REDDY: Those *inams* had to be resumed.

SHRI B. RAMAKRISHNA RAO (Andhra Pradesh): If that Act is not included in the Schedule, it will not be applicable to the tenants of those lands. That is why that law is being protected.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Do they have land above the ceiling limit?

THE DEPUTY MINISTER nsr THE MINISTRY OP LAW (SHRI BIBUDHENDRA MISRA) : It relates to land reforms in the sense that all these people were granted land in lieu of services. They no longer perform the services. How do you take away

the land? You have to pass an Act saying that since the services are not performed, the lands had to be taken away. They are no longer performing the aervices. In that way it has been done.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Even now I am not convinced. If they are not performing the services, still they possess the land. If they are prepared to cultivate the land and if the area of the land is under the ceiling limit, then there is no need to deprive them of their land.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: In the Act also provision for compensation is there.

श्री ए० बी० वाजपेयी : एक आशंका है जो संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में प्रकट की गई है । आशंका बलवती है जिसका निराकरण करना चाहिये । बहुत से समाधान सीलिंग के सम्बन्ध में परिवर्तन करके कर दिये गये हैं मगर यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि सीलिंग के कानून का उपयोग इस तरह से नहीं किया जायेगा कि किसानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सहकारी खेती में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाय । यह आशंका व्यापक है कि कांग्रेस ने नागपुर के अधिवेशन में सहकारी खेती का निश्चय किया है। सहकारी खेती के सम्बन्ध में दो मत हैं और यह समझने का कोई कारण नहीं है कि सहकारी खेती लागू करते ही हमारी सारी भूमि सम्बन्धी समस्याएं, उत्पादन की समस्याएं हल हो जायेंगी । जिन लोगों ने सहकारी खेती लागू की है, उन कम्युनिस्ट देशों में भी खेती का अनुभव अच्छा नहीं है । यदि मैं स्पष्ट कहूं तो कम्युनिस्ट देशों का तरीका अपना कर हम अपने देश में न तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं और न व्यक्ति की स्वाधीनता ही कायम रख सकते हैं। अगर कुछ किसान मिल कर काम करना चाहते हैं, मिलकर जोतना चाहते हैं, मिलकर सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहते हैं, जो उपज है उसको मिलकर बेचना चाहते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । वे मिल कर काम करने के लिये स्वतन्त्र हैं और शासन उन्हें प्रोत्साहन दे सकता है । लेकिन यदि किसान नहीं चाहता कि उसकी भूमि सारे गांव की भूमि में मिला दी जाय, वह अपनी भूमि पर अपना स्वामित्व कायम रखना चाहता है, वह अपनी जमीन का मालिक बन कर रहना चाहता है और अपनी जमीन को जोतना और बोना चाहता है तथा मरने के बाद अपनी जमीन को अपने बेटों को दे कर जाना चाहता है, तो ऐसे किसान को जबर्दस्ती कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल होने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये । यह आशंका है कि सरकार इस तरह की बात करने जा रही है और इस आशंका को दूर किया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि सहकारी खेती स्वेच्छा पर आधारित होगी । लोग जब चाहेंगे तभी मिल कर खेती करेंगे और तब ही सहकारी खेती लागू की जायेगी । सहकारी खेती लादी नहीं जायेगी । यदि लादी जायेगी तो वह सहकारी खेती नहीं होगी, सरकारी खेती होगी । लेकिन अगर कानून का उपयोग किया गया सहकारी खेती लादने के लिये, किसानों को उनकी भूमि से वंचित करने के लिए, तो संविधान में संशोधन करके लोगों के असन्तोष को आप रोक नहीं सकते हैं । ऐसा व्यापक आन्दोलन देश में खड़ा नहीं होगा जिसके सामने सरकार को जनमत का आदर करना पड़ेगा । लेकिन किसानों के मन में किसी तरह की कोई आशंका पैदा न होने दें, यह आशंका अब भी जोर पकड़ती जा रही है ।

इस कानून में, इस विधेयक में, गुजरात के एक ऐसे कानून को जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत किसी किसान की जमीन

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

सहकारी खेती में तबदील की जा सकती है और फिर वह किसान उस मामले को अदालत में नहीं ले जा सकेगा और न चुनौती ही दे सकेगा। हम उस कानून को इस विधेयक द्वारा संरक्षण दे रहे हैं। सीलिंग के सम्बन्ध में बने हुए कानूनों को—अगर कुछ राज्यों में सीलिंग कानून ऐसे हैं जिनसे आप चोर दरवाजे से सहकारी खेती लाना चाहते हैं—तो मेरा निवेदन है कि सहकारी खेती लाना है तो खुले दरवाजे से लाइये, चोर दरवाजे से नहीं। सहकारी खेती के सम्बन्ध में हम किसी कानून को संरक्षण नहीं दे सकते। क्योंकि सहकारी खेती एक ऐसा विषय है जिस पर व्यापक मतभेद है। और सरकार भी स्वीकार करेगी कि किसानों की इच्छा के विरुद्ध उन पर सहकारी खेती नहीं लादी जानी चाहिये। लेकिन हमने गुजरात के जिस कानून को संरक्षण दिया है उसमें यह व्यवस्था है कि किसानों की जमीन सहकारी समिति को स्थानान्तरित कर दी जाय और किसान अदालत का दरवाजा न खटखटा सके। सहकारी खेती लाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि जमीन का मालिक तो किसान ही बना रहे कागज में, कानून में, लेकिन जोतने के लिये वह जमीन सहकारी समिति के जिम्मे कर दी जाय। मैं समझता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं होगा। इसलिये ऐसे कानून जो किसानों के मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा करते हैं, उन कानूनों को भी अगर संरक्षण दिया जायगा तो फिर इस प्रचार को रोका नहीं जा सकता कि सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है, किसानों को उसकी जमीन से वंचित करना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसा सरकार का इरादा नहीं है और ऐसा सरकार को करने की इजाजत दी भी नहीं जायगी। । लेकिन जब आप ऐसा करना नहीं चाहते, आपकी घोषित नीति यह है कि किसानों को उनकी इच्छा से किसी भी खेती के प्रबन्ध में शामिल करें, तो फिर ऐसा कानून बनाने की क्या आवश्यकता है और उन कानूनों को संसद् के द्वारा संरक्षण दिलाना क्यों जरूरी होना चाहिये जो कानून किसानों के मन में यह भय पैदा करते हैं कि उनकी जमीन कभी छीन ली जायगी ?

महोदया, जो प्रश्न मैंने उठाये, उनका विधि मंत्री महोदय समाधानकारक उत्तर देंगे, इसकी मुझे आशा नहीं है क्योंकि वे तुले हुए हैं कि संविधान में संशोधन हो जाय और इसे जल्दी से जल्दी लागू करें। मैं संविधान में संशोधन का विरोधी नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो संविधान को पूजा की वस्तु मानते हैं और यह समझते हैं कि उसमें बदल नहीं होने चाहिये, उसमें परिवर्तन नहीं होने चाहिये। हम क्रांतिकारी काल में रह रहे हैं। सन् १९५० में जब संविधान बना, तब से परिस्थिति बदल रही है, जनता की भावनाएं परिवर्तित हो रही हैं। अगर अमेरिकी राजदूत के शब्दों में कहा जाय तो :

"We are witnessing a revolution of rising expectations."

लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। उसकी तुलना में हमारी उपलब्धियां, हमारी पूर्तियां कम हैं और बढ़ती हुई आकांक्षाएं और हमारे किये गये कामों के बीच में जो खाई है वह अगर बढ़ती गई तो लोकतन्त्र के लिये ही खतरा नहीं पैदा होगा, इस देश के स्थायित्व के लिये भी खतरा पैदा हो जायगा। इसलिये सामाजिक न्याय देने के लिये, देश में ऐसी व्यवस्था लाने के लिये, जो शोषण पर आधारित न हो, पोषण पर आधारित हो, जिसमें हर व्यक्ति समान रूप से प्रगति कर सके, आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करना चाहिये। लेकिन संविधान में संशोधन का आवरण ले कर के ऐसे कानून को शामिल करना उचित नहीं है जिनकी वैधता को अभी तक चुनौती नहीं दी

गई और न जिन्हें किसी हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अवैध घोषित किया है । यह परम्परा अच्छी नहीं है । अगर कोई राज्य सरकार या राज्य विधान सभा ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की वर्तमान मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है तो उस कानून को अदालतों में चुनौती दी जानी चाहिये और अगर अदालत उस कानून को रद कर दे तो विधान सभा को उस कानून में संशोधन करना चाहिये । हम अपवाद कर सकते हैं, मगर इस बात को नियम नहीं बना सकते कि राज्य विधान सभायें, राज्य सरकारें कोई भी कानून बनायें और यदि वे कानून संविधान की भावना के विपरीत जाते हैं और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद करते हों, तो संसद् में आ करके हम कहें कि इन कानूनों को हमारा संरक्षण मिलना चाहिये और कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत के दबाव के आधार पर ऐसा संरक्षण उन्हें प्रदान कर दे । आखिर हम एक संघीय पद्धति में रहते हैं जहां कानून बनाना विधान मंडलों का और संसद का कार्य है और कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है । यदि हमने ऐसी प्रवृत्ति का पनपने दिया कि विधान सभाएं और संसद् चाहे जैसे कानून बनाये और फिर अदालतों का उन कानूनों की आलोचना करने का, उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार हम सीमित कर दें इस तरह का संविधान में संशोधन ला करके, तो यह भारतीय गणराज्य के लिये बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा । अपवाद के लिये हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कुछ कानूनों को संरक्षण दिया जाय क्योंकि भूमि सुधार रुक नहीं सकता. उसमें काफी देरी हो गई है । भूमि सुधारों में मुझे शक है कि राज्य सरकारें भूमि सुधार लागू करने में ईमानदार भी है या नहीं । सीलिंग का कानून तब बनाया गया जब लोगों ने अपनी सारी जमीन घर वालों में बांट दी । सीलिंग का कानून लागू करने का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो फालतू जमीन बचे वह ऐसे लोगों को दी जाय जो बेजमीन हैं । जिनके पास मेहनत तो है मगर मेहनत के अलावा साधन नहीं है, वे जमीन के मालिक बनें और वे उत्पादन की प्रगति में योग दें, हम यह चाहते थे । मगर सीलिंग कानून बने तो देर से बने और इस ढंग से बने कि फालतू जमीन बचे ही नहीं । सारी जमीन घर वालों में बांट दी गई । खैर, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, बांट दी गई तो भी इकट्ठे हाथ में नहीं रही । लेकिन जो जमीन सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास है, केन्द्रीय सरकार के पास पड़ती जमीन पड़ी है, खेती के लिये जिस जमीन को उपयोगी बनाया जा सकता है, भूमिहीनों को जिस जमीन का मालिक बनाया जा सकता है, उस जमीन को खेती के योग्य बना करके भूमिहीनों में वितरित करने के लिये राज्य सरकारों ने क्या किया है ? हमारे विधि मंत्री कहेंगे कि इस प्रश्न का उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । बात ठीक है । यह कानून का सवाल नहीं है । लेकिन राज्य और केन्द्रीय सरकारें जो भूमि सुधारों का ढोल पीटती हैं और भूमि सुधारों के नाम पर संविधान में संशोधन किया जाय इस बात पर भी बल देती हैं, तो राज्य सरकारों से और केन्द्रीय सरकार से पूछा जाना चाहिये कि जो पड़ती जमीन पड़ी है, जो जमीन उपजाऊ बनाई जा सकती है, उस जमीन को उपजाऊ बना करके भूमि हीनों में बांटने के लिये उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाये । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का जो काम है वह सन्तोषप्रद नहीं है । केन्द्रीय सरकार भी जो केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में क्रांतिकारी नीति नहीं अपना सकी हैं । नतीजा यह हो रहा है कि भूमि की भूख बनी हुई है और उत्पादन की वृद्धि के लिये किसानों को, मजदूरों को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिये, उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है ।

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, केन्द्रीय सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी और अगर इस विधेयक में उन सुझावों को शामिल करना संभव न हो तो भी नीति के तौर पर यह स्पष्ट रूप से घोषित करे :

(१) किसी भी किसान को उसकी इच्छा के खिलाफ सहकारी खेती में शामिल करने के लिये विवश नहीं किया जायेगा ।

(२) भूमि की अधिकतम मर्यादा के जो कानून राज्यों में बन चुके हैं, सीलिंग के कानून बन चुके हैं, दस, पन्द्रह आने वाले वर्षों में उन कानूनों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

इससे किसानों में विश्वास पैदा होगा कि उनकी जमीन छीनी नहीं जायेगी और भूमि सुधारों के द्वारा सामाजिक न्याय और उत्पादन वृद्धि के हम जो दो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The lunch hour is cancelled. Even so, there are 18 more names here before me. The Minister will reply at 3-30 P.M. So, I request the Members not to exceed ten minutes each.

DR. S. CHANDRASEKHAR (Madras): Madam Deputy Chairman, I rise to support this Bill before the House. I shall not take very many minutes excepting to answer four or five objections raised by the Opposition. I need not repeat the need for this Bill before the House after the lucid and brief introductory remarks made by the hon. Minister. We are dedicated to the pursuit of a society based on social justice, with reduced economic inequalities and of promoting a socialistic pattern of society eventually within the framework of democratic, parliamentary, representative, political institutions. **And** in. **the'** light of this ideal, it is obvious that a large segment of the population, namely, the millions who work on the land, has never received a fair deal and therefore it is incombent and imperative that the Government should pursue the idea of giving them a fair return and that it should provide land for the landless, that is for those who actually till the soil. Therefore, the question of putting a ceiling on land-ownership has been pursued and the people who really have rights to land, in the sense of working on it, should be protected. Obviously, the situation has come in conflict with the fundamental rights in the Constitution in the light of certain strictures from the Supreme Court.

This amendment has been brought forward to make the State land ceiling legislation acceptable. A complicating factor has been the reorganisation of the States and the different patterns of land systems in several parts of this country. And, therefore, in this measure I even see an effort at evolving an integrated and uniform pattern of justice to the largest segment of the working population of this country—the agriculturists.

The first objection especially from the Swatantra Party—I think the hon. Members opposing it are not there— is that the Government seems to be in great haste, unholy haste to amend the Constitution. The Government seems to be in a mad rush when other means are easily available to achieve the desired ends, they say. The answer is very simple. Our Constitution is not something permanent, sacrosanct and immutable, lasting for ever. After all, the Constitution is made by man and it should serve the ends of man and not the other way round.

It is true, Madam, that we have been amending the Constitution very frequently. It is pointed out that in

the United States eighteen amendments to the Constitution have taken them. 200 years whereas we have had as many amendments in the course of 17 years. The answer is very simple. Our needs, our demands of social justice and economic amelioration of the people of this country have demanded that these amendments have to be undertaken and, therefore, 1 do not think that we are really treating the Constitution with scant respect as the Opposition has made out. 1 do not think we ought to take the objection seriously that we are amending the Constitution according to our whims and fancies. The amendment is necessary because there is need for it and we are driven to do it because the objectives have to be achieved. Therefore, we ought not to attach any great importance to this objection much as we like to really respect our Constitution.

Secondly, jt is said that this is bypassing the Supreme Court of the country. With all respect to the law courts of this country, it must be pointed out that this amendment is not really negativing, by passing or stultifying the legislation or the directives of the Supreme Court. On the contrary, I think we are respecting the Supreme Court by attempting to remove certain mistakes that we have committed in the light of the strictures passed by the Supreme Court. And, therefore, in one sense we are bowing to the decision of the Supreme Court and not bypassing, or stultifying or, shall we say, super-arrogating to ourselves the duties of the Supreme Court and the High Courts. And, therefore, even here, I should consider, the objections raised particularly by Prof. Ruthnaswamy, for whose erudition in constitutional law I have the greatest respect, do hot hold any water. On the contrary, we have said that we do abide by and respect the decisions and interpretations of the courts, whether it is a High Court or the Supreme Court, in view of the fact that we have acknowledged that we have made certain mistakes and through this provision we are'Trying to amend the Constitution and rectifying the mistakes.

Again, Prof. Ruthnaswamy said that we are attacking the very fundamental rights guaranteed to the citizens by the Constitution. Sir, this is a grave charge. I do realise that property is a very important right. Property is a great, social institution. Property confers personality to a man. Through the centuries, property has been conditioned, dominated, guided and controlled by countless human usages, traditions, customs, and laws evolved by various societies. And, therefore, while it is a fundamental right, there is no case made here whatsoever that it is being taken away at all. All that we are doing now is we are controlling it, we ar$_e$ guiding it in a different direction and we are making it go in a particular way to conform to the directive principles of the Constitution and, therefore, we are not taking it away. We might remember that there is the provision of compensation being paid at market rates for the land that might be taken away by this amendment. Therefore, the people who say that we have laid an axe upon the roots of our fundamental rights guaranteed in the Constitution are difficult for me to follow.

Sir, property in a social, and in a wider sense, is a cultural institution. Through the history of mankind property has not been taken as an isolated and abstract institution untouched by human needs and this we have sought to do based on certain compelling reasons, namely that we do want to achieve the greater objective, of better economic equality between the various sections of the population.

Lastly, Sir, the people have been saying that it is expropriatory. 1 could not follow Mr. Dahyabhai Patel when he said yesterday that this was a very serious matter and this might lead to something more serious. *I* fail to see in this amendment anything

. [Dr. S. Chandra Sekhar.] that threatens such a grave jeopardy of our way of life. In fact, the other way round, it is to promote -stability, to guarantee amenities and necessities to a very large segment of the population of our country that this amendment will be of help. By this amendment we are really guaranteeing a certain continuity, a stability *to the backbone of our population. We shall provide an incentive, we shall confer the pride of ownership, of owning the soil and contribute to the perennial problem of feeding the nation and producing more food from the land.

Whereas people have been contending that all the land legislations passed hitherto have not really contributed to the overall agricultural production of the country, I maintain that this amendment will enable the States to transfer land to the landless. It will be a major contributing factor in solving the perpetual problem of hunger in India and promoting more food production so that we may not go every year abroad with a beggar's bowl asking for more food.

Again, Sir, coming to Prof. Ruthna-swamy's speech yesterday, at the end of his speech he said that this is the thin end of the wedge, this is laying an axe at the very root of our free - way of life. I do not know what exactly he meant by this. He probably had" vague ideas as the Swatantra Party has been insisting in the press, outside this House as well as the Members who spoke in this House, that this amendment is thin end of the wedge. It would mean slowly co-operative farming and eventually collectivisation of land and the •dreaded Communist way of life engulfing this country and its 460 odd millions. If this were the contention or the fear implied in Mr. Ruthna-swamy's speech yesterday, I would like to say that if there is this possibility of an alien undesirable ideology engulfing the millions of this country, then it is exactly the reason why we ought to make our standards of social justice a little higher, a little better. In fact, we want this legislation to be interpreted in that way, in the sense that we are trying to prevent the red menace coming to this country. Therefore, instead of saying that this legislation is really attacking our free way of life, I should like to point out that this legislation will enable a very large segment, in fact the overwhelming majority of the people to possess some rights on the land, to enjoy the fruits thereof, to have an incentive in working it and to contribute to the stability and continuity of the traditions of our culture and economy. It is a pity that Professor Ruthna-swamy is not here because, I think, yesterday he took great pains to refer to this matter. Nothing will prevent, except this amendment, that kind of thing happening. I like to envisage that by such an amendment as this, we may fulfil our dream of a better life, a richer life, a happier life, a life of better economic equality and better distribution of the goods and services to every segment of the population, so that we may realise our avowed objectives by making this a greater, a more stable and happier country. Above and beyond this, through this amendment we may even ensure the possibility of ensuring peace in our countryside. If wars cannot be banished for ever, let us at least try and see that in our generation peace becomes a reality. Madam Deputy Chairman, it may seem that I am making a far-fetched claim for this, but if we look at it in its proper perspective, there is no reason whatsoever to think that our free Indian way of life is collapsing because we are passing this amendment to the Constitution. On the contrary, for the reasons just adduced, I think we will be achieving exactly the opposite, and therefore I have great pleasure in supporting this amendment to the Constitution.

श्री गोडे मुराहरि : मैडम डिप्टी चेयरमन, हमारे सामने यह जो संविधान में संशोधन करने का बिल आया है इस का

बुनियादी तौर से तो मैं समर्थन करूंगा लेकिन कुछ शंकायें उठती हैं, जिस के बारे में भी मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। अगर एक समाजवादी सरकार, अगर एक सरकार जो हिन्दुस्तान में एक समाजवादी समाज की व्यवस्था करती अगर ऐसी सरकार यह बिल लाती तो मेरे मन में इस तरह की शंका न उठती लेकिन जब ऐसी सरकार पूंजीवाद को कायम रखना चाहती है और जो अर्थ व्यवस्था में मिक्स्ड इकानामी चलाना चाहती है वह जब इस तरह के बिल लाती है तो कुछ शंकायें भी होती हैं और दाल में कुछ काला नजर आता है। और इस के लिये कुछ आधार भी है। मैं आप का ध्यान उन ऐक्टों की तरफ खींचना चाहूंगा जिन के अन्तर्गत कुछ किसानों को, जो छोटे किसान हैं, जिन के पास बड़ी जमीन नहीं है उन को अपनी जमीन को छोड़ना पड़ा इसलिये कि वहां पर कोई बड़ी फैक्टरी बसाई जा रही थी। उन को जमीनें इसलिये छोड़नी पड़ीं क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर बसाया जा रहा है। अभी आप को याद होगा, गाजियाबाद से कितने किसान यहां आए, दस दिन वे यहां पड़े रहे, उन के पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी। इस बिल के अन्तर्गत जो दूसरे ऐक्ट्स को संरक्षण दिया जा रहा है उन्हीं में से एक के जरिये उन को बेदखल किया गया और उन को कम्पेन्सेशन भी इतना कम दिया गया है कि कोई न्याय या कोई किसानों की भलाई के लिये यह चीज की जा रही है ऐसा नजर नहीं आता। जब इस तरह के ऐक्टों को इस में शामिल कर के यह सरकार इस ढंग की चीजें करती है, ऐसा बिल हमारे सामने लाती है तो फिर कुछ शंकायें पैदा हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद इस बिल का इस्तेमाल गलत ढंग से होगा। मैं इस बिल का इसलिये समर्थन करता हूं क्योंकि कोई भी समाजवादी ऐसा नहीं होगा जो निजी सम्पत्ति का संरक्षण करना चाहे--चाहे वह जमीन का हो चाहे और किसी चीज का हो। लेकिन हमारे मन में जो शंकायें उठती हैं उस से हम को लगता है कि शायद इस बिल का कोई गलत इस्तेमाल भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी ने यह तो नारा दिया है कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग लाने वाले हैं किन्तु अब तक कहीं कोआपरेटिव फार्मिंग इस देश में बनी नहीं है जब कि वह नारा लगाते कई साल हो गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि कहां तक इस संबंध में प्रगति हुई है।

वाजपेयी जी कहते हैं कि एक चोर दरवाजे से कोआपरेटिव फार्मिंग लाना चाहते हैं। मैं उन से इत्तिफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि वे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इस सरकार के जहन में कभी यह मन्शा नहीं है कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग करे। वह नहीं करना चाहते हैं। इस बिल को उस के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। मेरी तो यह निश्चित राय है कि यह बिल पास होने के बाद भी कोआपरेटिव फार्मिंग या किसी और चीज को करने में इस बिल का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बिल का इस्तेमाल वहां होगा जहां पर कल कारखाने बसाना चाहेंगे, जहां पर बड़े बड़े महानगर बसाना चाहेंगे, जहां बड़ी बड़ी फैक्टरियां बसाने के लिये किसानों को बेदखल करना चाहेंगे ऐसी जगहों में इस एक्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसलिये मेरी आशंका है और यही कारण है कि मुझे पूरे तौर से, पूरे दिल से इस का समर्थन करने में कुछ कठिनाई हो रही है। फिर भी मैं यह जरूर चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर किसान जो अपनी जमीन को जोतता है उसी किसान का उस पर अधिकार हो। मैं यह नहीं चाहता कि कोई आदमी जमीन रखे और शहर में बसा रहे और उस जमीन को जोतने वाले का कोई अधिकार उस जमीन पर न हो। इस बिल के अन्दर उस की कैसे पूर्ति होगी मेरी समझ में नहीं आता।

[श्री गोडे मुराहरि]

इस में एक प्राविजन है कि सीलिंग तक जो जमीन है उस में अगर इस बिल का इस्तेमाल किया गया तो फिर इस का उचित कम्पेन्सेशन दिया जायगा, मार्केट प्राइस पर कम्पेन्सेशन दिया जायेगा। यह मार्केट वैल्यू कौन तय करने वाले हैं ? मुझे मालूम है, जब गाजियाबाद का मामला सामने आया तो मार्केट वैल्यू तय करने में कई साल लगे, कई दिन बातचीत चली। एक हमारे डिप्टी मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर भी बहा गए इम्क्वायरी के लिये लेकिन जो तय हुआ वह मार्केट वैल्यू तो क्या वह तो सब-वैल्यू भी नहीं थी। जब छोटे किसानों का मामला होता है तो उस में इस ढंग की कार्यवाही होती है लेकिन जब बड़े बड़े जमींदार या और किसी की जमीन लेंगे तो फिर मुझे पूरा विश्वास है यह सरकार जब उस को कम्पेन्सेशन देना तय करेगी तो फिर मार्केट वैल्यू भी देगी या उस से कुछ और ज्यादा भी देगी। तो इसलिये एक शंका होती है कि यह सरकार हिन्दुस्तान में समाजवाद का नारा तो देती है लेकिन वह कायम रखना चाहती है उस व्यवस्था को जो आजकल है। कभी कभी यह शंका होती है कि स्टेट सरकार को इस तरह का अधिकार दिया जाय या नहीं।

लेकिन फिर भी इस बिल का इस्तेमाल जब होगा तो मैं चाहूंगा कि इन बातों के ऊपर ध्यान रखें और इस की कोशिश हो कि हिन्दुस्तान की जो जमीन है उस में एक "रीडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड" हो ताकि जो जोतने वाला है उस को जमीन के ऊपर अधिकार प्राप्त हो और मैं यह भी चाहूंगा कि जो भी आज कल सीलिंग के नाम पर जमीन का एक ऐक्ट बनाया गया है उस में जो बटवारा हुआ है उस के ऊपर सरकार की एक कमेटी बिठाई जाय और वह यह देखे कि कौन कौन से जमींदार के पास कहां कहां कितनी जमीन थी और उस जमींदार की जो सीलिंग से ज्यादा जमीन थी उस का क्या हुआ, यानी जो ऐक्ट्स स्टेट्स में पास हुए होंगे सीलिंग के एक्ट, उस के पांच साल पहले या दस साल पहले उस आदमी के पास कितनी जमीन रही है और पांच साल के अन्दर या दस साल के अन्दर उस ने उस जमीन का क्या किया है और किस ने उस जमीन का बटवारा किया है क्योंकि उस में यह पता लगेगा कि नजदीक के रिश्तेदार या नौकर चाकर जो हैं, जिन का उस जमीन में कोई मालिक नहीं, उन के नाम से जमीन का वितरण किया गया है या नहीं और इस ढंग से होगी वितरण के ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। और यह सारे मामले को देख कर जो बोने वाला है, जोतने वाला है, उस किसान को जमीन मिले तब तो इस का कुछ मतलब निकलता है कि इस बिल का इस्तेमाल सही ढंग से होने जा रहा है। वैसी जो जमीन होगी उस को सरकार ले ले और फिर उसका पुनः वितरण करे।

•

और मैं यह भी चाहूंगा कि इस दौरान में इस बिल का इंतजाम इस गलत ढंग से न हो कि हमारे देश की जमीन का जो मामला है वह जैसे का तैसा रह जाय। अगर आप जमीन का कोई पुनः वितरण करना चाहते हैं और आप का एक लैंड रिफार्म्स बिल लाने का उद्देश्य है तो फिर मैं यह चाहूंगा कि उस सारे लैंड रिफार्म्स का स्वरूप भी हमारे सामने आए और हमें मालूम हो कि सरकार इस बारे में क्या करने वाली है।

अब तक सारे स्टेट्स में जो बिल पास हो चुके हैं उन सब को इस ऐक्ट में जोड़ा जा रहा है और संविधान के अन्तर्गत उन को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं तो यह चाहता हूं कि जिस तरह से इस समय संविधान में संशोधन हुआ है उसी तरह से जो जमीन की व्यवस्था है उस के लिये भी एक नये वितरण की व्यवस्था की जाती और एक नई दिशा उस को दी जाती। जिस चीज के

लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है उसका हार्दिक समर्थन करने में मुझे कठिनाई अनुभव होती है और मैं उस का पूरा पूरा समर्थन नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मैंने १७ सालों से देख लिया है कि यह सरकार छोटे किसानों की भलाई करना नहीं चाहती। वह तो केवल बाहरी दिखलाव के लिए इस तरह का बिल लाई है और इसके लिये दलील देती है कि हम किसानों की भलाई के लिए यह बिल लाये हैं। अगर वह सच मुच किसानों की भलाई चाहती है तो उस के लिए वह दूसरा बिल लाये जिस से उन को सच्चे मायनों में फायदा पहुंचे।

SHRI BABUBHAI M. CHINAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, the Constitution (Seventeenth Amendment) Bill is now before us and this special session of Parliament has been called for this purpose. This measure has already been adopted by the Lok Sabha. The present session of the two Houses has acquired a poignancy due to the departure of our great and beloved leader Shri Jawaharlal Nehru. His interest in the proposed amendment is very well known, and the acceptance of this amendment would be a humble tribute and a due homage to the spirit of Shri Jawaharlal Nehru who had ever fought for reform and democratic change. He also wanted us to understand the implications of a Bill of this kind and its relations with other things. It is in this light that I wish to present my observations.

The Bill seeks to amend article 31A of the Constitution. It will be recalled that article 31A was introduced by the first amendment to the Constitution, in 1951. Article 31A states that no court of law can go into the question whether a Fundamental Right was being offended, so long it is said that it is being taken away in any other form than landed property. And estate was defined as including *jagir, inam, muafi* or other similar land. In other words, it took away the protection against the taking away of samindari. The proposed amendment to the Constitution says that the rights acquired by the intermediary in respect of land were also nonjusticiable. The present proposal is further to amend the definition of "estate" in article 31A of the Constitution to include land right under ryotwari settlement and also other lands in respect of which provisions are normally made in land reforms enacted, and also to include all land let for purposes of agriculture and for purposes ancillary thereto, including waste land, forest land, pasture land, sites for buildings and other structures occupied by cultivators and agricultural labourers, village artisans and so on.

The provocation for the present Bill is the Kerala Agrarian Relations Act of 1961. This Act was struck down by the Supreme Court in its application to ryotwari land transferred from the State of Madras to Kerala. The Act was further struck down by the High Court of Kerala in its application to land and estates in Malabar and Travancore. It was held that the Act violated articles 14, 19 and 31 of the Constitution and that the protection of article 31 of the Constitution was not available to these lands as they were not "estates".

Sir, the Indian peasant is the bulwark of the State, and any amendment of any law that gives power to the Government to take away the self-employed character of the Indian peasant has to be weighed cautiously. In our country, as much as 52 per cent, of the people own some land and, therefore, this amendment is of a very far-reaching nature. Further, this Bill will deprive the peasants of a Fundamental Right to go to a court of law in regard to any dispute relating to compensation paid by the Government. It is also necessary to note that this will have retrospective effect from the 26th January, 1950; As I said earlier, I support this amendment because I am confident that the Government as it is constituted today and which is inspired by the ideals of Shri Jawaharlal Nehru, will not do anything to injure the

[Shri Babubhai M. Chinai.] Fundamental Rights of the individual. Thank you.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I rise to give my qualified and limited support to the Constitution (Seventeenth Amendment) Bill. I shall extend my support to clauses 1 and 2 of the Bill and not to clause 3 of the Bill.

Much has been said in this House by the previous speakers about the need for gradual progress of the country towards the socialistic goal. But qualified observers of the agricultural scene are of the opinion that intermediaries who send up the cost of living and the cost of production should be eliminated. Also, as a result of the States reorganisation, a new situation has been created calling for a definition of the term "estate".

Sir, what I would like to submit to the House is that in enacting legislation of this character, the Government must bear in mind the Fundamental Rights of the citizen. There is a good deal of feeling On account of the fact that Dr. AmBedkar gave an assurance in the Constituent Assembly that ryotwari settlement would not be interfered with and...

THE MINISTER OF LAW (SHRI A. K. SEN) ; That is not the case, Sir. What he said was that the right of possession would not be disturbed, of the ryotwari tenant. That is quite a different thing to saying that ryotwari settlement would not be affected.

SHRI A. D. MANI: What he said was that the rights of the ryotwari settlement would not be interfered with, and if they were interfered with, the President would withhold his consent to a Bill seeking to withdraw those rights. In any case, the impression was created in the public mind that the ryotwari settlement would not be interfered with. Then sixteen years after thai, ussurance was given on the floor of the Constituent Assembly, this Constitution (Amendment) Bill has been brought in for discussion.

The second point I would like to make is that the Government as in other matters is dealing with the question of land in a half-hearted and piecemeal manner. The Government of India has no control over the agricultural policies of the States and a good deal of evidence has been laid before this Joint Select Committee to show that the tendency of legislation, of land reform legislation has been of a capricious character. In Gujarat, the Tenany Act has been amended as many as eighteen times. In view of the fact that the Government of India has no control over land legislation, I wonder whether it is appropriate for the Government to give their support to States which are experimenting in a very rash manner in regard to ownership of land.

Sir, I would like to point out further that land reform legislation cannot succeed unless the ancillary apparatus for such land reform is brought into existence. Land reform-can succeed if there is a slfong cooperative movement in the country. But unfortunately, except in the State of Maharashtra where the co-operative movement is flourishing and where the co-operators have shown that one acre can raise 100 tons of sugarcane, except in areas of that kind, the'co-operative movement has not been a conspicuous success. Further, the States have not been wholeheartedly implementing the land reform legislation. I am making all these submissions to show that the Government of India must come to some clear conclusion about the future of land reform in this country. Since so many States were experimenting in land legislation, I would like to submit to Government that the time has come for the establishing of a full-fledged land reform com-

mission which will go into all the questions of land reform and which ■will be some sort of a supervisory and consultative authority whom the States could consult with regard to the implementation of land reforms.

Sir, I would like to point out further that there is a feeling—and it is a justifiable feeling—on the part of cultivators that while the Government is trying to seek to fix a ceiling •*em* land, there is *no* attempt to fix a ceiling on other forms of property. With regard to ceiling on incomes, the Government of India has turned down the suggestion that has been made by the so-called left-wing forces in the country that there should be a ceiling on incomes. If we are going to fix a ceiling on land, it must take into account the fact that the price level has risen very high since 1949 and that any ceiling which is fixed must take into account the prices prevailing in the present time. It may seem a very incongruous argument but I may put it this way, that the ceiling should foe linked up with the price level like the dearness allowance because, as the price level goes up, the ceiling will have to go up in order to enable a cultivator to maintain himself. (Interruption). I am only making this point. This only shows that it has got to be flexible legislation. I am only pointing out the incongruity of the policy of fixing a ceiling particularly when the prices are rising. If a ceiling is fixed, if you say that each cultivator should get five hundred rupees or six hundred rupees, then if the price level increases, you should provide for an increase in the ceiling which means that the ceiling . . .

(Interruption)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHAHCAVA): One at a time, please.

SHRI M. M. DHARIA (Maharash--tra): The protection to the cultivator should be given by fixing a minimum price for his produce and not by . . . 338 RSD—3.

SHRI A. D. MANI: But the Government of India is not able to control the price level. We do not have the economic apparatus for controlling the price level, for giving a stable and remunerative price to the grower. As I said, the whole thing has been done in a'haphazard 'and piecemeal manner. If the price level increases, the ceiling has to increase to this class for, as I said earlier, the Planning Commission has got so much work put *on* its shoulder that it may not be possible for the Planning Commission to exercise continuous supervision over land reform legislation in our country. If a land reforms commission i_s there, that will go into all these questions and make suggestions for fixing stable prices for the grower.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): Just a minute, Mr. Mani. Mr. Narayan Patra wanted a clarification.

SHRI N. PATRA (Orissa): No linking will be necessary because if prices increase, equally the prices of foodstuffs will also increase. Therefore, the point that a ceiling and prices should go together does not arise in this case.

SHRI A. D. MANI: Unfortunately, the economic situation is not a geometrical proposition in this country. We are not in a position to say what exactly would rise. If a land reforms commission is there, it will go into all these matters. It is not impossible to have a flexible ceiling because you can make an enabling provision in all these land reform Acts enabling the Government to fix a ceiling by notification. This is done where the situation is of a very fluid character.

SHRI M. M. DHARIA: It is not my intention to disturb Mr. Mani, but the point is not clear. If the linking is there and if the ceiling is to be raised due to increase in the price level, from where is the land required to be got? The moment ceiling is

[Shri M. M. Dharia.] fixed, tike surplus land is distributed. From where is the land to be had for increasing the~ceiling? I have not so far followed this point and that is why I am disturbing Mr. Mani.

SHRI A. D. MANI: We are not thinking in terms of production; we are thinking In terms of production also which' is Important, as important as the equitable distribution of land to the landless labour. This calls for a very close study of what is an economic holding which may differ from State to State, from area to area. If you are going to fix, as has been fixed in some States, 12J acres as the ceiling, this may not enable a person to make a decent living. There should be, as I said, in the land reform legislation some sort of flexibility to meet the requirements of the present situation, the price situation.

Sir, I am taking more than ten minutes but I would like to deal with my opposition to clause 3 of the Bill. Sir, the Joint Select Committee must have gone in great detail into the provisions of the various Acts which have been listed in the Schedule. But I am totally opposed to the Parliament giving ratification to Acts which have been struck down by courts of law. It is wrong in principle, it does not promote respect for the judiciary and, in fact, I am not sure whether care has been taken by the State Governments to see that the land reform legislations that they have enacted conform to the requirements of the situation. The Communis? Government in Kerala gave some concessions and privileges to the cultivators and they were withdrawn by the Congress Government and that Act is now to be validated.

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): Will you please" tell us how it was withdrawn and what were the privileges given to fffe kisans there?

SHRI A. D. MANI: I am not able to go into more detail but some of the provisions of the old Act do not find a place in the new Act and this is now to be validated. What I am suggesting is that where States pass legislation of this character in a great hurry, I am not here to give my support to any change in the Constitution giving validation to such Acts just because some State has done it. If a State wants to enact land reform legislation, it should in the first instance conduct a public economic enquiry about what is an economic holding in that area and take evidence from the persons affected and then only come to some conclusions about it.

SHRI JOSEPH MATHEN; You have not replied to my point.

SHRI A D. MANI: I am not fully conversant with it but I am told and this was mentioned .

SHRI JOSEPH MATHEN: Then kindly do not make such statements.

SHRI A. D. MANI: But the Act passed by the Congress Government is not the same Act as was passed by the Congress Government. That is accepted.

SHRI JOSEPH MATHEN: It is not.

SHRI A. D. MANI: It is not. I am only saying that one Cabinet passed a certain legislation with the help of the legislature; another Cabinet which comes into existence after a few ' months passes another legislation and we in Delhi are not conversant with all the local conditions and we ~an-not, thereore, give our consent to the validation of these Acts by an amendment to the article of the Constitution. It is wrong in principle to validate Acts which have been challenged in courts of law. 'I know that this will lead to some delay in land reforms but land reforms if they are to succeed, Mr. Vice-Chairman, should have some ancillary apparatus which is absent and what I am afraid is that by passing this Constitution (Amendment) Bill and enabling the State Governments to so ahead with land

reform legislations, we are going to create chaos in the agricultural held in the country. In 1976, it is estimated that the country will have to produce as much as 117 million tons of foodgrains to sustain the growing population and we are not in a position even to be self-sufficient by the end of the Third Plan. In view of this, Sir, I would like to say that while I do not like to stand in the way of Government trying to go ahead with land reform legislation— and therefore I accord my support to clause 2 of the Bill—I am totally opposed to clause 3 of the Bill. The State Legislatures must deal with their problems themselves with the knowledge of the local requirements and must not pass hasty legislations which are challenged in courts of law.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I rise to give my support to this Bill. I think that there is no force m the arguments that we should not proceed with this Bill as we have only a caretaker Government and we must not have any controversial legislation at this time. The present Session was called especially for the consideration of this Bill. This has to be remembered by us. It was contemplated that the present Session would consider this Bill.

The second argument which was raised by Mr7 Ruthnaswamy was that this Bill is violative of certain Fundamental Rights and that we should not change the Fundamental Rights so easily. I quite agree that Fundamental Rights should not be changed in a light-hearted spirit but may I point out to him with all respect that the Constitution-makers did not look upon these Fundamental Rights as the Law of Medes and Persians. They did not look upon them as rights which cannot be changed under any circumstances; they did not look upon them as inalienable rights. If you look at the provisions of the Constitution, you will find that the Fundamental Rights can be changed with a process which is easier than for certain other rights on which one might say the allegiance of the States to the Union Government depends. For changing any Fundamental Right you need only a two-thirds majority of both Houses of Parliament but for changing certain other parts of the Constitution you need not only a two-thirds majority of each House of Parliament but also the concurrence of at least eight States. Therefore it was not thought by the framers of the Constitution that in a changing world, in a dynamic world, the Fundamental Rights would remain like the Law of Medes and Persians. I think, therefore, that, there is no force in the the argument that we should not enact this measure because it runs counter to some of the Fundamental Riahts enumerated or enunciated in the Constitution.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras): Then what is the meaning of 'fundamental' in "Fundamental Rights'; fundamental for the time being or for a few years?

SHRI P. N. SAPRU: Yes, fundamental does not mean immutable. If the idea of the framers was that Fundamental Rights should not [J]be changed, why did they provide any machinery for changing those rights? Why was not the machinery for hanging these Rights made more difficult than the machinery for changing other parts of the Constitution? I think there is a misconception.

SHRI M. RUTHNASWAMY: Probably the framers of the Constitution thought that when they called these Fundamental Rights, they would be considered as fundamental for all time as long as we are committed to the free way of life.

SHRI P. N. SAPRU: I say that the framers of the Constitution must have anticipated that there would arise occasions when it would become necessary to change these Fundamental Rights and they did not want

[Shri P. N. Sapru.] to enact something which would impede progress in the future. I am not therefore at all impressed with the argument that this is violative of the Fundamental Rights.

Then he said that this Bill is intended to apply to ryotwari estates and that there is something sacrosanct about the ryotwari system and Sir John Metcalfe did a very grand piece of work by giving to the people of Madras and the South this ryotwari system. I think there is no force in that argument. In the modern world, there can be no absolute right to property. Let us be quite clear about it. We must not stress the rights to property to the extent that those rights deny social justice. Where the rights to property come into '.■onflict with our notions of social justice, they hust go and, therefore, I do not look upon the right to property in the same manner as I look upon certain other rights. For example, I consider the right of free expression of opinion, the right of free association, etc. are far more fundamental than the riKht to property. It used to be said that property develops personality. I do not know whether it develops personality or whether it hampers the development of personality. I am therefore not impressed by arguments of that character.

Then, it has been argued that this Bill seeks to reverse some decisions of the Supreme Court and the High Courts. Now, I have the highest regard for the Supreme Court and our High Courts. The Supreme Court is the interpreter of the laws of the land and it is entitled to the highest respect from us all; but it is not for the Judges to tell us what the policy in regard to a particular piece of legislation should be or what the particular political programme of a party should be. The Judges nave the right to interpret the Constitution and they have interpreted the Constitution. We have accepted that interpretation but we find, that that interpretation interferes with the performance of the task of social justice which is, from our point of view, the most important task in the interest of the community. Therefore we are showing no disrespect to the Supreme-Court, we are showing no disrespect to the High Courts, by seeking to change the law.

Mr. Vice-Chairman, I will take only one or two minutes more. May I say that this question of land distribution is a very big task. We have hundreds of thousands of landless labourers and there are a few people who own much more land than they can manage. We want to have a more equitable distribution of land so that the ordinary man, the man who has no land, may have some land. We want to build our society on the foundations of social justice; we want to build an ethical society in this country and it is for that reason that I feel that this Bill is in accordance with those principles of justice, equity and ethics which must inspire a community which wants to take the rightful place in the comity of nations. I give it my full support.

شری عبدالغنی (پنجاب) : وائس
چیر میں سر - کچھ عرصے ہوا کہ لوک
سبھا میں یہی بل آیا تھا اور جیسا کہ
یہاں اس ہاوس میں پتہ چلا نہ صرف
کانگریس کے ممبر صاحبان نے بلکہ
دوسرے آزاد ممبروں نے بھی اور
اپوزیشن خیال کے ممبروں نے اس بل
کی حمایت کی اس کے باوجود وہ
وہاں پاس نہ ہو سکا اور کانگریس
سرکار نے اس میں ہیٹی سمجھی
اور وہ بہت جلد اس بل کو لائی -
کیوں لائی - کوئی معشوق ہے اس
پردہ زنگاری میں- اس میں جوڈیشری
کی اگزیکیٹو پر شاندار فتح واضح ہوئی ہے
اور دوسری طرف پالیسی کا جو قنڈا ہے
اس کی جوڈیشری پر فتح ظاہر ہوتی ہے -

انگریز کے راج میں اگر کوئی خرابی ہو تو میں سمجھ سکتا تھا کہ ودیشی راج ہے، وہ ہم لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہتا ہے اور اس لئے کسان کی حالت کو وہ بری رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھرتی ہو سکے - لیکن اپنے راج میں بڑی بڑی تعمیریں ہوئیں، چار ہو جائیں - چلیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ دو غلہ منگاتے ہیں باہر سے، اس میں کتنی کمی ہوئی - میں آپ کے انکڑوں کی فکر نہیں کرتا - آپ آنکڑوں میں دکھائیں گے کہیں ڈبل ہو گیا، کہیں ڈبل سے ٹریبل ہو گیا، لیکن جب تک آپ باہر سے غلہ منگانے پر مجبور ہیں اور اس میں کمی نہیں ہوتی تو میں کیا سمجھوں - میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جتنے بچے بڑھ گئے، پیداوار بڑھ گئی جتنی آبادی بڑھ گئی، اس کو آپ نے کیا قابو کرنے کی کوشش کی - لیکن جب بھی میں سوال کرتا ہوں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے - میں نے پوچھا کہ پنجاب میں کتنا مال—وہ ویسے بتاتے نہیں - فیگرس دیتے ہیں - آنکڑے دے دیتے ہیں—میں نے پوچھا کتنا باہر بھیجا گیا ریل کے ذریعہ اور کتنے کو ریل کے ذریعہ باہر دوسرے ملکوں سے یا دوسری اسٹیٹوں سے پنجاب میں لایا گیا تو اس میں راز کھلا کہ جو آمد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے - جو باہر سے مال آیا، فوڈ گورنمنٹس، وہ بہت زیادہ ہے اور جو

یہ بل لایا گیا ہے اس لئے کہ سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹس نے ان کی اس پالیسی کو جو یہ لینڈ ریفارم کی پالیسی کہتے ہیں اس کے راستہ میں ان کا فیصلہ کچھ حائل ہوا - ان کا کہنا یہ ہے کہ کسان کا بھلا اس میں ہے کہ یہ بل جو ہم پاس کرنے جا رہے ہیں - یا پاس کر چکے ہیں اس کو کامیاب بنایا جائے اور عدالت کی رکاوٹیں اس پر حائل نہ ہوں - کل ہمارے تھیا بھائی پٹول جی نے یہ کہا کہ ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ۴۵ پرسینٹ کے نمائندے ہیں - تو میں نے ہنس کر کہا تھا ۲۵ پرسینٹ سے بھی کم - کیوں کہ وہ ۲۵ پرسینٹ ہے ۵۵ پرسینٹ کا - ان کے ۱۰۰ پرسینٹ کا - تو یہ بل لائے ہیں کسان کے نام پر اگر واقعی کسان کو، وائس چیرمین صاحب، اس کے ذریعہ فائدہ ہو تو میں سپورٹ خوشی سے کرتا - گاندھی وادی ہونے کے ناتے سے میں اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا کہ کسی حالت میں بھی جوڈیشری کا دروازہ کسی بہانہ سے کسی حد تک بند کیا جائے - یہ گاندھی وادیوں کو، گاندھی جی کا [illegible] لینے والوں کو، سمجھتا نہیں ہے - پھر حال وہ کسان کا نام لیتے ہیں - انہیں ۱۷ برس میں دیکھیں کہ ہم اکتنے اربوں روپیہ ڈگرو مور فوڈ، کے نام پر سینٹر سے ایڈ میں دے چکے - یا اسٹیٹس نے دگرو مور فوڈ کے نام پر خرچ کیا ہے، - پہلے

حکومت ہے، کانگریس کے بھائیوں سے، کہ کارٹلنگ پر سیلنگ لاگو نہیں ہوگی - اس میں کرتے کیا ہیں - جیسا یہ کرتے ہیں، اتنے ہزار اتنے کروڑ درخت لگائے گئے - اس میں چند پودے لگا کر مالٹا کے، سنترہ کے، امرود کے یا اور کسی پھل کے - اس کو کارٹلنگ کا نام دے کر سیلنگ سے الگ کر دیتے ہو - کتنی لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جو آپ نے اپنے نام کی ایک نوک سے، اپنے جو چہیتے تھے جن کو سمجھایا کہ راتوں رات باغ بنالو اور وہ کھیتوں کے باغ بن گئے اور اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں کہ آپ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، کسان کے لئے کہ کسان کو ہمیں کو زمین دینی ہے - اور زمین کو کھینچتے کھینچتے ہو - بڑے بڑے فارم کہلاتے ہیں جن کو بناؤ ان کو ہم دستبرد نہیں کریں گے - وہ فارم کن کے ہیں، کیسے فارم بن گئے - کسان کا کیسے فارم نہیں بن سکتا - جو چھوٹا جاگیر دار ہے - اگر آپ کا مقصد یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کل کفیل صاحب نے فرمایا کہ جاپان میں مگرتھر نے جب کہا کہ اتنی زمین تھوڑی تھوڑی ایکڑ کر دو، چھ ایکڑ سے بھی کم - دو تین ایکڑ کر دو - تو پھر پانچ ایکڑ والے تو ۵۶ فی صدی پہلے ہی سے تھے پھر آپ کو کیا پریشانی ہوئی - اس کے معنی یہ ہیں آپ زمین میں پیداوار کو بڑھا نہیں

[شری عبدالغنی]

گیا وہ اس سے کم ہے - تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ نام تو کسان کا لیتے ہیں کہ کسان کا بھلا اس میں ہے تو اس میں تو پیداوار بڑھنی چاہئے - اصل بات یہ ہے کہ جتنی اسٹیٹوں نے قانون پاس کئے، وہ پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو درجنوں پاس ہوئے - پنجاب میں، اور باقی اسٹیٹوں کے بارے میں وہاں کے بھائی خود جانتے ہوں گے - وہ اس افراتفری میں کیا جاتا ہے یا اس نیت سے کیا جاتا ہے - میں نے کل بڑا وچار کیا، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران کی لسٹ میں نے اپنے سامنے رکھی اور مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے زمین دار جو ہیں کانگریس کے حصہ میں تو ۷۰ فی صدی زمین کانگریس والے قبضہ کئے ہوئے ہیں اور جب میں نے ان کی طرف توجہ کی جو اپنے آپ کو سوتنتر کہتے ہیں اور اس بل کی مخالفت کرتے ہیں ان کے حصہ میں تو ۵ فی صدی آتا ہے - تو میں سمجھا یہ ۵ فی صدی والے کیوں شور مچاتے ہیں - ان پر تو لاگو ہوتا نہیں - تو مجھی سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ آپ قانون بناتے ہو - سیلنگ کرتے ہو لیکن سیلنگ کرتے وقت آپ قانون میں کیسی موشو گافیاں کرتے ہو - کیسی ہوشیاری سے تم راستہ نکالتے ہو - میرا مطلب ہے خداوندان حکومت سے کہ جن کے ہاتھ میں

پائے - اگر بوڑھا پاتے تو جاپان میں اگر دو یا تین ایکڑ یا جو ہے وہ بھی اپنی فیملی کا اپنے بچوں کا پورا انتظام کر سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہندوستان میں بھی وہ بات نہیں ہو پائی کیوں کہ آپ نے ارب ہا روپیہ اس کے لئے خرچ کیا - تو کوئی نہ کوئی کمی ہے کہ جس کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ یہ پناہ لے رہے ہیں - یہ سترھویں امینڈمینٹ کی -

آپ کو بڑا غصہ آیا جب ڈھیبا بھائی جی نے اس کو امورل کہا - آپ کو غصہ آیا لیکن میں کہتا ہوں عقل کا دیوالہ ضرور ہے - اگر یہ اخلاق کا دیوالہ نہیں ہے تو عقل کا دیوالہ ضرور ہے جو آپ نے نکالا ہے - کیوں نکالا ہے - ؟ کیوں ضرورت پڑی آپ کو ایسا ایمنڈمینٹ لانے کی - میں ڈھیبا بھائی جی سے اتفاق رکھتا ہوں کہ کوئی خدائی خوبی نہیں ہے جو ہمارا کنسٹی ٹیوشن ہے اس میں کوئی امنڈمینٹ ہو ہی نہیں سکتا - لیکن ایمنڈمینٹ کرنا اس لئے ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو - میرا دعوی ہے کہ دنیا کے بہترین جو ودھان ہیں ، ہندوستان کا ودھان ، ان میں بڑی شاندار جگہ پر ہے - اس میں کمی کیا ہے - ترٹیاں کیا ہیں - ترٹیاں اس طرح سے پوری کی جائیں کہ یہ جو بڑی بڑی

سیاہ لنک ہو رہی ہے ان کے دعوی جائیں گے - یہ وہی دعوی جائیں گے جو مرارجی جی نے کہا - مرارجی جی اور ہمارے پروفیسر مکٹ بہاری لال جی باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی نیت بخیر نہیں - وہ جانتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے ، جو پیش ہوا ہے اور جس کا پوتھا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے وہ نکما ہے ، وہ بوسیدہ ہے ، ان قانون میں بڑی ترٹیاں ہیں ، ان میں بڑی کمیاں ہیں ، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی تائید کرتے ہیں - کاہے کی تائید کرتے ہیں ، آج آپ دنیا کے سامنے یہ دیکھ کر جا رہے ہیں کہ کسی حد تک عدالتوں کا دروازہ کسی صورت میں آپ بند کرنا چاہتے ہیں - پنجابی میں کہتے ہیں سپ کو نہیں جاندا پیہہ کو جاندا ہوں - ، میں اس جانور کی طرف نہیں دیکھ رہا جس کا آج آپ شکار کر رہے ہیں بلکہ اس راستہ کو دیکھ رہا ہوں جس راستہ سے آپ شکار کرنے جا رہے ہیں - جیسے انگریز جب جا رہے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی پناہ لی ، جب اس سے کام نہیں چلا تو انہوں نے اچھوت بھائیوں کی پناہ لی ، جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو راجاؤں اور نوابوں کی پناہ لی - اب آپ بھی اپنی مہاجنی کے بل پر ایسا

[شری عبدالغنی]

اسٹیبلشمینٹ لا رہے ہیں کہ جو راستہ ہم کو دکھا رہے کہ کل جب ہم جائیں گے ، جو کچھ کہیں گے ، ہم کرینگے ، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ آنے والے الیکشن میں جیتنے والے نہیں ہیں - آپ کی ہار ہونے والی ہے - اس لئے آپ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں - خدا کا شکر ہے ، میں خوش ہوں کہ میرا ملک کافی حد تک شاستری جی کے آنے سے بن جائے گا لیکن وہ پاکستان نہ بنیں ، خروشچوف پیچھے بیٹھا ہے - ان کو ہوشیار رہنا چاہئے -

میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ جس راستہ پر جا رہے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر کسان کا بھلا ہو لیکن کسان کے بھلے کے نام پر آپ اپنا بھلا سوچیں ، آپ اپنی گدی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ، [میں اس کی ندا کرتا ہوں ، اور ڈھیا بھائی جی کے ان الفاظ کی تائید کرتا ہوں کہ آپ کے اخلاق کا دیوالہ نکل رہا ہے -

(Time bell rings.)

کیوں کہ مجھے حکم ہوا ہے اور میں ہمیشہ پابند رہتا ہوں اس لئے میں اپنے خیالات کا پھر کسی موقعہ پر اظہار کرنے کی کوشش کرونگا - حالیہ کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ورنہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ -

جس کھیت سے دہقاں کو
میسر نہ ہو روزی

اس کھیت کے ہر خوشہ
گندم کو جلا دو

میں مانتا ہوں لیکن اس پردہ میں ہزاروں ایکڑوں پر باغات کے نام پر ، فارموں کے نام پر ، کوآپریٹیو کے نام پر سوسائٹی آپ نے کھڑی کی اور اس میں ہزاروں ایکڑ لے لیئے ، کسانوں کے چھین لیئے ، اس طرح سے جو قانون آپ نے بنایا ہے آپ اپنے ساتھ بھی انیائے کرتے ہیں ، جنتا کے ساتھ بھی انیائے کرتے ہیں اور صرف اپنی اکثریت کے بل پر ایسا بل پاس کرنا چاہتے ہیں - میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں -

†[श्री अब्दुल ग़नी (पंजाब) : वाइस चेयरमैन, सर कुछ अरसा हुआ कि लोक सभा में यही बिल आया था और जैसा कि यहां इस हाउस में पता चला न सिर्फ कांग्रेस के मैम्बर साहबान ने बल्कि दूसरे आजाद मेम्बरों ने भी और लेफ्टिस्ट ख्याल के मेम्बरों ने भी इस बिल की हिमायत की। इस के बावजूद वह वहां पास न हो सका और कांग्रेस सरकार ने इस में हेठी समझी और वह बहुत जल्द इस बिल को लायी। क्यों लायी। कोई माशूक है इस पर्दाए जंगरी में। इस में जुडीशियरी की ऐक्जीक्यूटिव पर शानदार फतह वाजय होती है और दूसरी तरफ पालिसी का जो डंडा है उस की जुडिशियरी पर फतह जाहिर होती है।

■j-[ ] Hindi transliteration

यह बिल लाया गया है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्टस् ने उन की इस पालिसी को, जो यह लैंड रिफार्म की पालिसी कहते हैं, इस के रास्ते में उनका फैसला कुछ हायल हुआ। उन का कहना यह है कि किसान का भला इस में है कि यह बिल जो हम पास करने जा रहे हैं या पास कर चुके हैं उस को कामयाब बनाया जाय और अदालत की रुकावटें इस पर हायल न हों। कल हमारे डाह्याभाई पटेल जी ने यह कहा कि उन को याद रखना चाहिये कि यह ४५ परसेन्ट के नुमाइन्दे हैं। तो मैं ने हंस कर यह कहा था २५ परसेन्ट से भी कम। क्योंकि वह २५ परसेन्ट है ५५ परसेन्ट का। उन के १०० परसेन्ट का। तो यह बिल लाए हैं। किसान के नाम पर। अगर वाकई किसान को, वाइस चेयरमैन साहब, इस के जरिए फायदा हो तो मैं सपोर्ट खुशी से करता। गांधीवादी होने के नाते से मैं इस बात को कतई पसन्द नहीं करता कि किसी हालत में भी जुडीशियरी का दरवाजा किसी बहाने से किसी हद तक बन्द किया जाय। यह गांधीवादियों को, गांधीजी के नाम लेने वालों को, सजता नहीं है। बहरहाल वह किसान का नाम लेते हैं। आइए १७ बरस में देखें कि हम कितने अरबों रुपया 'ग्रो मोर फुड' के नाम पर सेन्टर से एड में दे चुके या स्टेट्स ने 'ग्रो मोर फुड' के नाम पर खर्च किया है। पहले अंग्रेज के राज में अगर कोई खराबी हो तो मैं समझ सकता था कि विदेशी राज है। वह हम लोगों को फौज में भरती करना चाहता है और इसलिए किसान की हालत को वह बुरी रखना चाहता है ताकि वह भरती हो सके। लेकिन अपने राज में बड़ी बड़ी तामीरें हुईं। चार योजनायें चलीं। आप बता सकते हैं कि वह जो गल्ला मंगाते हैं बाहर से उस में कितनी कमी हुई। मैं आप के आंकड़ों की फिक्र नहीं करता। आप आंकड़ों में दिखायेंगे कि कहीं डबल हो गया, कहीं डबल से ट्रिपल हो गया लेकिन जब तक आप बाहर से गल्ला मंगाने पर मजबूर हैं और उस में कमी नहीं होती तो मैं क्या समझूं। मैं यह समझ सकता हूं कि जितने बच्चे बढ़ गये हैं पैदाइश बढ़ गयी, कितनी आबादी बढ़ गई उस को आप ने क्या काबू करने की कोशिश की। लेकिन जब भी मैं सवाल करता हूं कुछ समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे यह पता चलता है। मैं ने पूछा कि पंजाब में कितना माल—वह वैसे बताते नहीं, फिगर्स देते हैं, आंकड़े दे देते हैं— मैं ने पूछा कितना बाहर भेजा गया रेल के जरिये से और कितने को रेल के जरिये बाहर दूसरे मुल्कों से या दूसरी स्टेटों से पंजाब में लाया गया तो उस में राज खुला कि दरामद जो है वह बहुत ज्यादा है। जो बाहर से माल आया, फूडग्रेन्स, वह बहुत ज्यादा है और जो गया वह उस से बहुत कम है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर आप नाम तो किसान का लेते हैं कि किसान का भला इस में है तो इस में तो पैदावार बढ़नी चाहिय। असल बात यह है कि जितनी स्टेटों ने कानून पास किए हैं वह पता नहीं, हमारे यहां तो दर्जनों पास हुए, पंजाब में, और बाकी स्टेटों के बारे में वहां के भाई खुद जानते होंगे। वह इस अफरा-तफरी में किया जाता है या इस नीयत से किया जाता है—मैं ने कल बड़ा विचार किया, लोक-सभा और राज्य सभा के मेम्बरान की लिस्ट मैं ने अपने सामने रक्खी और मुझे अन्दाजा यह हुआ कि बड़े बड़े जमींदार जो हैं कांग्रेस के हिस्से में तो ७५ फी सदी जमीन कांग्रेस वाले कब्जा किए हुए हैं। और जब मैं ने उन की तरफ तवज्जोह की जो अपने आप को स्वतन्त्र कहते हैं और इस बिल की मुखालिफत करते हैं उन के हिस्से में तो पांच फी सदी आता है। तो मैं समझा यह ५ फी सदी वाले क्यों शोर मचाते हैं उन पर तो लागू होता नहीं। तो मेरी समझ में जो बात आई वह यह है कि आप कानून बनाते हों, सीलिंग करते हों लेकिन सीलिंग करते वक्त आप कानून में कैसी मुशगाफिया करते हों। कैसी होशियारी से तुम रास्ता निकालते हो। मेरा मतलब है

[श्री अब्दुल ग़नी]

खुदावन्दाने हुकूमत से कि जिन के हाथ में हुकूमत है, कांग्रेस के भाइयों से कि गार्डिनिंग पर सीलिंग लागू नहीं होगी। उस में करते क्या हैं ? जैसा ये करते हैं, इतने हजार, इतने करोड़ दरख्त लगाए गये । उस में चन्द पौधे लगाकर माल्टे के, सन्तरे के, अमरूद के या और किसी फल के, उस को गार्डनिंग का नाम दे कर सीलिंग से अलग कर देते हो। कितनी लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो आप ने अपनी कलम की एक नोक से, अपने जो चहेते थे, जिन को समझाया कि रातों रात बाग बना लो और वह खेतों के बाग बन गए । और उस में कोई पूछने वाला नहीं है । क्योंकि आप मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, किसान के लिए कि किसान को हमीं को जमीन देनी है । और जमीन को खेंचते कैसे हो । बड़े बड़े फार्म कहते हैं जिन को बनाओ उन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे । वह फार्म किन के हैं, कैसे फार्म बन गए । किसान का कैसे फार्म नहीं बन सकता, जो छोटा जागीरदार है । अगर आप का मकसद यह है, वह यह है कि कल किन्हीं साहब ने फरमाया कि जापान में मैकार्थर ने जब कहा कि इतनी जमीन थोड़ी थोड़ी एकड़ कर दो, छः एकड़ से भी कम दो तीन एकड़ कर दो तो फिर पांच एकड़ वाले तो ५६ फी सदी पहले ही से थे फिर आप को क्या परेशानी हुई। उस के मायने यह हैं कि आप जमीन में पैदावार को बढ़ा नहीं पाए । अगर बढ़ा पाते तो जापान में अगर दो या तीन एकड़ या जो है वह भी अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का पूरा इंतजाम कर सकता है तो कोई वजह नहीं कि हिन्दुस्तान में भी वह बात नहीं हो पाती क्योंकि आप ने अरबाह रुपया इस के लिए खर्च किया। तो कोई न कोई कमी है कि जिस कमी को पूरा करने के लिए आप अब यह पनाह ले रहे हैं यह १७ वें अमेंडमेंट की ।

आप को बड़ा गस्सा आया जब डाह्याभाई जी ने इस को इम्मारल कहा । आप को गुस्सा आया लेकिन मैं कहता हूं कि अक्ल का दिवाला जरूर है । अगर यह अखलाक का दिवाला नहीं है तो अक्ल का दिवाला जरूर है जो कि आप ने निकाला है । क्यों निकाला है, क्यों जरूरत पड़ी आप को ऐसा अमेंडमेंट लाने की ? मैं डाह्या भाई जी से इत्तिफाक करता हूं कि कोई खुदाई खूबी नहीं है । जो हमारा कांस्टीट्यूशन है । उस में कोई एमेंडमेंट हो ही नहीं सकता । लेकिन अमेंडमेंट करना इसलिए है कि वह इस से बेहतर हो । मेरा दावा है कि दुनिया का बेहतरीन जो विधान है, हिन्दुस्तान का विधान, उन में बड़ी शानदार जगह पर है । उस में कमी क्या है त्रुटियां क्या हैं ? त्रुटियां इस तरह से पूरी की जायें कि यह जो बड़ी बड़ी सीलिंग हो रही है उन के दावे जायेंगे । यह वे ही दावे जायेंगे जो मुराहरि जी ने कहा । मुराहरि जी और हमारे प्रो० मुकुट बिहारी लाल जी बावजूद इस के कि वह जानते हैं कि सरकार की नीयत बखैर नहीं, वह जानते हैं कि यह कानून जो है, जो पेश हुआ है और जिसका पोथा हमारे पास रखा हुआ है वह निकम्मा है, वह बोसीदा है, इन कानूनों में बड़ी त्रुटियां हैं, उनमें बड़ी कमियां हैं इसके बावजूद कहते हैं कि हम सरकार की ताईद करते हैं । काहे की ताईद करते हैं ? आज आप दुनिया के सामने यह देख कर जा रहे हैं कि किसी हद तक अदालतों का दरवाजा किसी सूरत में आप बन्द करना चाहते हैं । पंजाबी में कहते हैं "सै को नहीं जांदा, पै को जांदा हूं" मैं उस जानवर की तरफ नहीं देख रहा जिसका कि आप शिकार कर रहे हैं बल्कि उस रास्ते को देख रहा हूं जिस रास्ते से आप शिकार करने जा रहे हैं । जैसे अंग्रेज जब जा रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों की पनाह ली । जब उससे काम नहीं चला तो उन्होंने अछूत भाइयों की पनाह ली । जब इससे भी काम नहीं चला तो राजाओं और नवाबों की पनाह ली । अब आप भी अपनी मैजोरिटी के बल पर ऐसा अमेंडमेंट ला रहे हैं कि जो रास्ता हमको दिखा दे कि कल जब

हम जायेंगे, जो कुछ कहेंगे, हम करेंगे । क्योंकि आपको डर है कि आप आने वाले इलेक्शन में जीतने वाले नहीं हैं, आपकी हार होने वाली है, इसलिए आप डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं । खुदा का शुक्र है कि मैं खुश हूं कि मेरा मुल्क काफी हद तक शास्त्री जी के आने से बच जाएगा । लेकिन वह बुल्गानिन न बने, ख्रुश्चेव पीछे बैठा है, उनको होशियार रहना चाहिए ।

मैं कह यह रहा था कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर किसान का भला हो । लेकिन किसान के भले के नाम पर आप अपना भला सोचें, आप अपनी गद्दी को मजबूत करना चाहते हैं मैं इसकी निन्दा करता हूं और डाह्याभाई जी के उन अल्फाज की तारीफ करता हूं कि आपके अखलाक का दिवाला निकल रहा है । ***(Time bell rings.)*** क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है और मैं हमेशा पाबन्द रहता हूं इसलिए मैं अपने खयालात का फिर किसी मौके पर इजहार करने की कोशिश करूंगा । हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और । वरना मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि :—

"जिस खेत से दहकां को मुय्यसर न हो रोजी,

उस खेत के हर खोशाए गंदम को जलादो ।"

मैं मानता हूं लेकिन इस पर्दे में हजारों एकड़ों पर बागात के नाम पर, फार्मों के नाम पर, कोआपरेटिव के नाम पर सोसाइटी आपने खड़ी की और उसमें हजारों एकड़ ले लिए, किसान के छीन लिए । इस तरह से जो कानून आपने बनाया है आप अपने साथ भी अन्याय करते हैं, जनता के साथ भी अन्याय करते हैं और सिर्फ अपनी अक्सीरियत के बल पर ऐसा बिल पास करना चाहते हैं । मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं ।]

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन लाने का जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं । हमने अपने संविधान में यह गारन्टी दी है :

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity oC the Nation;"

मेरा विनम्र निवेदन और मत है कि संविधान की इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही हमारे संविधान में अन्य प्रावधानों की व्यवस्था है । जो संविधान के अन्य प्रावधान इन लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक हैं उनका संशोधन करने का हमें प्रति दिन और प्रतिक्षण अधिकार है । इसलिए इस सदन के अन्दर और बाहर जिनका भी यह मत हो कि संविधान हमारा ऐसा वेद वाक्य है कि जिसमें संशोधन करने का अधिकार इस सदन को नहीं है, उसमें नये संशोधन करने का अधिकार नहीं है, वह मेरी समझ में सही नहीं है । भूलों का सुधार करना मनुष्य का शाश्वत अधिकार है और मनुष्य चूंकि सीमित है, इसलिए उससे भूलें, अधिक से अधिक बुद्धिमान आदमी से भी, एक व्यक्ति से या समूह से भी, हो सकती हैं ।

जब हमने संविधान का निर्माण किया था उस समय यह आशंका नहीं थी कि जो हमारे मौलिक लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में इतनी जल्दी

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

रुकावट आने लगेगी । हमने अपने संविधान के इन अधिकारों की प्राप्ति और इन लक्ष्यों की ओर जाने के लिए अपना लक्ष्य सामाजिक न्याय पर आधारित समाजवाद घोषित किया । समाजवाद की स्थापना में शीघ्रता लाने के लिए जितनी विषमता है उसको दूर करना हमारा पहला कर्त्तव्य है । उसी के साथ हमने जो कदम उठाये स्वाधीनता के बाद, एक के बाद दूसरे, हमने जितनी सामाजिक विषमतायें थी उनको मिटाने की ओर कदम बढ़ाया और भौमिक अधिकारों को समान करने का काम सब से पहले शुरू किया । हमारा जो बड़ा देश और खेती का देश है, उसमें सम्पत्ति के अधिकार ऐसे थे कि एक तरफ तो सामन्तशाही थी, ताल्लुकेदारी थी और बड़े बड़े किसान थे। और एक तरफ भूखा हमारा अपार जनसमूह था जिसके हाथ में काम करने की शक्ति थी और उदरों में क्षुधा थी, इन लोगों का भी एक समूह था । इन लोगों को खिलाने के लिए हमें करोड़ों टन गल्ला बाहर से मंगाना पड़ा । यदि हम सामाजिक न्याय की तरफ कदम उठाने के लिए कृत-संकल्प हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि उस सामाजिक न्याय को पूर्ण रूप से अवतरित करने के लिए जो भी बाधाएं हमारे संविधानरोक हैं उनको दूर करें । आज का संशोधन विधेयक केवल उसी रुकावट को दूर करता है और उस सामाजिक न्याय को शीघ्र से शीघ्र लाने के लिए एक आगे का कदम है ।

इस संशोधन के सम्बन्ध में यह कहना कि सम्पत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर यह कुठाराघात है, यह मेरी विनम्र सम्मति में सही नहीं है । सम्पत्ति का मौलिक अधिकार कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को अगर सारे देश की भूमि पर अधिकार करने का स्वत्व हो तो हम उसे स्वीकार करें ? वास्तव में हमने अपने देश में जिस समाज की स्थापना का संकल्प किया है उसको हमने यह स्वरूप देने का संकल्प किया है कि इस भारत की धरती सारे देश की सामान्य सम्पत्ति है । इस देश की धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती की सम्पत्ति से सुख भोग करने का वही अधिकार है जो कि एक मां के स्तन से दूध पीने का अधिकार उसकी सभी सन्तानों को है । यदि कोई भी भाई अपने दूसरे भाई को मां के स्तन से दूध पीने से वंचित करता है तो वह न्यायसंगत बात नहीं है । इसी प्रकार यदि कोई विधान, कोई भी संविधान, कोई भी कानून अपने प्रत्येक नागरिक को उसके शाश्वत अधिकार के उपभोग से वंचित करे तो वह अन्याय है और उसको दूर करना इस संसद का परम कर्त्तव्य है। इसलिए जो भौमिक सुधार के कानून हमारे राज्यों में पिछले १९५२ से, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है बनते चले आये हैं, उनके रास्ते में जो रुकावटें संविधान के कारण प्रतीत हुई है उनको दूर करने का प्रयास हम आजतक करते चले आ रहे हैं । यह कहना कि सुप्रीमकोर्ट या उच्च न्यायालय की भी कोई अमान्यता या उनकी अवमानना हमारे इन संशोधनों से होती है तो यह बात भी सही नहीं है । वह न्यायालय, यह संसद, ये सभी एक उद्देश्य से समाज की सेवा के लिए है । संसद जहां कभी भी ऐसा कानून बनाये जो जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करता हो तो सुप्रीमकोर्ट या उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वहां उन्हें रोकें । लेकिन जहां तक हमारे इन आदर्शों की पूर्ति में जिनको हमने अपने लक्ष्यों में घोषित किया है कि हम इस देश में सामाजिक क्षमता लायेंगे, समाजवाद की स्थापना करेंगे, उसकी पूर्ति के लिए जहां कहीं भी संविधान में हमसे भूल हुई है, न्यायालयों के निर्णयों से इसमें बाधा पड़ी हो, वहां हमें हर तरह का सुधार करना आवश्यक है । हम अपने न्यायालयों के निर्णयों को मान्यता देते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ जाने के लिए

सुधार करेंगे तो यह कोई अनुचित बात नहीं होगी ।

मान्यवर, हमें इस बात का सन्तोष है कि इस सदन के प्रायः सभी दल के लोगों ने इस सदन में और बाहर इस संशोधन का मौलिक रूप से स्वागत किया है । किन्तु एक दल है जो सामन्तों का और सामन्तशाही का समर्थक है, उसी दल की ओर से आपत्ति की गई है । (*Interruption*) वे रानियां जो हमारे मत में हो जाती हैं वे रानी नहीं रह जाती हैं । वे राजा जो हमारे मत में हो जाते हैं फिर राजा नहीं रह जाते हैं । गनी साहब ने महात्मा गांधी जी का नाम लिया । उनको जानना चाहिये कि गांधी जी हृदय परिवर्तन के शाश्वत अधिकारों को मानते थे । हृदय परिवर्तन राजाओं का भी, हो सकता है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवाज जो सामन्तशाही की आ रही है आज के इस राकेट युग में, वह कुछ उचित मालूम नहीं देती है । जहां एक ओर यह आवाज आ रही है कि हम संविधान में जल्द से जल्द परिवर्तन करते चले जा रहे हैं, वहां दूसरी ओर यह आवाज भी प्रजा समाजवादी दल, साम्यवादी दल की ओर से आ रही है कि हमारी गति, हमारी प्रगति मन्द है । स्वतन्त्र दल का कहना यह है कि हमारी गति तेजी से जा रही है, यह सही बात नहीं है । वस्तुतः उनके मन में जो साम्यवाद के आने का भय है उसको रोकने का केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि जिस तरीके से हमने पिछले १५ वर्षों से देश को समाजवाद की तरफ हृदय परिवर्तन के साथ, शान्ति के साथ, प्रजातान्त्रिक तरीकों के साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं तरीकों के साथ आगे भी लेते चले जायं । उसी तरीके के अपनाने का परिणाम यह हुआ कि हमने सामन्तशाही, जमींदारी, ताल्लुकेदारी को बगैर किसी विप्लव के अपने देश से खत्म कर दिया । यह हृदय परिवर्तन का सब से बड़ा परिणाम है ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं । मेरी अपनी सम्मति यह है कि स्वतन्त्र पार्टी की ओर से इस संशोधन का जो विरोध किया जा रहा है वह कोई ऐसा नहीं है जिसके जवाब देने की आवश्यकता है । वे तो एक वैस्टेड इन्टरेस्ट के लोग हैं । इस देश में सामन्तशाही मरती हुई एक व्यवस्था है जो अपने जीवन की अन्तिम घड़ियों का इन्तजार कर रही है । यही कारण है कि ये लोग इतना शोर करते हैं ताकि कुछ दिन और जिन्दा रह सकें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दिन बीत चुके हैं । इस देश में सम्पत्ति अधिकार की जो वस्तु आज से ५० वर्ष और १७ वर्ष पूर्व थी उसका सपना देखना एक सोते हुए सपने के समान है और वह भी रहने वाला नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI B. K. GAIKWAD (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. While supporting it, I will have my observations.

Going through the Statement of Objects and Reasons of the Bill, as introduced in the Lok Sabha, it is specifically pointed out that the proposed amendment has been necessitated by the judgment of the Supreme Court declaring certain vital provisions of the Kerala Agrarian Relations Act, 1960 *ultra vires* the Constitution. Sir, the Kerala Agrarian Relations Act was the one piece of land reforms legislation which sought to translate the declared objective of the Five Year Plan into reality and to confer substantial rights on the tillers of the land in Kerala. Sir, it is our conviction that this country cannot progress or move towards the national goal of socialism without basic changes in the land system. When such major reforms are launched, it is but natural that s;>me fundamental rights of others may be contravened largely because the right to hold pro-

[Shri B. K. Gaikwad.] perty is a guaranteed right under our Constitution.

Sir, the Kerala Agrarian Relations Act, 1960, in preference to the obnoxious measure, has been subsequently passed under pressure of the landed interests in the State. In fact, there is no justification for giving up the Agrarian Relations Act. It had received considerable debating attention in the Assembly and in the Press. It underwent thorough scrutiny at the hands of the Joint Committee and many amendments were made. The Central Government had given its approval through Presidential assent. The Planning Commission had also scanned and satisfied itself about the provisions.

In view of the Government policy, several State Governments have also passed several such Acts and tried to bring socialism.

While considering this Bill under discussion, the Joint Select Committee also opposed the deletion of the various Acts of the States which were included in the amending Bill. They were included by way of abundant caution in order to protect them against possible attacks in the Supreme Court or the High Courts.

Sir, I will now turn to the Acts which the State Governments have passed. The aim of introducing ceiling on the land is that there should be a fair distribution of the land on an equitable basis amongst those who cultivate the land. What do we find today? About 42 per cent, of the people of the country possess less than one acre of land. Very few persons possess thousands of acres of land as their own. We do not want to go to the root cause as to how these persons got such big lands in their names. In the interest of the country now all such lands should be redistributed equitably. Now we have to see whether the Acts which have been passed by the State Governments have redistributed the lands equitably. Sir, my reply to that would be that there are several loopholes in these Acts and therefore several States have failed to confer real rights on the cultivators.

I will quote a few instances in the matter. In the proviso to clause 2(1) of the Bill, it is said—

> . " . . .where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit . . . ", etc.

Here, there is no definition of personal cultivation. In some of the Acts passed by the States, the definition of personal cultivation is:—

> "To cultivate personally means to cultivate land on a person's own account
>
> (1) by his own labour; or
>
> (2) by the labour of any member of his family; or
>
> (3) by hired labour or by servant on wages payable in cash or kind (but not crop share) under the personal supervision of himself or any member of his family."

Sir, you will find that this definition is very vague. May I ask what would be the definition of 'to cultivate'? The definition of 'to cultivate' should be that a man must cultivate the land personally by his own hands and not through labour or under his personal supervision. However, there are many such funny and silly definitions in these Acts.

As I come from Maharashtra, I will quote what the Maharashtra State Government have decided while fixing the ceiling. In my opinion, there is no principle in it. They ought to have taken into consideration that—

> (1) the revenue assessment of the ceiling area should have been equal or approximately equal;

(2) the money value of the ceiling area should have been equal or approximately equal;

(3) the production from the ceiling area should have been equal or approximately equal;

(4) the gross income from the ceiling area should have been equal or approximately equal.

But you will find that while fixing up the ceiling area, and the amount of ceiling area, the minimum revenue rate at some places is Rs. 594 and the assessment of ceiling area at maximum revenue rate is Rs. 1,650. It further reveals that instead of equal land revenue getting equal acreage as ceiling area, the Act has given unequal land revenue to fix ceiling area. It is apparent therefore that the classification of the lands under that Act is in total disregard of any fair, just and equal basis even in respect of land revenue.

In continuation of the above, for a picture of higher and lower money values of ceiling areas in the Maharashtra State, I may say that the ceiling area money value at lower revenue rate is from Rs. 831 ■ 50 and the ceiling area money value at higher revenue rate is Rs. 99,000. Where the land approximately is of the same quality, the difference in the ceiling area should have been just the same. The ceiling areas in Thana, Kolaba and Ratnagiri Districts are 66 acres uniformly while in Chanda District it varies from 108 acres to 198 acres and in Bhandara District it varies from 108 acres to 114 acres. The same is the case for fixing compensation.

Further, I want to suggest that it is no use introducing land reform measures unless they are going to be implemented properly. The crux of the matter is that on the on$_e$ hand, millions of tenants and landless labourers do not get any land to cultivate and on the other, there are persons having a large acreage in their possession. There is poverty and jnemoloyment in rural areas. They are half-fed, half-naked. They are treated a$_s$ slaves. They have not seen the rising sun of independence. They are leading a miserable life. Sir, the Government, therefore, should come forward with the necessary powers to carry out a bold and swift programme of land revenue. After the passing of the measure, they should not be found fumbling.

Lastly, a word which may or may not relate to this Bill. It is a fact that there is considerable Government wasteland available in the country. If we want to get land for the poor and the landless, Government should take necessary precautions to see that this land is at least, to begin with, distributed among the landless and the down-trodden poor people immediately, as early as possible. This demand is being made in this House as well as in the Lok Sabha for years together. Such land is something like 125 million acres of land. If it is done, it will be a great help to the downtrodden. With these words, I conclude.

SHRI NAFISUL HASAN (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the motion which is under the consideration of the House. To my mind, this amending Bill contains nothing new. As a matter of fact, this is meant to remove the technical hindrance which has come before us and which is going to prevent us from implementing the land reforms policy, a policy initiated even before the country attained freedom, a policy which is accepted not only in the Preamble of the Constitution but also in the Directive Principles of the Constitution, a policy which has been accepted by the country during the last so many elections. The question of land reforms was prominently raised during all the general elections. What are the steps that have been taken or the implementation of that policy?

Sir, we started with the abolition of zamindari. Intermediaries were taken away. There was to be direct rela-

[Shri Naflsul Hasan.] tion between the Government and the tiller of the soil. We find that the question of adequacy of compensation was dealt with under the Constitution amending Bill, and it was accepted by Parliament also that as far as the question of compensation was concerned, the court's jurisdiction was to be taken away and the Government should decide what compensation would be adequate. After that there were two other amendments which brought in article 31(a). And it was •clearly laid down that the question of compensation for the lands, for the estates acquired, in order to implement land reforms will also not go before the courts of law. Now, Sir, the intentions of those who made amendments were absolutely clear. Unfortunately, the definition of the word "estate" was such that when the question went before the Supreme Court and the High Courts, they held that certain lands were not to be included according to this definition. Re-organisation of State also led to certain confusion because according to the definition, as it was originally contained in the Constitution, estate was to be considered in different ways according to the definition given to it by the land reforms Acts in the different States. And on account of the re-organisation certain parts of land, which originally were governed by the Acts of a particular State, went over to other States where there was a different definition.

Anyway, Sir, it is contended by the Swatantra Party that by passing this amendment, w_e are showing disrespect to the Supreme Court. I submit. Sir, that we are, on the other hand, showing the greatest respect to th_e Supreme Court. Here we are expected to make laws whereas they are there to interpret them. We are going fully to accept their interpretation. We bow our beads to them as far as their (functions are concerned. Whereas we believe that they are there to interpret, on the well known rule of interpretation that the Legislature will be presumed to mean what it said and said what it meant. Now, it is quite open to us to include all agricultural lands under the definition of 'estate'. Therefore, having full respect for their views, we are making our intention absolutely clear.

Now, Sir, all the opposition to this Bill comes from the Swatantra Party. I was wondering what was there to oppose it. All the principles had been accepted already. It is only a lacuna that has arisen on account of the interpretation of the Supreme Court that we are bringing forward this amendment. And, you see, Sir, there was such a huge propaganda against this Bill. There were meetings and so many representations. I was on the Joint Select Committee. I do not know how many representations were there.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): That shows how many people in this country are against this measure.

SHRI NAFISUL HASAN: I know the machine of the Swatantra Party was very active. All the means of propaganda were applied but the whole ground, they will find, of their propaganda fell when it was found that from the Select Committee the Bill came in a form which showed that

ill consideration had been given a3 far as the interest of small tenants is concerned.

A new proviso has been added which clearly shows that if any person is in possession of land, no law will be valid to acquire the land which is within the ceiling unless there is provision for making payment of full compensation at market rates. Therefore, thair propaganda that the small tenant and everybody is going to be affected has absolutely no force.

There is one other objection that by including all these Acts, this is a sort of blanket deal. A_s a matter of fact, the Select Committee has scrutinised all these Acts and they have taken out quite a number of them. Moreover, there is one other point and

that is this. It is not absolutely-necessary to include these Acts in the Schedule because our whole purpose is served by the changed definition of 'estate'. But in order to make ourselves doubly sure, these Acts are being mentioned in the Schedule. The immunity which is given to these Acts is that they will be immune only insofar as the provisions thereof are inconsistent with the Fundamental Rights. If there is any other defect, supposing they suffer from the defects in the power of their Legislatures to make that law, or for certain other reason, then in that case, even their inclusion in the Schedule will not cure that illegality. They will be valid only to the extent that their provisions are inconsistent with particular Fundamental Rights, and therefore I submit that even if they had not been included in the Schedule—these Acts —the definition of 'estate' would have saved all those enactments.

Just one word more. In their propaganda against this Bill, Shri Dahyabhai Patel, the Leader of the Opposition, said the other day that the Government was only a temporary one, a caretaker Government and so we should not proceed with this Bill. Earlier also, I remember, on a day -we met after the demise of our late lamented Prime Minister, a suggestion was made, not only in this House by the Leader of the iSwatantra Party, but also in the other House, that we should not do any other business.

SHRI S. S. MARISWAMY (Madras): What is wrong with it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): It is time to wind up, Mr. Nafisul Hasan.

SHRI NAFISUL HASAN: I am winding up in one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You said, 'one word more'. Now you want one minute; the position goes on changing.

338 RSD—4.

SHRI NAFISUL HASAN: All right, Sir. If you do not allow me, I have to close down; I shall sit down.

SHRI C. K. GOVINDAN NAIR (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, today we are attempting at last to fulfil and to implement certain promises and pledges which we gave to ourselves. As things stand, any reform—be it social, economic or agrarian—ig bound to cause some loss to a few, and some privileges enjoyed by a few have to be distributed among the many, and specially when it relates to land, it is a valuable right, and the position in India becomes rather worse on account of certain things. In our Constitution, we have guaranteed Fundamental Rights. At the same time, we have the Directive Principles also, the intentions of which are mainly to create a society which is more or less equal. But at the same time, there are the courts of India, which have been established long before the establishment of the Constitution, which have been working under a different system for a long number of years and which, as all courts of law, naturally, are conservative in outlook; courts of law are generally conservative in outlook. So, what we find when we try to implement the principles underlying the Indian Constitution is a conflict. On the one hand, the courts are there. Whatever might have been the intentions of the courts, the general feeling among the laymen is that the courts are sitting as a sort of appellate authority over the decisions and enactments made by this Parliament. Whatever that might be, the result with regard to land reforms has been always very unhappy. Several laws were passed by the State Legislatures, which were struck down very often by the courts of law.

Sir, reference has beem made to Kerala by several Members of this House. I do not want to go into the merits of the two or three legislations by different Governments in Kerala, whether one legislation is more beneficial to the tiller of the soil, or the other legislation is less beneficial to

[Shri C. K. Govindan Nair.] tnem. That apart, the general intention was to have a better distribution of land with certain modifications in the present system. What happened, unfortunately, in Kerala—was it happened throughout India in some courts —was that systems which were very similar to ryotwari were held to fall within the term 'estate' while in some cases the courts in some States held that they did not come within the term 'estate', and the position in Kerala became rather very peculiar due to the decisions of the courts. After the passing of the Agrarian Relations Act, 1960, two or three cases went up to the High Court. In certain cases it was held that 'ryotwari' did not come under the term 'estate'. As was pointed out by some hon. Members yesterday, the ryotwari system is claimed to be much more ancient than even the British Government. It is even said that it was established by Manu. Simply because a system happens to be very ancient, it does not become very sacred. Very many things which were considered sacred, and Which were traditionally supposed to have been established by Manu, have been given the go-by in India, and it has been given the goby by the Indian Legislatures; nobody questioned then the character of those legislations because they were ancient. Whether it was established by Manu or Monroe or anybody else, we have to change the system. We have come to

■>t stage. So then, in certain parts of the old Madras Province, in South Canara, it was held that this Act would not apply and the Act was struck down, because they said it was under 'ryotwari'. Unfortunately, a very curious thing happened in Malabar also. The Malabar *janmi* is supposed to have the most superior right in land. Even under the Tenancy Act passed by the Madras Legislature, he was described as having the most superior proprietary rights in land. No *janmi* of Malabar would ever say that he had at any time any right which was less than that of the Government; he claimed even greater rights than the Government; the ancient documents also show that. Even the courts, I remember, have given certain decisions which said that the Government had absolutely no right over the land of these *janmis* What happened after the passing of this Agrarian Reforms Act and after the judgment of the Supreme Court was that the whole scheme was amended and certain amendments were made in the plaint and it was said that even the *janmam* right was only ryotwari right. That is to say the position was changed. It depended upon a very funny thing. After the settlements in Malabar, of 1900 to 1905, 1930 to 1933, unfortunately what appears on the printed pages of these papers i$_s$ the letter "R" in Malayalam. This letter "R" means—and that is the interpretation of the Court and I am not blaming the Court—the High Court Judges held that "R' meant "ryotwari". *Janmam* was given the go-by, to the most agreeable surprise of even the *janmis.* The *janmi* always said that he had the most superior possessory right over the land in his possession, whether it be with the tenant or whether it be with himseH. But he found to his great surprise that for the purpose of defeating the provisions of this Act, it was held that he was also a ryotwari holder, so much so that he did not come under the provisions of the said Act. That is to say, he does not come under the definition of "estate". Therefore there was a stalemate. Naturally it was a stalemate. Well, there may be difference of opinion with regard to the various sections of the Act. Whatever it be, another Government came into power and they also, almost on the same lines, passed a certain legislation and that legislation has now been included in this amending Bill, and so we have now the position that all these Acts would be put on the permanent list of enactments which cannot be questioned in a court of law.

Now, very much has been said about -Fundamental Rights, about the ancient character of these tenancies and **all** that. Well, I would like thi$_s$ House to

consider the nature of Fundamental Rights or the eternal rights. What are these fundamental, these eternal rights? Are there any eternal rights in the world? "We are living in a changing world, and these Fundamental Rights, for whose benefit are they? Surely they are not there for the benefit of a few. They are there for the benefit of the people of the land, of the people who framed the Constitution and gave it to themselves and] to the country. Certainly, I say Fundamental Rights are for those people who made the Constitution and gave it to themselves, to the people of India. You cannot ignore the people of India in the name of the Fundamental Rights. The Fundamental Right has to go to the wall, and if they do not go to the wall, under a process of law, some other things will happen which should be avoided. Thank you.

श्री देवी सिंह (राजस्थान) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन के सामने जो संशोधन पेश हुआ है यह एक बहुत ही महत्व का है जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग को अफैक्ट करेगा । हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलते हुए उसके बारे में बहुत गुण बतलाये । उन्होंने कहा कि यह किसानों के अन्दर इन्कलाब लायेगा, देश के अन्दर ज्यादा उत्पादन करेगा, देश में जो छोटे छोटे खेत हैं, उन्हें सरकारी खेती में दे दिया जायेगा जिस की बड़ी तरक्की होगी । जो सरप्लस जमीन है वह दूसरों के पास चली जायेगी और मिडिलमैन नहीं रहेंगे ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आज जो मिडिलमैन का क्वैश्चन लाया जाता है, वह कहां से आ गये ? जमींदारी और जागीरदारी बिल पास होने के बाद इन सब लोगों का अंत हो गया है और इसके बाद अब मिडिलमैन कहां रहे ? परन्तु आज भी हमारे कांग्रेसी भाइयों के ख्वाब में भूत ही नजर आ रहा है और उसकी आड़ में दूसरी दूसरी चीजें करने जा रहे हैं । हमारे भाई उत्पादन के बारे में भी बात करते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग से उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जायेगा । अब आप ही देखिये कि चीन और रूस में कोआपरेटिव फार्मिंग किया गया तो क्या वहां पर अब भी अनाज की कमी नहीं है । आज इन मुल्कों को भी दूसरे देशों से अनाज लाना पड़ रहा है ।

हमारे जो कांग्रेसी भाई यह कहते हैं कि इस बिल द्वारा किसानों में इन्कलाब आ जायेगा उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान को ही देख लीजिये । राजस्थान में भूमि के सम्बन्ध में जो ऐक्ट बना था उससे मैं वाकिफ हूं । मेरी वहां के मेम्बरों से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी और उनका दृष्टिकोण सीलिंग के सम्बन्ध में इस प्रकार का था । वे लोग यह चाहते थे कि काश्तकारों के पास इतनी जमीन हो जिससे उनकी आमदनी १०० रु० माहवार हो जाय । अब आप खुद ही ख्याल कर सकते हैं कि आप काश्तकार को इतनी जमीन देना चाहते हैं जिससे कि उसको सिर्फ १०० रुपया माहवार की आमदनी हो सके और वह इन १०० रुपयों से अपने सारे घर का खर्च चलाये । इन रुपयों से वह अपने लड़कों की शिक्षा का भी प्रबन्ध कर सके क्योंकि यह बात सब लोग जानते हैं कि आजकल शिक्षा के बारे में सरकार ने क्या प्रबन्ध कर रखे हैं । अगर काश्तकार या उसके बाल-बच्चे बीमार हो जाते हैं तो गांवों में अस्पताल का कोई प्रबन्ध नहीं है । आप की कृपा से आजकल दवाइयों और डाक्टरों की फीस इतनी ऊंची चली गई है कि वे गरीब बेचारे उसको मीट नहीं कर सकते हैं और आप यह चाहते हैं कि १०० रुपये के अन्दर किसान सब कुछ कर ले । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि आपकी पालिसी क्या है जबकि शहरी तबके हजारों रुपया कमा सकता है, उसकी कमाई पर आप कोई सीलिंग नहीं लगाने जा रहे हैं और आप देहात वालों से यह चाहते हैं कि

[श्री देवी सिंह]

वह १०० रुपया माहवार में अपना सारा खर्च चलायें और इससे ज्यादा न कमायें। आज दुर्भाग्य इस बात में है कि हमारे सदन के सदस्य यह चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह ४०० रु० माहवार से ५०० रु० माहवार हो जाय और किसानों की आमदनी १०० रु० माहवार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यह हमारी सरकार की नीति है।

अब दूसरी तरफ आप देखिये कि हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान है और वहां पर कोई उपज नहीं होती है। वहां पर ज्यादातर लोग भेड़ और गाय पाला करते हैं और इस तरह से अपना धन्धा चलाते हैं। हमारी सरकार द्वारा भेड़ और गाय चराने के लिए एक सीलिंग कानून बनाया गया था जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने पांच साल पहले भेड़ों के समूह को रजिस्टर करा लिया है उन्हें ही जमीन चरने के लिए दी जायेगी। जो गरीब जमींदार देहातों में रहते हैं उन्हें इस कानून का पता नहीं है। जिन लोगों के पास सौ, दो सौ, पांच सौ भेड़ें हैं, जो बड़े जमींदार हैं और जिन्हें कानून का पता है उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है और उन्हें चरने के लिए जमीन दे दी गई है। जिन लोगों ने पांच साल पहले अपने जानवरों का सामूहिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें जमीन नहीं दी गई है। स्वतंत्र पार्टी इस पक्ष में नहीं है कि कोई इतना बड़ा लैन्डलार्ड के रूप में रहे परन्तु आप इस बिल के द्वारा यह बात करने जा रहे हैं जो कि एक काश्तकार को बुरी तरह से हिट करेगा और आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं। मगर मुझे इस बात का अनुभव हो रहा है और हमारे अधिकतर कांग्रेसी सदस्यगण खेती के मामले में अनभिज्ञ हैं क्योंकि वे ज्यादातर शहरी इलाकों से आते हैं। वास्तव में उनको यह पता नहीं है कि काश्तकार का क्या हाल है और इस ऐक्ट के द्वारा आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि जड़ काट रहे हैं।

इन सब चीजों के साथ बहुत सी ऐसी चीजें कही गई हमारे सदन में कि हमारी सरकार देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी लाना चाहती है और स्वतंत्र पार्टी और ऐसी प्रतिक्रियावादी पार्टियां उसे रोक रही हैं। हमें बड़ी खुशी हुई यह सुन करके कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न ला रहे हैं, परन्तु मेरी तुच्छ बुद्धि में सोशलिस्टिक पैटर्न अभी तक समझ में नहीं आया है। आप सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं, लेकिन आपके रैंक्स में इस तरह के सदस्य हैं जिन को लाखों रुपये का प्रीवी पर्स मिलता है। उनके पास लाखों और करोड़ों रुपये की इमारतें और प्राप्टीज हैं। फिर भी आप सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। हमारे वे माननीय सदस्य सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अगर वास्तव में कांग्रेस के सदस्य सच्चाई के साथ सोशलिस्टिक पैटर्न चाहते हैं, जैसा कि वे कह रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कहता; बल्कि जो भी स्टैंर्ड वे सोशलिस्टिक पैटर्न का मानें उससे एक्सट्रा जितनी लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति जिन कांग्रेसी सदस्यों के पास है, उसको उन्हें देश को वापस कर देना चाहिये देश की तरक्की के लिये, तब तो मैं कहूंगा कि आप सच्चे रूप में सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, वरना मैं यही कहूंगा कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। वास्तव में मैं तो यह समझूंगा कि यह तो गांधी जी के नाम पर जो बड़ी बड़ी प्रापर्टी और जायदादें हैं उनको सोशलिस्टिक पैटर्न की दुहाई दे करके बचाने के सिवा और कुछ नहीं है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की बातें कहीं। यह कहा गया कि जिनके पास बड़ी बड़ी चार-पांच सौ एकड़ जमीनें हैं उनको हम हटाना चाहते हैं। इसके विपरीत हम को मिलता यह है कि तीन सौ

स्क्वायर माइल जमीन हमारी सरकार अन्डमन्स में देने जा रही है। यह इस पत्र में मौजूद है। तो एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि जिन के पास ४०० या ५०० एकड़ जमीन है वह ले ली जाय और दूसरी तरफ हमारी सरकार तीन-तीन सौ स्क्वायर माइल भूमि सोशलिस्टिक पैटर्न के अन्दर लोगों को किसी रिवार्ड के रूप में देना चाहती है।

श्री लोकनाथ मिश्र : किस को दी जा रही है ?

श्री देवी सिंह : कोई साहब होंगे। यह अखबार मौजूद है।

तो यह आप का सोशलिस्टिक पैटर्न है। मैं मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको साफ तो करें कि आप के सोशलिस्टिक पैटर्न का आखिर में क्या स्तर है। जैसा कि मैं देख रहा हूं, वह अगर लाखों करोड़ों का है, तो मेरे खयाल में विश्व की किसी भी राइट विंग पार्टी को आप का सोशलिस्टिक पैटर्न ऐक्सेप्ट करने में कोई शंका नहीं होगी।

हमारे हाउस की एक माननीय सदस्या ने कल ऐसा फर्माया कि स्वतंत्र पार्टी के नेता श्री राजगोपालाचारी जी, जब हमारा विधान बन रहा था, उस समय इस तरह के प्रगतिशील कानूनों के पक्ष में थे, परन्तु आज वे और उनकी पार्टी बिलकुल बदल गई है और स्वतंत्र पार्टी प्रगति के रास्ते में बाधा के रूप में आ रही है। मेरे खयाल से राजा जी के जो विचार उस समय थे, उनमें आज भी कोई अन्तर नहीं हुआ है। राजा जी और हमारी पार्टी के किसी भी प्रगतिशील कानून के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया कि यह कानून जो आप इस वक्त इस सदन के अन्दर लाये हैं, यह प्रगतिशील नहीं है और इसके अन्दर काश्तकारों की जमीनें ले ली जायेंगी जिससे आगे चल कर उनके दिमाग में अनस्टेबिलिटी आयेगी। अगर बड़े जमींदारों का ही सवाल था तो उनके लिये आप एक स्पेशल ऐक्ट बना सकते थे कि इतने से ज्यादा जमीन उनके पास न हो। परन्तु इस तरह का यह जो बिल आया है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और मैं सदन के सब सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे इस पर अच्छी तरह से विचार करके आगे अपनी राय जाहिर करें।

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सदन के सामने है उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे ताज्जुब है कि हमारे कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस बिल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते हुए, जो शासक वर्ग है उसकी नीयत में कुछ सन्देह प्रगट किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने न तो पिछले इतिहास पर विचार किया है और न उन वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया है जिनके कारण यह बिल आया है। उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिये और यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि संविधान बनाने में जो खास हिस्सा या हाथ रहा है वह जो आज का शासक वर्ग है उसका ही रहा है, यानी दूसरे माने में कांग्रेस पार्टी का ही रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो संकल्प किया था, जो प्लेज लिया था और जो हमेशा वह लेती रही है, उसके आधार पर ही उसने सारे कानून बनाये और उसी के आधार पर संविधान बनाया। संविधान जब बना, उसके बाद उसके अमल में आने में न्यायालयों से जो दिक्कतें पेश आईं, उनको दूर करने के लिये अब यह अमेंडमेंट हाउस के सामने आया है। मैं तो समझता हूं कि जो महोदय इस प्रकार का विचार प्रगट करते हैं उन्हें तो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के शासक लोगों को धन्यवाद देना चाहिये कि जब कभी भी उन्हें आवश्यकता हुई और जब कभी भी उनको यह मालूम हुआ कि उनके बनाये हुए कानूनों में कोई त्रुटि है तो उन्होंने उसको दुरुस्त करने में कभी दरेग

[श्री राम सहाय]

नहीं किया, कभी परहेज़ नहीं किया और कभी यह ख़याल नहीं किया कि उनके ऐसा करने से कुछ बुराई पैदा होगी। जिसके लिये जैसी जैसी आवश्यकता हुई, उस प्रकार के कांग्रेस सरकार ने कानून बनाये और उस प्रकार के संशोधन संविधान में भी किये।

अभी अभी हमारे एक सदस्य महोदय ने यह बताया कि कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि किसानों में इन्क़लाब लाने के लिये यह कानून बना है। मैं कहता हूं कि किसानों में तो इन्क़लाब लाया जा चुका है और जो इन्क़लाब लाया गया है उसको कायम रखने के लिये ही यह संशोधन हाउस के सामने उपस्थित किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर वे इस पर विचार करते और इस शैड्यूल में जो ऐक्ट्स शामिल करने के लिये रखे गये हैं उन पर ध्यान देते, तो उनको यह अवश्य ज़ाहिर हो जाता कि दरअसल इस अमेंडमेंट के लाने का मक़सद यह है कि जो दिक्क़तें हमारे सामने आईं उनको दूर करने के लिये, और जो सुधार किसानों के लिये किये गये उनको क़ायम रखने के लिये ही यह संशोधन लाया गया है।

एक बात मैं यह अर्ज़ करूं कि इस बात को कभी भूल नहीं जाना चाहिये कि इस संशोधन में जो कुछ भी कहा गया है वह यह कहा गया है कि जब कभी किसी की भूमि ली जायगी तो उसे मार्केट वल्यू दी जायगी। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा इंसाफ की चीज और क्या हो सकती है। हम ने वह ज़माना भी देखा है जब किसानों की भूमि या ज़मींदारों की भूमि या जागीरदारों की भूमि अकारण ही ले ली गई और अगर किसी को कुछ मुआवजा दिया गया तो वह बिल्कुल नगण्य था। अब हम जब इस प्रकार के कानून बनाते हैं कि जिस किसी की भी ज़मीन ली जायगी उसे बाजारी कीमत दी जाय और उस पर कुछ परसेंटेज अधिक भी दिया जाय तब मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार से कोई भी अन्याय करने की बात नहीं कही जा सकती। मेरा ऐसा ख़याल है कि हम इस बारे में अच्छी तरह से विचार करेंगे तो हम सही नतीजे पर पहुंचेंगे।

अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उसका कल हाउस में जिक्र आया और उस बारे में कुछ दुहराने की आवश्यकता नहीं है, उसकी वजह से भविष्य में जो रिफार्म्स अभी तक किये गये हैं उन सब को यथावत कायम रखा जा सके, सारे स्टेट्स में जितने भी ज़मीन के सुधार के सम्बन्ध में कानून बने हैं उन पर अच्छी तरह से अमल हो सके—यही उद्देश्य इस संशोधन का है और इस संशोधन के बारे में कुछ भी शंका करना मुनासिब नहीं है।

अभी जो सदस्य महोदय बातें कर रहे थे वह सोशलिस्ट पैटर्न की बात कह रहे थे, उसमें आशंका ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम लोग महात्मा जी के फालोअर्स हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के फालोअर्स हैं और उन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिन्होंने आज से १० साल पहले यह वसीयत की कि उनकी भस्मी भी जो है वह भी कृषकों के काम में आये, यह बात उन्होंने वसीयतनामे में आज से १० वर्ष पहले लिखी, तो उन्हें इन सब बातों पर विचार करना चाहिये और वह जब कभी भी अपने विचार प्रकट करें तो इस पृष्ठभूमि में ही उनको अपने विचार प्रकट करना चाहिये। विरोध के लिये कुछ भी बात कही जा सकती है उसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन जो तथ्य हैं उन से इन्कार नहीं करना चाहिये। विरोध करने का जो दायरा है वह भी एक सीमा तक होना चाहिये। जो कार्य किसानों की भलाई के लिये, सुधार के लिये किया जा रहा है उस पर भी कोई संदेह ज़ाहिर करना कभी भी

मुनासिब नहीं है, गांवों में एक गलतफहमी पैदा करना कुछ मुनासिब नहीं है, कृषकों के लिये जो सुधार किये गये हैं उन पर किसी प्रकार की शंका प्रकट करना कुछ मुनासिब नहीं है । यह तो इतिहास बता रहा है कि कांग्रेस ने जितने भी कार्य किये हैं वह कृषकों की भलाई के लिये किये हैं, ज़मींदारी, जागीरदारी इत्यादि जो समाप्त की गई है वह कृषकों की भलाई के लिये ही की गई है । आज जो बहुत से कृषकों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उन पर जो सीलिंग कायम की गई है वह भी कृषकों की भलाई के लिये ही किया गया है । इतिहास इस बात का साक्षी है । मैंने तो यह देखा है कि दूसरे पेशों के लोग, वकील, डाक्टर, साहूकार इत्यादि जो गांवों में ज़मीन लेने के लिये उत्सुक रहते थे, जिन्होंने वहां हज़ारों बीघे ज़मीन ले रखी थीं, वे सब अपनी अपनी ज़मीनें बेच बेच कर अपने अपने यथास्थान पहुंच गये हैं और वे उससे लाभ नहीं उठा सके । मैं यह भी देखता हूं कि बड़े बड़े किसान जिनके पास अधिक ज़मीनें हैं वे भी अपनी ज़मीनों को बेचते हैं, उनको भी अपनी ज़मीनें बेचना पड़ेगा और केवल वही लोग जो खुद हाथ से खेती करते हैं अब कृषि कर सकेंगे । तो मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार के कानून बनाये जा रहे हैं, इस प्रकार के सुधार किये जा रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष नमूना हमारे सामने है उस वक्त— इन कानूनों को बनाते समय, इन कानूनों के बनने के बाद इन कानूनों की व्यवस्था को कायम रखने के लिये जो संशोधन संविधान में किया जाय उसके बारे में तनिक भी कोई शंका प्रकट करना मुनासिब नहीं है । मैंने देखा है कि जो पार्टियां इस प्रकार से गलत प्रचार करके कृषकों को धोका देती थीं या धोका दे रही थीं . . .

شری عبدالغنی : دھوکا لفظ بڑا سخت ہے۔

†[**श्री अब्दुल गनी** : धोका लफ्ज़ बड़ा सख्त है ।]

t[ ] Hindi transliteration.

श्री राम सहाय : मैं तो ऐसा समझता हूं कि मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है ।

. . . उनको यह बात मालूम हो गई है कि अब कृषक लोग इतने नासमझ नहीं रहे हैं कि वह उनके मुगालते में आ सकें ।

(Time bell rings)

चूंकि मेरा वक्त समाप्त हो गया है इसलिये मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

SHRI D. L. SEN GUPTA (West Bengal): Mr, Vice-Chairman, the Bill before this House really poses a challenge to the question whether we stand for reform or whether we allow the present status *quo* to be maintained. So far as our Constitution is concerned, we have promised social and economic equality. Unless there is reform, there cannot be any social or economic equality. It will remain there word for word without ever being implemented. So, we must vote for reform. Reform as it is must amount to a certain amount of reasonable restrictions on those who were so long having a field of exploitation unfettered by any law whatsoever. In the past when we talked of nationalisation of industries, it was really argued that we were curtailing somebody's Fundamental Rights. When it was tested in the court, what was the opinion of the Supreme Court and High Courts? Any reasonable restriction does not amount to curtailment of Fundamental Rights. So, whosoever was arguing for Fundamental Rights must remember that Fundamental Right is not a right to exploitation, is not a right to continue in a state as it was before. My colleagues here have expressed apprehension that if this amendment is passed, the peasantry might suffer. There are others also who swear in the name of the peasantry being benefited, that land must be distributed among the landless labour and land must come within the control of the State, and that is

[Shri D. L. Sen Gupta.] why this amendment is necessary. So, everybody is swearing in the name of the peasantry. Now, let us see where the land lies. It is certainly not in the hands of the peasantry, certainly in the hands of big zamindars. It is certainly in the hands of vested interests. So, land has got to be got from them and for that, reform is necessary. Unless we do that reform, those who are with thousands of acres of land in their hands will continue with that and those who are without land will also continue. Land cannot be produced out of nothing. Land has got to be distributed from the hands of those who possess it. That being the position we must take a realistic view.

What is there in this Bill? This Bill really promises land reform. Where land reform has been enacted by the State Legislature, by democratic vote, by a majority of the votes, those land legislations have got to be allowed to stand on the Statute Book. We talk of democratic rights. When I turn to clause 3, I find that from 21 to 64, all were passed by State Legislatures. The Resolutions are there. People's representatives there passed these Bills and these must obviously have been in the people's interests. Otherwise, they would have been voted out. People would have said: You have passed anti-people's legislation. So, these legislations are there and those legislations should take effect. If they cannot take effect for any technical reasons, the technical barriers must be removed. That is the purpose why from 21 to 64, they have been added.

So far as clause 2 is concerned, I find that this clause really provides for compensation at the market rate. It does not provide for taking over of land. I think in the interests of the peasantry, in the interests of the people, this provision should be there. Nobody wants that there should be taking of land without any compensation. It is stated there:

> "Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land compris ed therein is held by a person under his personal cultivation....."

If any land is taken by any State, then what is to be done?—

> ". . .it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof."

From my experience in the State Legislatures, I have seen that these legislations have been often misused. There is a danger. The danger is that I have seen zamindars having thousands of acres of land redistributing them among ten or more relations or friends either in their own name or in *binami.* So people are not getting advantage of that. The real disease lies in the Implementation of the legislation. Implementation and legislation are two different things. The mischief lies in the implementation of the legislation. But that should not hinder the passage of a legislation. That is one aspect.

The second thing is, what is fundamental right so far as land reforms are concerned? I do not claim to know every land tenure system everywhere, but the Permanent Settlement in West Bengal gave rise to the zamindari system, and the then British Government actually gave land to those who betrayed national interests. Those who served their imperialist interests were made zamindars. By fundamental right do we mean the fundamental right of" those people who were traitors to the

people's interests and who got zamindaries, and should they be maintained? Unless this legislation is there, possibly land reforms will not be possible, and unless land reforms are there people's interests will suffer.

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र (बिहार) :उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो कांस्टीट्यूशन का संशोधन बिल आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । स्वतन्त्र पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह बिल किसानों के मौलिक अधिकार पर आघात करता है । लेकिन मुझे उनको यह बतलाना है कि आप जरा समूचा संविधान देखिये, उसके प्रिएम्ब्ल में क्या है । उसके प्रिएम्ब्ल में यह है कि हम समाज के अन्दर सोशल जसटिस देंगे । सोशल जसटिस आप कैसे दे सकते हैं अगर आप समाज के साथ न्याय नहीं करेंगे । वैसे ही हमारे कांस्टीट्यूशन के जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिप्ल हैं उनमें साफ दिया हुआ है कि आप जमीन का बंटवारा करेंगे । हर राज्य को, हर स्टेट को यह निर्देश दिया गया है कि जमीन का ठीक तरह से बटवारा करेंगे । इसलिये यह संशोधन जो आया है यह उसी की पूर्ति के लिये आया है और यह पहला मौका नहीं है कि संविधान में संशोधन हो रहा है । यहां कहा गया है कि अमेरिका में २०० वर्ष में १७ या १८ संशोधन संविधान में किये जा चुके हैं लेकिन हमने अपने यहां १७ वर्ष में यह सत्रहवां संशोधन रखा है जिसको हम स्वीकार करने जा रहे हैं । अमेरिका में हर एक संशोधन में जनता को ज्यादा अधिकार दिया गया, लेकिन हमने अपने हर एक संशोधन में जनता का अधिकार घटाया है । आखिर जनता कौन है ? जनता मुट्ठी भर आदमी, जिसके पास सम्पत्ति ज्यादा है, वह नहीं है, हमारी जनता लाखों करोड़ों गरीब आदमियों की जनता है । तो हम किसकी भलाई करते हैं । हमारे संविधान में जो भी संशोधन जरूरी होता है, वह जनता की भलाई के लिये होता है । यह सही है कि जो थोड़े से पूंजीपति या थोड़े से जमींदार या बड़े बड़े किसान हैं उनको नुक्सान होगा । लेकिन जैसा कि कहा गया है, हमारे यहां ९२ प्रतिशत किसान हैं जिनके पास ५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, इस प्रकार कानून द्वारा यह सीलिंग कम से कम ९२ प्रति सैकड़ा किसानों के ऊपर नहीं लागू हो रही है । यह सही है कि विरोधी दल वाले जान बूझ कर, इसलिये कि कुछ विरोध करना है उसी दृष्टि से बातें करते हैं लेकिन अपने दिल जानते हैं कि संविधान के अंदर संशोधन करना ठीक है और यह जो संशोधन हो रहा है वह किसानों की भलाई के लिये है ।

एक ही बात मुझे कहनी है । अभी आज यह संशोधन आया है । इसमें प्रवर समिति ने जो एक बात का समावेश कर दिया कि पर्सनल कल्टीवेशन अगर कोई करेगा तो वह सीलिंग के अंदर हो और वह सीलिंग के अंदर की जमीन ली जायेगी तो उसका मुआवजा पूरा दिया जायेगा, बाजार की दर से दिया जायेगा । इसमें पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में कोई डेफिनीशन नहीं दी गई है । यह सही है कि किसान को बाजार दर पर मुआवजा देना चाहिये । लेकिन बिहार में, जिस राज्य से मैं आता हूं, वहां, पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में यह भी कहा गया है कि अगर वह हायर्ड लेबर से भी कोई खेती करावे उसको भी पर्सनल कल्टीवेशन कहा जायगा । डेफिनीशन में कहा गया है कि अपने आप या अपने परिवार वाले से या नौकर से या जो हायर्ड लेबर से भी खेती करायें तब भी उसको पर्सनल कल्टीवेशन कहा जायेगा, उनको वहां रहने की भी जरूरत नहीं है । वह पर्सनल कल्टीवेशन माना जायगा । इसलिये मैं समझता हूं कि प्रवर समिति को चाहिये था कि पर्सनल कल्टीवेशन के बारे

[श्री प्रतुल चन्द्र मित्र]

में और सफाई के साथ विचार रखती । हर एक अलग अलग राज्य अलग अलग पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन देता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में साफ तरीके से लिख दिया जाना उचित है कि वह पर्सनल कल्टीवेशन अपने या अपने परिवार वाले से खेती कराते हैं । हो सकता है कि किसी के पास २० एकड़ जमीन हो और कोई आदमी अकेले उतनी जमीन पर खेती नहीं कर सकता हो तो वह अपना हायर्ड लेबर रख सकता है । लेकिन कम से कम कुछ उनको खुद अपने आप भी करना होगा तब वह पर्सनल कल्टीवेशन कहा जायेगा । लेकिन जिस प्रकार से यह कानून बन रहा है उसमें यह चीज स्पष्ट नहीं की गई है ।

दूसरी बात यह है कि यह नाइन्थ शेड्यूल में जो आज हम लोग जोड़ रहे हैं और समझ लिया है कि यह तो शेड्यूल में कई एक कानून जोड़कर, जिससे कोर्ट का अधिकार नहीं रहेगा, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया । यह जितनी दूर तक किया जा रहा है वह सही है । लेकिन हमारे स्टेट में गवर्नमेंट में बदलाव होता है तो कानून भी बदलता है, मिनिस्टरी बदलती है तो कानून का ढर्रा भी बदलता है । पहले जो जमींदारी अबालिशन कानून हुआ उसमें यह था कि जिस दिन से वह बिल लाया गया, इन्ट्रोड्यूस किया गया उस दिन से अगर कोई भी अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी हस्तांतरण करे तो वह हस्तांतरण माना नही जायेगा ।

3 P.M.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

लेकिन लैंड-सीलिंग करके जो कानून पास हुआ उसमें ऐसा है कि कानून पास होने के बाद भी ६ महीने के भीतर जो चाहे बटवारा कर सकता है । इसके बाद भी जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ६ महीने का समय और ऐक्सटेण्ड कर दिया गया जिससे लोग अपने रिश्तेदारों को जमीन दे सकें और बटवारा कर सकें । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो ९वां शेड्यूल बढ़ाया जा रहा है, उसका नम्बर बढ़ाया जा रहा है, पीछे जैसे जैसे देश प्रोग्रेस करता रहेगा, उसी हिसाब से नम्बर और शेड्यूल बढ़ाना होगा । अभी जो होना चाहिये, जिस तरह से सीलिंग लगाई जानी चाहिये, जिस तरह का बंटवारा होना चाहिये, उन सब के लिये यह कानून बनाया जा रहा है ।

इसके साथ ही साथ मैं इस बात के लिये भी प्रवर समिति को धन्यवाद देता हूं कि बिहार का जो सीलिंग ऐक्ट था, जो कानून था, उसमें जो २८वीं धारा है उसको इस कानून के परव्यू से अलग कर दिया गया है । मैं इस बात का समर्थन करता हूं क्योंकि जिनके पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको १/२० हिस्से ले कर १/६ हिस्से तक सरकार को देना पड़ता । इस तरह से जो गरीब किसान जिसके पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिनको जमीन देने के लिये जबर्दस्ती की गई थी, कोर्ट उनके अधिकारों के बारे में इन्टरफियर करने से वंचित नहीं होंगे । इसलिये मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूं ।

श्री जगत नारायण (पंजाब) : डिप्टी चेयरमैन, महोदया, मैंने इस बिल पर ट्रेजरी बेन्चेज के मेम्बरों, स्वतन्त्र पार्टी के मेम्बरों और अपोजीशन मेम्बरों के नेताओं की तकरीरें सुनीं और बड़े गौर से पढ़ीं । इस सदन का कोई भी मेम्बर ऐसा नहीं हो सकता है जिसके दिल में किसानों के लिये हमदर्दी न हो या वह किसानों की बहबूदी नहीं चाहता हो । ट्रेजरी बेन्चेज से यह कहा गया है कि यह बिल किसानों की बहबूदी के लिये लाया गया है इसलिये इस सदन में संविधान में तरमीम किया जा रहा है । मगर जो लोग इसकी मुखालिफत करते

हैं उनके बहुत से खदशे हैं और सबसे बड़ा खदशा यह है कि कान्स्टीट्यूशन को अमेन्ड करके इस बिल को पास करने की कोशिश उन वोटों से की जा रही है जो या तो सरमायेदार हैं, लैण्ड लार्ड हैं, महारानी हैं या राजा महाराजा हैं। कल इसी हाउस में पंजाब की मेरी एक बहिन ने तकरीर की और उन्होंने यह कहा कि वह सोशलिज्म लाना चाहती हैं और वे सोशलिज्म के हक में हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है और वह यह है कि उनके पति को २५ लाख रुपया प्रीवी पर्स मिलता है। अगर आप राजपुरा से कार में बैठ कर पटियाला जायें तो ७ मील के फासले पर एक बड़ा फार्म मिलेगा जिसका ७ मुरब्बा मील रकबा है। उस फार्म में किसी का हिस्सा नहीं है और वह सिर्फ महाराजा पटियाला का फार्म है। फिर मेरी यह भी इत्तिला है कि महाराजा पटियाला ने अन्डमान में ४०० एकड़ जमीन ले ली है। महोदया, जो मेरी बहिन पर सोशलिज्म का प्रचार कर रही थीं, जो खदशे हैं वह यह है कि जिनके वोटों से वह बिल पास किया जायेगा वे कीमत मांगेंगे। कैसी कीमत मांगेंगे? मुझे याद है कि सच्चर वजारत ने जो ३० स्टण्डर्ड एकड़ मुकर्रर किया था उसका क्या हुआ। जो बड़े बड़े लैण्डलार्ड थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने क्या किया? जो बच्चा कल पैदा होने वाला था उसके नाम में भी ३० एकड़ जमीन लगा दी और इस ढंग से वे इस लेजिस्लेशन को खत्म करना चाहते हैं। जिस मुद्दा को सामने रख कर स्टैण्डर्ड एकड़ की हद मुकर्रर की गई है उसको भी खत्म करके रख देना चाहते हैं।

दूसरा उन्होंने यह किया कि जो गार्डन कालोनीज हैं तीन सौ, चार सौ, पांच सौ, एकड़ की उन जमीनों को ले लिया। अगर आप मेरे साथ जलन्धर चलें तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सरमायादार हैं उन्होंने गार्डन कालोनी के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें ले ली हैं दो सौ, तीन सौ, चार सौ एकड़ की और उनमें सिर्फ ५० या १०० दरख्त लगे हुए हैं। वे लोग उस जमीन में क्या करते हैं? वे लोग उस जमीन में आलू बीजते हैं क्योंकि यह कैस क्राप है और आपको वहां पर कोई फलदार दरख्त नजर नहीं आयेंगे। वे लोग इन जमीनों में आलू बीजते हैं और इस ढंग से किया कि जिन मजारों के लिए यह कानून बनाया गया था, यह लिमिट मुकर्रर की गई थी वे बेचारे बेबस हैं। आज उन्हें दो तिहाई हिस्सा मिलता है जबकि पहले वे आधा हिस्सा लेते थे बटाई का। मैं बड़े अदब से वजीर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि बेशक उनके दिल में किसानों की भलाई होगी, किसानों के लिए हमदर्दी होगी। मगर उनको यह याद रखना चाहिये कि जो खतरा है, जिन लोगों की वोटों से यह बिल पास किया जा रहा है क्योंकि आपकी दो तिहाई मेजारिटी है, वही लोग कल कानून को भंग करेंगे। वही आपके पास आयेंगे और कहेंगे कि इस ढंग से जमीन को रहने दो कि जो कानून आप पास करने जा रहे हैं वह उस पर लागू नहीं हो सकेगा।

दूसरा महोदया, बड़ा खदशा यह है खतरा यह है कि सूबाई सरकारों ने जो लिमिट तीस, बीस, दस एकड़ की अपने अपने सूबे में मुकर्रर की है उनको हुकूमत लेजिस्लेशन के जरिये यह करेगी कि दुसरे सूबे में कम है इसलिये हमारे सूबे में भी उतनी ही होनी चाहिये। अगर जाब में ३० एकड़ है और किसी दूसरे सूबे में २० एकड़ है तो १० स्टैन्डड एकड़ जमीन सरकार खुद ले लेगी। तो मैं समझता हूं कि वजीर महोदय जब जवाब दें तो इस बात का हाउस को यकीन दिलायेंगे कि सूबों में जो जो स्टेन्डर्ड एकड़ हद मुकर्रर की गई हैं, तमाम सूबों में इसके बारे में जो लेजिस्लेशन बने हुए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई तबदीली नहीं होगी।

[श्री जगत नारायण]

इसके अलावा तीसरा बड़ा खदशा यह है कि इस लेजिस्लेशन के पास होने के बाद सूबाई जो वजीर हैं, जो मुख्य मंत्री हैं वे वैनडिक्टिव होंगे । जो उनके मुखालिफ हैं, जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं, उनकी जमीनों को वह अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी। कोई कहेगा कि हमने फरीदाबाद में इन्डस्ट्रीयल टाउन बनाना है, कोई कहेगा कि ग्रेटर दिल्ली बनानी है, इसलिए गुड़गांव का हिस्सा आ जाए । जो लोग जमीन पर निर्भर करते हैं उनकी जमीन सरकार लेने की कोशिश करेगी जैसा कि पिछले दिनों हमारे मुख्य मंत्री जी के लड़के ने दरख्वास्त दी थी कि फरीदाबाद में स्पिनिंग और वीविंग मिल खोलने के लिए जमीन चाहिए । जो गरीब किसान फरीदाबाद में जमीन के जरिये अपनी रोटी खा रहे थे उनको उजाड़ दिया गया और डेढ़ लाख रुपये में उनकी जमीन खरीद ली गई और बन्दूक के जोर से उस पर कब्जा कर लिया गया। आज उस जमीन की कीमत पांच, छः लाख के करीब होगी लेकिन वहां पर अभी तक कोई वीविंग मिल और न किसी तरह की और मिल लगी है । तो इस ढंग से यह होगा कि वह वैनडिक्टिव होंगे । इस तरह का खदशा जो लोग उनकी मुखालिफत करते हैं उनके दिल में है ।

दूसरा खदशा उनका यह है, जैसा कि मैंने कहा कि जो जमीन ली जाती है उसका बहुत कम कम्पेनसेशन मिलता है । तो मैं वजीर महोदय से अर्ज करूंगा कि यह जो तीन चार बातें मैंने उनके सामने रखी हैं वे उनकी तरफ तवज्जो देंगे । जो सबसे बड़ा खदशा है, जो हमारी सूबाई सरकार है वह इस ढंग से चलती है कि कई दफा किसानों से जमीन ले लेती है और लीज में अपने दोस्तों और मित्रों को दे देती है । महोदया, कभी आप करनाल की तरफ जायेंगी तो आपको मालूम होगा १५,००० एकड़ जमीन जिसको काश्तकारों ने तोड़कर के ठीक किया था उसको लीज पर दे दिया गया । इस ढंग की जो बातें हैं, इस तरह के जो खदशे हैं, वे लोग जाहिर करते हैं और लेजिस्लेशन के जरिये आप इन खदशों को रखते हैं । मैं चाहूंगा कि वजीर साहब इन खदशों को सामने रखकर, इस हाउस में इस बिल के बारे में जब जवाब देंगे तो इन खदशों के बारे में भी अपने खयालात का इजहार करेंगे और क्या वाकई सच्चे दिल से गरीबों की मदद करना चाहते हैं ।

सब से अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो हमारा आईन है, यह बड़ा सैक्रेड डाक्युमेन्ट है । इसकी हम शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद इस हाउस के मेम्बर बन करके बैठते हैं । जितने वजीर हैं, जितने गवर्नर हैं, जितने जज हैं, वे सब इस आईन की शपथ लेते हैं । लेकिन इस आईन की तब्दीली जितनी जल्दी जल्दी में हो रही है, उससे बाहर के मुमालिक में हिन्दुस्तान एक मजाक का मजमून बन रहा है । आज सुप्रीम कोर्ट अगर एक फैसला कर देती है तो इस गवर्नमेन्ट को इतनी उजलत नहीं होनी चाहिये कि वह उसके मुताबिक फौरन ही आईन में तब्दीली कर दे । उसको जल्दी में आईन में तब्दीली नहीं करनी चाहिये । होता यह है कि इसी लैंड लेजिस्लेशन के सिलसिले में इस आईन में चार दफा तब्दीली की गई है । क्यों नहीं एक दफा आप बैठ करके और सोच करके तब्दीली कर लेते हैं । एक फैसला हुआ, फिर तब्दीली कर ली । दूसरा फैसला हुआ फिर तब्दीली कर ली । तीसरा फैसला हुआ, फिर तब्दीली कर ली । यह तरीका अच्छा नहीं है । इससे हमारी सरकार मजाक का मजमुन बनती है ।

बाकी मैं अपने कांग्रेस के भाइयों सेयहकहना चाहता हूं कि अगर वे यह समझते हैं कि यह सोशलिज्म इन महाराजा, महारानियों और सरदारों की वजह से यहां हिन्दुस्तान में ले आयगे, तो वे किसी गलतफहमी में बैठे

हुये हैं। ये राजे महाराजे तो दिन में चार दफा अपने लिबास तब्दील करते हैं। सुबह नाश्ते के वक्त इनका लिबास तब्दील होता है, लंच के वक्त तब्दील होता है, चाय के वक्त तब्दील होता है और फिर डिनर के वक्त तब्दील होता है। इनके पास एक एक लाख की कारें हैं। यही आपका सोशिलिज्म शायद लायेंगे ? इसके मुकाबले में आप जाइये देहातों में और देखिये कि वहां क्या हालत है। जहां ये दिन में चार दफा लिबास बदलते हैं और आज बड़ी ऊंची आवाज में यह कहते हैं कि हमें सोशलिस्ट स्टेट बनाना है, हम सोशलिस्ट स्टेट के हक में हैं, वहां आज हमारे देश में यह हालत है कि ऐसी हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके जिस्म पर सिर्फ एक कपड़ा है। जब उसको साफ करना होता है, तो वे पहले अपने घर का दरवाजा बन्द करती हैं और फिर उस कपड़े को साफ करती हैं। इसके अलावा अंग्रेजों के वक्त में सिर्फ बम्बई और कलकत्ता में लोग सड़कों पर सोते थे। आज दिल्ली और दूसरे मुकामात में भी लोग सड़कों पर सोते हैं। मेरी बहन को क्या मालूम होगा कि लोग किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनको एक रात सड़क पर सोना पड़े तो उनको पता लगे कि देश की हालत क्या है।

एक माननीय सदस्य : उनकी शराफ़त की क़द्र है।

श्री जगत नारायण : उनकी शराफ़त की क़द्र मैं भी करता हूं। लेकिन मैं सोशलिस्ट स्टेट की बात कर रहा हू।

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आपकी बसातत से जो मैंने सुझाव वजीर साहब की खिदमत में बयान किये, मैं यह चाहूंगा कि वे उनको अपने सामने रखें और उन पर गौर करते हुये और उनको स्वीकार करते हुये, फिर इस बिल को पेश करें।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I rise to support this measure, naturally, with certain reservations the reasons for which had been given by our colleague, Comrade Damodaran, in his speech and, also, what ye have to say in this connection was stated in the Note of Dissent submitted by two Members of our Party to the Joint Select Committee's report.

Madam, I support thia Bill because it removes certain obstacles in the way of implementing the agrarian reforms even of the Congress Government,—I say even of the Congress Government advisably because the agrarian reforms are not a_s yet what they should have been. They fall far short of the needs and the requirements of our economy in general and of our agriculture in particular.

It is understandable, Madam Deputy Chairman, for this measure to have been met with fierce opposition from the Swatantra Party and from Jan Sangh. What surprises us sometimes is that the leaders of the Swatantra Party, including the very wise ones amongst them, like Shri Rajaji, try to make out as if their opposition is based on their concern for the tiller of the soil. In fact, we have been told in this House and in the other House that this Bill is going to affect the rights of the cultivating peasants. Were it so, then we would have never supported this measure because we would like the interests of the cultivating peasants, be they rich, be they poor, or be they in the middle category, to be maintained. But they take the name of peasants because they dare not come out with the truth because this measure—if the Government will really like to use it—is going to hit the richer sections, the landlord class, the exploiting classes. Naturally, it is customary with the representatives or the political representatives of the exploiting classes to speak in the name of the exploited. That shows the moral weakness of the position of the parties like the , Swatantra Party and the Jan Sangh ' in such matters because they are not

[Shri Bhupesh Gupta.] in a position publicly to get up and plainly say that they are opposing this measure in the interests of the landlord class.

SHRI LOKANATH MISRA: May I have an elucidation? The esteemed leader of the Communist Party goes all out to respect the judgment of the Supreme Court when it affects his Communist friends in Jail, but when it affects the Fundamental Rights in the country, he goes against it. How does he reconcile the two positions?

SHRI BHUPESH GUPTA: Swatantra Party is at a discount in such matters . . .

SHRI LOKANATH MISRA: I think it is the Communist Party which is at a discount.

SHRI BHUPESH GUPTA: ... not for anything else but for political reasons. I will come to the Fundamental Rights. Let me dispose of the argument about the peasantry because lots of crocodile tears have been shed in this House and in the other House and it looked as though the House would be swept away by the crocodile tears that came in torrents, from the Swatantra Party. Therefore, I say let me dispose of the cjuestion'of peasantry first.

Madam, their argument has nothing to do with the interest of the peasantry. As far as Fundamental Rights are concerned, yes, Fundamental Rights, but Fundamental Rights for whom? The amendment does not take away the Fundamental Rights. They remain in the Constitution as they are. It only empowers the State in certain circumstances to enact certain legislation so that the Government and the vested interests, as I said, cannot obstruct social and progressive legislation if they are meant to be opposed.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Like preventive detention.

SHRI BHUPESH GUPTA: Now by preventive detention, he says.

SHRI LOKANATH MISRA: You are confusing the issue.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think the Swatantra Party should be in preventive detention, not physically I would like its politics to be quarantined in the country, isolated, exposed so that no one supports it. I would like Mr. Dahyabhai Patel minus his politics, but it is not a question of preventive detention. The Fundamental Rights, I say, remain as they are. All that is being sought to be done. Under certain circumstances-certain measures can be taken without any fear being there, without being frustrated by the vested interests who may take recourse to the courts of law.

Since the point has been raised about the Supreme Court, have we said any time that every judgement that comes from the Supreme Court is precious and we have to support it? No, we have never said that. Whatever is in the interest of the country and the people we support. Whatever goes in the interest of the vested interests and the exploiting classes we oppose, no matter where these things emanate from.

The Supreme Court is not a religious temple for us where we have to lie prostrate irrespective of what comes from there. That is our position. Our friends here do not seem to understand the Communist position at all.

SHRI LOKANATH MISRA: We know.

SHRI BHUPESH GUPTA: You also take the same view. When the Supreme Court judgement goes against the exploiting classes, shall we say, against the employer, you are against that judgement, but when the Supreme Court successfully gives a judgement against a social legislation or frustrates it like the land reforms,

you support the Supreme Court. You have a double standard.

SHRI LOKANATH MISRA: There has never been an occasion when we opposed a judgment of the Supreme Court.

SHRI BHUPESH GUPTA: Many times you have done it. Ask Mr. Masani, who seems to be a little more conversant with the subject, how many times you have done it. Well, I do not want to waste the time of the House by entering into politics at this stage, but let us not try to argue as if our friends here are the absolutely obedient disciples of the Supreme Court, are the worshippers, of the Supreme Court and we have become renegades of justice. This is not at all the position.

Now, the Supreme Court is meant to interpret the laws; our task is to pass the laws. Therefore, we are here to pass the law and then we shall leave it to the Supreme Court to understand it as they like, but the Supreme Court cannot arrogate to itself the task of legislation; it is our task; what would be in the interests of the country or not, is a matter for the Parliament of the country to decide; where it is a matter to be decided in the social, political and economic spheres of the country, the requisite legislative language certainly has to be found, and that is found here. After that it is for the courts of law to interpret them, when they are challenged or disputed. That is the position. Therefore, there is no conflict of loyalties in this matter between the vital limbs, between ourselves and the Supreme Court; we are functioning in our respective spheres leaving unto Caesar, the Supreme Court, the interpretation of law, assuming to yourself what belongs to you, namely the enactment of law. If we think that certain laws in the constitutional provisions are defective, are found wanting, it stands to reason that we in Parliament modify, change and amend them. There is nothing wrong in it. Therefore our Swatantra friends should kindly understand it. Their talk about the Fundamental Rights is all meaningless. Fundamental Rights for whom? To the exploiting classes who have lived for ages on the backs of the down-trodden peasant masses, persecuting them, harassing them, sucking their life blood white, and are we to give them Fundamental Rights? If we do, it would be a prostitution of Fundamental Rights in the name of Fundamental Rights. We are not for it.

Therefore, if the peasant masses were to stand on their own feet, if something has to be done in our agriculture with a view to ensuring development in agriculture, for the reorganisation of agriculture, we must be in a position to strike and strike hard against the vested interests of the landlord class, and this is a simple thing. You cannot run with the hare and hunt with the hound more especially in the sphere of social relations. You have given the choice on whose side you are. We have chosen—many, I believe, on that side have also chosen—and we are on the side of the tiller of the soil; we are against the landlord class; we do not make any secret about it. We want this class to be economically brought down to their knees. Politically they should be put in the right place. Socially they should be made a thing of the past. That is how we want to treat this class. This class must go out of our social and political scene if the peasantry were to be installed in the throne of the dignity of man—a simple proposition. It is no use trying to make out as if you are cosmopolitan in this matter, love everybody . . .

SHRI LOKANATH MISRA: We are with the tillers as well.

SHRI BHUPESH GUPTA: This is now 'as well'; he has come to the 'as well'.

SHRI LOKANATH MISRA: You said you are with the tiller; I said we are with the tiller as well.

SHRI BHUPESH GUPTA: Tell us which one you love most.

SHRI LOKANATH MISRA: The masses.

SHRI BHUPESH GUPTA: Then support this measure.

SHRI LOKANATH MISRA: But the policy is wrong.

SHRI BHUPESH GUPTA: Well, first of all you make up your mind. You cannot say that you love this young lady and run after another; you cannot; it cannot be. You must demonstrate by your action that what you profess is correct. But this is what you are doing.

SHRI LOKANATH MISRA: Your assumption is wrong; this policy is wrong.

SHRI BHUPESH GUPTA: Your ^demonstration gives me that idea. It is not an assumption; every time a Swatantra leader speaks, it is demonstrated before the country that the Swatantra leaders stand for blatant reaction, that the party is wedded to the past. It tries to hug the past in the name of the Constitution. It tries to hug the Fundamental Rights in order to deprive the peasant masses of these Fundamental Rights, of their desire to live as decent and honourable citizens of India, worthy of the name of this great country. Such has been their conception of these Fundamental Rights and we are not here for supporting that kind of Fundamental Rights. Hon. Members will have noted that never do they speak in the name of their real love, never the landlord class, the monopolist class, the princely class.

'To my amazement yesterday and to -my present surprise, yesterday a lady Member from that side, coming from an aristocratic class, spoke in support ->f this Bill. Let us accept that speech. Why make a personal attack on her? I know that she has to go a far longer way in order to live down the dismal feudal past, but let us applaud her when she makes a speech which accords with the present Bill and supports it. And why should the hon. Member opposite become so unchivalrous as to launch a personal attack?

SHRI LOKANATH MISRA: I think you are as sincere as she was in the interests of the tillers. Is it not?

SHRI BHUPESH GUPTA: Well, I am concerned with the policies, and this policy is a good policy although it has some defect. Well, the Swatantra Leader, speaking about the peasant, reminds me of some Minister in Switzerland speaking about the navy, or Hitler speaking about justice.

SHRI S. S. MARISWAMY: I strongly object to this remark when the Leader is not there and further, Sir, he had never opposed land reforms or peasant class as such. He always stood by the peasants of India.

SHRI BHUPESH GUPTA; I am very glad. How can he oppose the peasant class as such, with their votes obtained through deceit you have to be returned to Parliament? How can you oppose it? You combine demagogy with deceit in order to wangle the Swatantra Party and then, with the votes secured, to oppose the Constitution.

SHRI LOKANATH MISRA: The Communist Party excels all others in the world in demagogy and deceit, and if that brought in votes, you would have been there in power.

SHRI BHUPESH GUPTA: You see who is speaking for the peasantry here. I am very glad to hear. . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Are you speaking for China or Russia? Tell us.

SHRI BHUPESH GUPTA: China or Russia?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: You make up your mind about it and tell us.

SHRI DEPUTY CHAIRMAN: You hardly have a couple of minutes more.

SHRI BHUPESH GUPTA: China or Russia, what has it got to do with this Bill?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Because your interests are not here but elsewhere.

SHRI BHUPESH GUPTA; I know]] you will make irrelevant observations, J because you are in a tight corner.

Now here, Madam Deputy Chairman, our agriculture is in a state of semi-stagnation. Now I criticise the Congress Party—I have done my part with this side. The Congress Government has exhibited tardiness in the matter of land reform. It has spoken a lot, and it has made so many declarations, and so on, but when it comes to action, it is faltering and faltering very badly. Many of the land legislations are partial and defective with plenty of loopholes and, what is more, in their implementation, they have given ample opportunities to the landlord class in order to evade even the existing law—I do not want to go into this story—as a result of which these enactments which are there already could not be properly implemented, and the peasantry suffer thereby. We find that even today only three per cent, of the rural households own between them thirty per cent, of the total cultivated area. That only shows the concentration of land in the hands of a few, a handful of upper strata in the society, in the rural agricultural society. At the other end we find huge masses of the peasantry, the agricultural labourers, the poor peasants, between them holding a very little proportion of the total land; a little less than the same amount of land is held by eighty-five per cent of the people. Such is the position.

Therefore, you see in the countryside today that despite legislation we have landless peasants, agricultural labourers, poor peasant^, a kind of situation which should have been overcome long ago. And this has resulted in unemployment and under-employment in the rural areas, leading to stagnation in our agriculture— if you like, semi-stagnation. Our food front is not looking up, we all know and we (have to modify our Plan targets. And if we go deeper into the matter we will find that the root of all our trouble and the cause of our food deficit lies in the agrarian relations, in a situation in which the exploiting classes have the preponderance over the exploited classes. That is the position. Therefore our requirement is radical agrarian reform which will give the land to the tiller of the soil and make the tiller the owner of the land. That is the crux of the matter.

Naturally, we cannot solve the food problem unless we come to grips with this vital and crucial problem of agrarian relations. Have courage and make amends. If anything had gone wrong, have the courage now to come and correct it and pass the necessary legislation, and what is more, implement the legislation so that you really make the tiller of the soil the owner of the land. That will break the concentration of wealth in the rural areas. Otherwise agriculture cannot turn the corner and that is absolutely clear today. All the economists have spoken in this way. The Planning Commission in its various reports have pointed this out and drawn attention to the drawbacks and shortcomings in our agriculture. The Land Reforms Committee, appointed by the Government under the Planning Commission, has come to the same conclusion. But because of the pull of the landed vested interests on the State Governments, and their pull on the State apparatus and their

[Shri Bhupesh Gupta.] collusion with the administrative machinery, we find nothing is being done effectively in order to improve the situation and that is what we object to very much today.

Therefore, whereas we should be thinking of passing comprehensive agrarian legislation amending the existing one in a proper direction, we have here the spectacle of some Members of Parliament opposing even this limited improvement, in the name of the Fundamental Rights. Every time reaction has spoken in every country in all historic situations in the name of democracy and in the name of fundamental rights, only to trample under foot the very conception of fundamental rights and the conception of democracy. That is what is happening and it is not going to be an exception in our country. You see immediately after the Prime Minister's tragic demise, the hon. Member Shri Dahyabhai Patel spoke here on the Condolence Resolution and he did not forget to demand that this House should be adjourned without passing what he called a controversial measure. Therefore, he showed his class consciousness, class consciousness from the point of view of reaction, Death of the Prime Minister or no death, he must hold the banner of the Swatantra Party aloft, That is the idea that he cherishes, as if the Prime Minister in his will said that we should not pass this measure,

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I strongly object to this interpretation of what I said. I said that this was a shock to the country, that the Cabinet had received a shock. Let us recover from it. Don't you see that the shock is there and the Cabinet has not yet recovered from it? Therefore, I am fully justified in what I said. If I wanted to say anything against the measure, I know when to say it and where to say it; and Mr. Bhupesh Gupta need not twist my words.

SHRI BHUPESH GUPTA: I will be very sorry if I twisted them.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: You have.

SHRI BHUPESH GUPTA: Now I understand that he made that suggestion to heip the Cabinet to recover from the shock. What great concern for the Cabinet it represents, what kindly affection it shows on his part.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: What a perverted mind you have.

SHRI BHUPESH GUPTA: You may call it perverted mind. But don't you think that we are a little too> grown up to accept your logic and such argument of yours, when you say that you are so much concerned about the shock received by the friends on the Cabinet?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I just made a suggestion.

SHKt BHUPESH GUPTA: Yes, it was just a suggestion. I agree it is a suggestion and therefore it is no remedy for shocks.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up Mr. Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: These light interruptions are there. Anyway, I am very s°rry my friend Mr. Patel should have misunderstood roe.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I understand you thoroughly. I am only trying to help other people to understand you better.

SHRI BHUPESH GUPTA: Do you think that these people have now understood me in the way you want them to understand me? Well, one of the drawbacks of the Swatantra Party is that they have several illusions, that they suffer from illusions. One of their illusions is that some day they will come and *(pointing to Treasury Benches)* sit here, antf here is another illusion of my hon. friend here that the people will understand me just as he wants them to. That

will not" materialise. Now, I must finish my speech, as the Deputy Chairman has asked me to do.

Therefore, Madam, we support this measure. But when we support it we make it very clear that we are not happy about what has happened. What we fear now is that with a big man, a powerful man gone from the scene, without his weight and authority and prestige and his influence and his leadership, there will be more effective and intensive effort from the side of reaction—whether they are entrenched here openly or hidden there under different guises—and they will build up pressure so that this measure is not passed. Therefore, the need is even greater now for vigilance and 1 think it is a good thing that we today will be dispersing after enacting this legislation. That is cne way in which we can tell the country as a whole: Well, unfortunately, the Prime Minister has gone, but his good ideas will be carried forward, if necessary with tears in our eyes, while mourning his death. That is how we should project ourselves to the country. That is how I feel today when we are passing this measure. But 1 only hope that this Government will consider with greater vigour, with greater foresight and with the requisite seriousness the' need for agrarian reforms of the kind that we want. We need modifications and amendments in a much more radical direction. We must create a situation when we can get up in Parliament and tell ourselves and the country that we have a legislation which gives land to the tiller of the soil, make the tiller the owner of the land, the master of the land. That is the true way to protect our country and the honour of the country. That is the true way to strengthen our independence and that is the true way to make it possible for the country's industrialisation to go apace. It is by such land reform that we oan remedy the social disparities more than by anything else and it is through making the peasants masters of the land that we can make the people masters of the country, and it is by making the peasant feel that he is the true owner and creater of his own wealth that we can generate a new spirit and outlook and democratise the country, and bring in social justice, as stated in the Preamble of the Constitution. That is the first thing in our Constitution that we have given to ourselves and to the country and that has to be translated and implemented not in sentimental words and expressions, nor merely in Bhubaneswar resolutions or in occasional speeches at the A. I. C. C. meetings, but in the practical life, and above all. as far as the Government is concerned, in the formulation and implementation of the democratic popular policies. Thank you.

SHRI A. K. SEN: Madam Deputv Chairman, may I start by congratulating Mr. Bhupesh Gupta on his fine and brilliant speech this afternoon? This is one of his best that I have heard and the rare humour which he has exhibited today. I hope, will continue to enliven his speeches in the years to come on the floor of this House.

He has questioned us about the loyalty we should bear to one love and also to one principle. I entirely agree with him. I do not know how far our friends *on* the other side would gree with many of the observations he has made. I am constrained to agree with him and I feel that much of the opposition that has come against this Bill in the name of the independence of the judiciary or loyalty to judicial pronouncements, the infallibility of the. provisions of the Constitution, the undesirability of amending the Constitution ever so often. ᵛave sprung from one desire, namely, to stail progress in the field of land reform in our economic life. I was so surprised when Mr Gupta said—in fact dr; the very words from my mouth—that the role of the judiciary as we conceive it in our Constitution, is not to laᵧ down policies of State action. How true it is. I hope this is realised not only by the Swatantra Party but by all

[Shri A. K. Sen.] of us when we come up against uninformed criticism of State action whenever that State action takes a course which is contrary to judicial pronouncement. The Judges interpret the law as we have passed them. They interpret the Constitution as it reads with the words employed. They **are** not concerned with the policies; nor are they concerned with laying down norms of State behaviour. It is not their function. They only tell us how far State action would be authorised within the bounds of law as it exists today. If those bounds become inconvenient and stall State policies which we have accepted as our norms, it will be for the competent legislatures to make such changes in the law as they consider necessary.

SHRI LOKANATH MISRA: Then why not make everything non-justiciable?

SHRI A. K. SEN: As it is, even the new law will be justiciable. I am afraid the hon. Member has not quite appreciated the point I am making; nor have I the time at my disposal to explain to him in detail what I wanted to say. When we change our laws with a view to enabling us to pass such legislation as would become necessary to give effect to our State policies, it casts no aspersion on the judiciary. It will be the privilege of the judiciary to pronounce upon the validity or otherwise of the laws that we pass and it will be our duty to follow such pronouncements as and when they are made. Therefore, I do not see how it is relevant at all to talk of the independence of the judiciary or of the high pedestal on which we have put our courts. In my submission, there is a good deal of substance in the criticism levelled by Mr. Gupta that these are for the purpose of camouflaging the real opposition which lies elsewhere, which springs from other motives.

Then, Madam, it has been said that the Constitution is inviolable; it should not be changed as if the Constitution is more important than the life which it serves to sustain, the fulness of life which it seeks to bring about and the streams of benefit which it seeks to extend to those who have been denied the fruits of the Constitution and its benefits for centuries past. It is true that in implementing our laws of land reform there have been omissions here and there. It may be that the enforcement has not been as vigorous as it should be. Nevertheless the measures, as they have passed out of the different State legislatures, follow one pattern which has been prescribed on an all-India basis and which has been arrived at after mature thinking and after a good deal of deliberation by experts who had been helping the Planning Commission. This pattern has been followed in every State. It is only in some States that difficulties have occurred, like Madras, Gujarat, Maharashtra and so on. In other States the land reforms have been fully implemented. How far some big peasants or some big landlords have evaded the provisions of the law relating to ceilings is a different matter but the implementation in most of the States has been completed. Some States have been facing difficulties because of traditions relating to estates and other matters with which I dealt when I introduced the motion originally. It is therefore our endeavour to remove all obstacles whatever may be the difficulties and it is no use trying to condemn our efforts on the ground that we are trying to expropriate land from the peasants. I do not know how it follows though it is of course a good thing to say so because the real opposition if expressed candidly would condemn those who would be opposing this measure. Therefore they have to adopt some other thing, some principle, for the purpose of showing the nobleness of the opposition which is being put forward to this Bill. How is this, Madam, a measure to expropriate the peasant? I fail to see; on the contrary, for the first time this Bill seeks to graft a provision in the Constitution itself—while there was none before—which protects the small tenant from being deprived

of his land so long as it falls within the ceiling, except on payment of full compensation, full market value. I hope hon. Members belonging to Mr. Dahyabhai Patel's party ponder for a moment about the effectiveness of this safeguard.

SHEr DAHYABHAI V. PATEL: Is the compensation justiciable?

SHRI A. K. SEN: Yes; so far as the market value is concerned, certainly. Not only that; it will be appealable right up to the highest tribunal.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: It is not clear; it is delightfully vague.

SHRI A. K. SEN: It is vague because the Constitution does not provide for the machinery of compensation. It will be for the different State legislatures to frame relevant laws providing for compensation.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Don't you know how our State Legislatures are going?

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): Is it not a fact that market value is justiciable?

SHRI A. K. SEN: Of course, yes. In my respectful submission, this Bill only seeks to remove certain disabilities but does not prescribe measures of land reform in the different States. Land being a State subject, it will be for the different States to frame their own measures. If ever any State wants to take over land falling under the ceiling, it will be absolutely necessary for that State to prescribe payment of market value as compensation and it will be then for the courts also to decide in particular cases whether in fact market value has been given or not. This should clear all reasonable doubts and in my submission, Madam, this constitutional safeguard would always be hailed by the small man; but it is true that the big landlords would be a little upset because this Bill at the same time removes all disabilities in **the** way of State Legislatures to initiate vigorous schemes of land reform touching huge *ryotwari* holdings of landlords and also other holdings which unfortunately due to technical objections today are not comprehended, but for this new amendment, within the meaning of the word 'estate.' Thi$_s$ is a point . . .

SHRI GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA (Madhya Pradesh): Big landlords are wise enough; they have already brought their land within the ceilings.

SHRI A. K. SEN: That does not take away from the validity of the measure itself. As I said there is *no* use *trying* to confuse issues. This is not a Bill to expropriate; this is not $_a$ Bill to set the pattern for land reforms legislation. This is a Bill to remove those disabilities which are confronted by the State Legislatures in enforcing and initiating vigorous and standard forms of land reform legislation which have been accepted as our norms on an all-India basis. These are all my submissions, Madam.

Srar BHUPESH GUPTA: On a point of clarification. With regard to the new proviso that you are adding under clause 2—I would ask the Law Minister to kindly follow it—I want $_a$ point to be clarified so that there is no confusion. I have been informed by one of our leading comrades in Andhra, Comrade Rajeshwar Rao, that the Swatantra Party is telling there in Andhra Pradesh that the small peasant will have no remedy to go to court even.if his land is taken away. Do I understand here that if land is acquired within the limits of the ceiling, the peasant can go to the court of law on the ground that he has not been paid adequate compensation or the market value?

SHRI A. K. SEN: Yes.

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, I understand that this will make it open to the peasant to go to the court ., and challenge if he feels that it shfT'^d

[Shri Bhupesh Gupta.j be challenged, that the market value has not been paid *lor* the land which has been acquired from him. That point should be made clear.

SHRI A. K. SEN: It is precisely so; because it limits the power of any State Legislature to acquire land within the ceiling, except on payment of market value. That means there can be no valid State legislation without providing for payment compensation the full market value when they seek to acquire land falling within the ceiling.

Even if that is done, it will be invalid, lit will be challengeable even in a Munsiff's Court.

ISHRI BHUPESH GUPTA: So, he can go to a court of law on that ground.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has been very clear.

SHUT BHUPESH GUPTA: Let the Minister say it. It is very important.

SHRI A. K. SEN: I have said it several times that it is precisely so.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes— 174; Noes—9.

AYES—174

Abdul Samad, Shri A. K. A. Abdul Sh'akoor, Moulana Abid Ali, Shri Abraham, Shri P. Ahmad, Shri Syed Ammanna Raja, Sh aati C.
Anandan, Shri T. V.
Anis Kidwai, Shrimati Annapuma Devi
Thifmmareddy, Shrimati
Anwar, Shri N. M.
Ai'ora, Shri Arjun
Asthana, Shri L. D.
Atwal, Shri Surjit Singh
Baharul Islam, Shri
Bansi Lai, Shri
Barooah, Shri Lila Dhar
Bedavati Buragohain, Shrimati
Bhargava, Shri B. N.
Bhargava, Shri M. P.
Bhuwalka, Shri R. K.
Bobdey, Shri S. B.
Chagla, Shri M. C.
Ch-aman Lall, D.'..-.
Chandra Shekhar, Shri
Chandrasekhar. Dr. S.
Chatter ji, Shri J. C.
Chavda, Shri K. S.
Chengalvaroyan, Shri T.
Chetia, Shri P.
Chinai, Shri Babubhai M.
Damodaran, Shri K.
Das, Shri L. N. Das, Shri
N. K. Dasgupta, Shri T. M.
Dass, Shri Mahabir Deb,
Shri S. C.
Deokirijandlan Narayan, Shri
Desai, Shri Khandubhai K. Desai,
Shri Suresh J. Devaki. Gopidas,
Shrimati Dharia, Shri M. M. Dikshit,
Shri Umashankar Diwakar, Shri R.
R. Doogar, Shri R. S. Dutt, Shri
Krishan Gaikwad, Shri B. K.
Ghosh, Shri Niren Ghosh, Shri
Sudhir Gilbert, Shri A. C. Gujral,
Shri I. K. Gupta, Shri Bhupesh
Gupta, Shri Gurudev
C.unpada Swamy, Shri M. S.
Hathi, Shri Jaisukhlal
Iyer, Shri N. Ramakrishna
Jahanara Jaipal Singh, Shrimati
Jairamdas Daulatram, Shri
Joshi, Shri J. H.
Kakati, Shri R. N.

Karmarkar, Shri D. P.
Kathju. Shri P. N.
Khan, Shri Akbar Ali
Khan', Shri M. Ajrr.al
Khandekar, Shri R. S.
Kothari. Shri Shantil-al
Koya, Shri Pal-at Kunhi
Kulkarni, Shri B. T.
Kumaran, Shri P. K.
Kumbha Ram, Shri
Kurre, Shri Dayaldas
Lai, Prof. M. B.
Mahanti, Shri B. K.
Mallik, Shri D. C.
Malviya, Shri Ratanlal Kishorilal
M-ani, Shri A. D.
Maniben Vallabhbhai Patel, Kuman
Mary Naidu, Miss
Mathen, Shri Joseph
Mehta. Shri M. M.
Meht-a, Shri Om
Mir, Shri G. M.
Mishra, Shri L. N.
Mishra, Shri S. N.
Misra, Shri M.
Mitra, Shri P. C.
Mohammad, Chaudhary A.
Mohinder Kaur, Shrimati
Moideen, Shri M. J. J-
Momin, Shri G. H. Valimohmed
Muhammad Ishaque, Shri
Naflsul Hasan, Shri
Nagpure, Shri V. T.
Ntair Shri C. K. Govindan
Nair Shri M. N. Govindan
Nandini Satpathy, Shrimati
Nanjundaiya; Shri B. C
Narasimha Rao, Dr. K. L.
Neki Ram, Shri
Pande, Shri C. D.
Pand- Shri T.
Panjhazari, Sardar Raghbir Singh
Parthasarathy, Prof. (Mrs.) G.
Pathak, Shri G. S-
Patil, Shri P. S.
Patra, Shri N.
Fattabirsjnan, Shri T. S.
Pawar, Shri D. Y.
Phulrenu Guha, Dr. Shrimati
Pillai, Shri J- S.
Poonacha, Shri C. M.
Prasad, Prof. B. N.
Punnaiah, Shri Kota
Puttappa, Shri Patil
Rajagopalan, Shri G.
•Ramachandran, Shri G.
Ramaswamy, Shri K. S.
Ramaul, Shri Shiva Nand
Rao, Shri B. Ramakrishna
Rao, Shri V. C. Kesava
Ray, Dr. Nihar Ranjan
Ray, Shri Ramprasanna
Reddy, Shri M. Govinda
Reddy, Shri N. Narotham
Reddy' Shri N. Sri Rama
SadiqAli, Shri
Sahai Shri Ram
Sait, Shri Ibrahim Sulaiman
Sanjivayya, Shri D.
Sapru, Shri P. N.
Satyanarayana, Shri M.
Savnekar, Shri Baba Saheb
Seeta Yudhvir, Shrimati
Sethi, Shri P. C.
Shah, Shri K. K.
Shah, Shri M. C.
Shakuntala Paranjpye, Shrimati
Shanta Vasisht, Kumari
Sharda Bhargava, Shrimati
Shai-ma, Shri L. Lalit Madhob
Sherkhan, Shri
Shervani, Shri M. R-
Shukla, Shri M. P.
Shyam Kumari Khan, Shrimati
Siddhu, Dr. M. ML S.
Singh, Dr. Anup
Singh, Thakur Bhanu Pratap
Singh Dr. Gopal.
Singh, Shri Jogendra
Singh, Shri Mohan
Singh, Shri Santokh
Sinha, Shri B. K. P.
Sinha, Shri Ganga Sharan
Sinha, Shri R. B.
Sinha Shri Rajendra Pratap
Sinha, Shri R. P. N.
Sur, Shri M. M.
Syed Mahmud, Shri
Tankha. Pandit S. S. N.
Tapase, Shri G- D.
Tara Chand, Dr.
.Tara Ramchandra Sathe, Shrimati
Tariq, Shri A. M.
Thanglura, Shri A.
Tiwary, Pt. Bhawaniprasad
Tripathi, Shri H. V.
Varma, Shri B. B.
Vai-ma, Shri C. L.
Vasan, Shri S- S.
Venkatappa, Shri J-
Venkateswara Rao, Shri JN.
I Vero, Shri M.

Vijaivargiya, Shri Gopikrishna
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Zaidi, Col. B. H.

NOES—9

Abdul Ghani, Shri Mariswamy, Shri S. S. Misra, Shri Lokanath Oberoi, Shri M. S. Patel, Shri Dahyabhai V. Patel. Shri S. M. Ruthnaswamy, Shri M. Singh, Shri J. K. P. N. Singh, Shri S. P.

The motion was adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill. There are two amendments. Amendment No. 1 is in the name of Mr. D. B. Desai. He is not here. Amendment No. 2 is in the name of Mr. Damodaran.

Clause 2—*Amendment of article* 31A

SHRI K. DAMODARAN (Kerala): Madam, I move:

2. "That at page 1, line 11, after the words 'personal cultivation' the words 'that is, cultivation by him or by any member of his family' be inserted."

The question was proposed.

SHKI K. DAMODARAN: The object is very simple. If the Minister stands for what he has said, that is, in the interests of the tiller and not the landlord, I think he will not have any objection to accept this amendment.

SHRI A. K. SEN: If I may say *so,* his amendment would cut down the scope of personal cultivation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish what he has to say.

SHRI K. DAMODARAN: Here the words *personal cultivation' may mean anything. It may mean personal cultivation of, land owned by the landlord. I want to make it clear that market value may be given as compensation only to the tiller. Only when land is acquired from some people 4 P.M. when it is personally cultivated—which also includes cultivation by any member of his family and not by anybody who does not cultivate, who is not supposed to be the owner or the landlord of that land—only when land is taken from those who personally cultivate, then only this clause which has been added and brought here should be applicable. I think the Minister himself will accept it.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, I do not wish to say on that point. I think the hon. Minister has explained the position, but I speak on clause 2 in order to afford an opportunity to the Government to clarify the position, and I consider it necessary in the interests of all those who stand for this measure to bring it to the notice of the House and seek a clarification precisely on this point. When this measure was known to the country, a propaganda was started that the small peasant, after this proviso is added, after the amending law is passed, would have no right whatsoever to go to the court at all when certain land is acquired from him. This propaganda was specially carried on in Andhra Pradesh, as I mentioned before, and certainly some peasants were confused. But after all, we are all interested in the peasants of our land. If I understand it correctly, after this proviso is added to our Constitution, according to me—and the Law Mirister will correct me if I am wrong—if any State passes an Act which does not provide for compensation at the rate of the market value for land acquired from a peasant within the limits of the ceiling, it would be open to him to challenge that law, that State legisla-

tion, in the High Court or the Supreme Court as a breach of Fundamental Right. This is what I understand from it. Therefore, the peasant in genuine cases will get the right to challenge it as a breach of Fundamental Right should a State legislation be found to violate the requirements of this proviso namely, that it does not provide for any adequate compensation at the rate of the market value.

The second point is suppose a State passes a legislation which provides for a scale of compensation—it will be in monetary terms or other terms—and suppose I find that land has been taken by the Government and the legislation which provides for compensation ie not really giving me the compensation at the market value, is it open to me to go to the court of lav/? I thought that it was open to me and he said that I could go to the court of law to point out that I had not been given the compensation which the State should give under the terms of the Constitution or which the measure should give. Therefore, I have two remedies open to me: firstly, I can challenge the legislation as such as a breach of Fundamental Right under the Constitution in the High Court or the Supreme Court and, secondly, I can go to the court of law when I think I have not been given compensation at the market value. There will be an objective test for it in order t6 get the remedy and I can move the court so that I am given compensation at he market value. This position should be made clear so that there need be no confusion about it because we want the co-operation of the peasants in such matters and there should not be any room for misunderstanding on the part of the peasants.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: May 1 ask another explanation bearing on the same point? The Law Minister said that land taken within the ceiling would be paid the market value and that a peasant would have the right to go to court if he was aggrieved. May I know what ceiling it is? Is it the ceiling as it exists under the different State laws today or is it a variable ceiling that exists at the sweet will and pleasure of the Chief Minister of each State Government? Will the Law Minister kindly explain?

SHRI A. K. SEN: Madam Deputy Chairman, may I take the amendment moved by Mr. Damodaran first[7] His amendment would cut down the scope of personal cultivation. Personal julti-vation not only includes cultivation by members of one's family but also by servants and labour hired or paid by a person so long as the cultivation is under his supervision. What he seeks to do would be to cut down the scope of personal cultivation. We have taken a good deal of care to define what personal cultivation is. A man who has 50 acres can employ 50 labourers. That would be prevented.

SHRI K. DAMODARAN: That is the purpose of the amendment.

SHRI A. K. SEN: Madam we are not in favour of it because the Planning Commission has prescribed the definition for personal cultivation because it is not always possible for a man to do all the manual operation himself. He has to employ hired labour. So long as it is done under his supervision, it will be personal cultivation. Therefore, all the State laws define personal cultivation as cultivation by one's own labour, labour of his family, and also labour of his servants and hired labour under his supervision. Otherwise a minor will not be able to cultivate if he cannot employ servants and so on, or a widow or a female would not be able to cultivate. Therefore, it will cause hardship and particularly operate on such persons adversely. Therefore we cannot accept this amendment. It is an all-Iridia pattern which is followed by all State laws.

Then, Madam, I thought I was quite clear when I told Mr. Bhupesh Gupta that those St3te laws would be invalid if they seek to acquire any land falling within the ceiling prescribed by State Legislatures by valid laws by them, unless they provide for payment

[Shri A. K. Sen.] Of compensation at market value. If any such law is unwisely pajfed by a State Legislature—I cannot Conceive ■ it would be because each State Government has its own legal advisers, but should there be such an unwise and improbable contingency—I have no doubt that the courts will strike it down immediately, and any person whose land is sought to be acquired under such an invalid law would have remedy in any civil court of the country, and even the criminal court would be available in order to prevent trespassers coming in the name of acquisition.

Mr. Patel's query as to -whether it is the ceiling fixed by the Chief Minister of the State Government, I think, is rather a very rash statement. How can Chief Ministers of Governments fix . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I a_m (sure the Law Minister understands my point. He is trying to misrepresent me. I asked whether it is the ceiling prevailing today or which may be variable according to the will of the Chief Minister of a State. That is what I a?ked. Is it the ceiling prevailing today?

(Interruptions) SHRI A. K. SEN: Ceiling as fixed by. competent State Legislatures. That being a State subject, only competent State Legislatures can fix a ceiling.

THC DEPUTY CHAIRMAN: I will now put the amendment (No. 2) to vote The question is:

2. "That at page 1. line lL afler the words 'personal cultivation[1] the words 'that is_i cultivation by him or by any member of his family' be inserted.""

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The •question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes—177; Noes—9.

AYES—177 Abdul Samad, Shri A. K. A. Abdul Shakoor, Moulana Abid Ali, Shri Abraham, Shri P. Ahmad, Shri Syed Ammanna Raja, Shrimati C. Anandan, Shri T. V. Anis Kidwai, Shrimati Annapurna Devi Thimmareddy, Shrimati Anwar, Shri N. M. Arora, Shri Arjun Arthana, Shri L. D. Atwal, Shri Surjit Singh Baghel, Shri K. C. Bahavul Islam, Shri Bansi Lai, Shri Barooah, Shri Lila Dhar Bedavati Buragohain, Shrimati Bhargava, Shri B. N. Bhargava, Shri M. P. Bhuwalka, Shri R. K. Bobdey, Shri S- B. Chaman Lall, Diwan Chandra Shekhar, Shri Chandrasekhar, Dr. S. Chatterji, Shri' J. C. Chavda, Shri K. S. Chengalvaroyan, Shri T. C- Ua. Shri P. Chinai, Shri Babubhai M. Damodaran, Shri K. Das, Shri L. N. Das, Shri N. K. Dasgupta, Shri T. M. Dass, Shri Mahabir Deb, Shri S. C. Deokinandan Narayan, Shri Desai, Shri D. B. Desai, Shri Khandubhai K. Desai, Shri Suresh J. Dovaki Gopidas, Shrimati Dharia, Shri M. M. Dikshit, Shri Umashankar Diwakar, Shri R. R. Doogar, Shri R. S. Dutt, Shri Krishan Gaikwad, Shri B. K. Ghosh, Shri Niren Ghosh, Shri Sudhir Gilbert, Shri A. C.

Gujral, Shri I. K.
Gupta, Shri Bhupesh
Gupta, Shri Gurudev
Gurupada Swumy, Shri M. S.
'Hathi, Shi-' Jaisukhlai
Iyer, Shri N, Ramakrishna
Jaha'nara Jaipal Singh. Shrimati
Jairamdas Daulatram, Shri
Joshi, Shri J. H.
Kakati, Shri R. N.
Karm-arkar, Shri D. P.
Kathju, Shri P. N.
Khan, Shri Akbar Ali
Khan', Shri M. Ajmal
Khandekar, Shri R. S.
Kothari, Shri Shantil-al
Koya, Shri Palat Kunhi
Kulkarni, Shri B. T.
Kumaran. Shri P. K.
Kumbha Ram, Shri
Kurre, Shri Dayaldas
Lai, Prof. M. B.
Mahanti. Shri B. K.
Mallik, Shri D. C.
Malviya, Shri Ratanal Kishonlai
M-jni, Shri A. D.
Maniben Valiab-hbhai Patel, Kumari
Mary Naidu, Miss
Mathwi, Shri Joseph
Mehta, Shri M. M.
Mehta, Shri Om
Mir, Shri G. M.
Mishra, Shri L. N.
IvJishra, Shri S. N.
Misra, Shri M.
Mitra, Shri P. C.
Mohammad, Chaudhaiy A.
Mohinder Kaur, Shrimati
Moideen, Shri M. J. *3.*
Momin, Shri G. H. Valimohmed
Muhammad Ishaque, Shri
Nafisul Hasan, Shri
Nagpure, Shri V. T.
N-air, Shri C. K. Govindan
Nair, Shri M. N. Govindan
Nandini Satpathy, Shrimati
Nanjundaiya, Shri B. C.
Narasimha Rao, Dr. K. L.
Neki Ram, Shri
Pande, Shri C. D.
Pande. Shri T.
PanjhazarL Sardar Raghbir Singh
Parthasarathy. Prof. (Mrs.) G.
Pathak. Shri G. S.
Patil, Shri P. S.
Patil, Shri U. S.
Patra, Shri N. Pattabiraman, Shri T.
S. Pawar. Shri D. Y. Phulrenu Guha, Dr.
Shrimati Piilai, Shri J. S. Poonacha, Shri
C. M. Prasad, Prof. B. N. Punnaiah, Shri
Kola Puttappa, Shri Patil Rajagopalan,
Shri G. Ramachandran, Shri G.
Ramasv.amy. Shri K. S. Ramaul. Shri
Shiva Nand Rao, Shri B. Ramakrishna
Rao! Shri V. C. Keshava Ray, Dr. Nihar
Ranjan Ray, Shri Ramprasanna Reddy,
Shri M. Govinda Reddy, Shri N.
Narotham Reddy' Shri N. Sri Rama
Sadiq Ali, Shri Sahai, Shri Ram Sait,
Shri Bbrahim Sulaiman Sanjivayya,
Shri D. Sapru, Shri P. N. Sarla
Bhadauria, Shrimati Satyanarayana,
Shri M. Savnekar, Shri Baba Saheb
Seeta Yudhvir, Shrimati Sethi. Shri P.
C. Shah, Shri K. K. Shah. Shri M. C.
Shakuntala Paranjpye, Shrimati Shanta
Vasisht, Kumari Sharda Bhargava,
Shrimati Sharma, Shri L. Lalit Madhob
Sherkhan, Shri Sheirvani, Shri M. R.
Shukla, Shri M. P. Shyam Kumari
Khan, Shrimati Siddhu, Dr. M. M. S.
Singh, Dr. Anup Singh, Thakur Bhanu
Pratap Singh. Dr. Gopal Singh. Shri
Jogendra Singh, Shri Mohan Singh',
Shri Santokh Sinha, Shri B. K. P. Sinha,
Shri Ganga Sharan Sinha, Shri R. B.
Sinha, Shri Rajendna Pratap Sinha, Shri
R. P. N. Sur, Shri M. M. Syed Mahmud,
Shri Tankha, Pandit S. S. N. \ Tapase,
Shri G. D.

Tara Chand, Dr.
Tara Ramchandra Sathe, Shrimati
Tariq, Shri A. M.
Thanglura, Shri A.
Tiwary, Pt. Bhawaniprasad
Tripathi, Shri H. V.
Varma, Shri B. B.
Varma, Shri C. L.
Vasan, Shri S. S.
Venkatappa, Shri J.
Yenkateswara Rao, Shri N.
Vero, Shri M.
Vijaivargiya, Shri Gopikrishna
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Zaidi, Col. B. H.

NOES—9

Abdul Ghani, Shri Mariswamy, Shri S. S. Misra, Shri Lokanath Patel, Shri Dahyabhai V. Patel, Shri Sundar Mani Ruthnaswamy, Shri M. Singh, Shri Devi Singh, Shri J. K. P. N. Singh Dev, Shri Sankar Pratap

The motion was adopted by a *majority of the. total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.*

Clause 2 *was added to the Bill.*

Clause 3—*Amendment of Ninth Schedule*

THE DEPUTY CHAIRMAN; The question is;

"That clause S stand part of the Bill."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes —176; Noes—10.

AYES—176

Abdul Samad, Shri A. K. A. Abdul Shakoor, Moi'j'ana Abid A]i, Shri Abraham, Shri P. Ahmad, Shri Syed Ammanna Raja, Shrimati C. Anandan, Shri T. V. Anis Kidwai, Shrimati Annapurna Devi TMrniwareddy, Shrimati
Anwar, Shri N. M.
Arora, Shri Arjun
Asthana, Shri L. D.
Atwal, Shri Surjit Singh
Baghel, Shri K. C.
Baharul Islam, Shri
Banerjee, Shri Tara Shanker
Bansi Lai, Shri
Barooah, Shri Lila Dhar
Bedavati Buragohain, Shrimati
Bhargava, Shri B. N.
Bhargava, Shri M. P.
Bhuwalka, Shri R. K.
Bobdey, Shri S. B.
Ch-aman Lai], Diwan
Chandra Shekhar, Shri
Chandrasekhar, Dr. S.
Chatterji, Shri' J. C.
Chavda, Shri K. S.
Chengalvaroyan, Shri T.
Chetia, Shri P.
Chinai, Shri Babubhai M.
Damodarar., Shri K.
Das, Shri L. N.
Das, Shri N. K.
Dasgupta, Shri T. M.
Dass, Shri Mahabir
Deb, Shri S. C.
Deokinandan Narayan, Shri
Desai. Shri D. B.
Desai, Shri Khandubhai K.
Desai, Shri Suresh J.
Devaki Gopidas, Shrimati
Dharia, Shri M. M.
Dikshit, Shri Umashankar '
Diwakar, Shri R. R.
Doogar, Shri R. S.
Dutt, Shri Krishan
Gaikwad, Shri B. K.
Ghosh, Shri Niren
Ghosh, Shri Sudhir
Gilbert, Shri A. C.
Gujral, Shri I. K.
Gupta, Shri Bhupesh
Gupta, Shri Gurudev
Gurupada Swamy, Shri M. S.
Hathi, Shri Jaisukhlal
Iyer, Shri N. Ramakrishna
Jahanara Jaipal Singh, Shrimati
Jairamdas Daulatram, Shri
J'oshi, Shri J. H.
Kakati, Shri R. N.
Karmarkar, Shri D. P.
Kathju, Shri P. N.
Khan, Shri Akbar AH
Khan, Shri M. Ajmal

Khandekar, Shri R. S.
Kothari, Shri Shantil-al
Koya, Shri Palat Kunhi
Kulkarni, Shri B. T.
Kumaran, Shri P. K.
Ku'mbha Ram, Shri
Kurre, Shri Dayaldas
Lai, Prof. M. B.
Mahanti, Shri B. K.
Mallik, Shri D. C.
Malviya, Shri Ratanal Kishorilal
Maniben Vallabhbhai Patel, Kumari
Mary Naidu, Miss
Mathen, Shri Joseph
Mehta, Shri M. M.
Meht-a, Shri Om
Mir, Shri G. M.
Mishra, Shri L. N.
Mishra, Shri S. N.
Misra, Shri M.
Mitra, Shri P. C.
Mohammad, Chaudhary A.
Mohinder Kaur, Shrimati
Moideen, Shri M. J. J.
Momin. Shri G. H. Valimohmed
Muhammad Ishaque, Shri
Nafisul Hasan, Shri
Nagpure, Shri V. T.
Nair, Shri C. K. Govindan
Nair, Shri M. N. Govindan
Nandmi Satpathy, Shrimati
Nanjundaiya, Shri B. C.
Narasimha Rao, Dr. K. L.
Neki Ram, Shri
Pande, Shri C. D.
Pandt, Shri T.
Panjhazari, Sardar Raghbir Singh
Parthasarathy, Prof. (Mrs.) G.
Pathak, Shri G. S.
Pat.il, Shri P. S.
Patil, Shri U. S.
Fatra Shri N.
Pntla'mraman, Shri T. S.
Pawar, Shri D. Y.
Phulrenu Guha, Dr. Shrimati
Pillai, Shri J. S.
Poonacha, Shri C. M.
Prasad. Prof. B. N.
Punnaiah, Shri Kota
Puttappa, Shri Patil
Rajagopalon, Shri G.
Ramachandran, Shri G.
Ramaswamy, Shri K. S.
Barnaul, Shri Shiva Nand
Rao. Shri B. Ramakrishna
Rao, Shri V. C. Kesava Ray, Dr. Nihar Ranjan Ray, Shri Ramprasanna Reddy, Shri M. Govinda Reddy, Shri N. Narotham Reddy, Shri N. Sri Rama Sadiq AH, Shri Sahai, Shri Ram Sait, Shri Ebrahirn Sulaiman
Sanjivayya, Shri D. Sapru, Shri P. N. Sarla Bhadauria, Shrimati Satyanarayana, Shri M. Savnekar, Shri Baba Saheb Seeta Yudhvir, Shrimati Sethi, Shri P. C. Shah, Shri K. K. Shah, Shri M. C. Shakuntala Paranjpye, Shrimati Shanta Vasisht, Kumari Sharda Bhargava, Shrimati Sharma, Shri L. Lalit Madhob Sherkhan, Shri Sheirvani, Shri M. R. STiukla, Shri M. P. Shyam Kumari Khan, Shrimati Siddhu, Dr. M. M. S. Singh, Dr. Anup Singh, Thakur Bhanu Pratap Singh, Dr. Gopal Singh, Shri Jogendra Singh, Shri Mohan Singh, Shri Santokh Sinha, Shri B. K. P. Sinha, Shri Ganga Sharan Sinha. Shri R. B. Sinha, Shri Rajendra Pratap Sinha, Shri R. P. N. Sur. Shri M. M. Tankha, Pandit S. S. N. Tapase, Shri G. D. Tara Chand, Dr.
Tara Ramchandra Sathe, Shrimati
Tariq, Shri A. M. Thanglura, Shri A.
Tiwary, Pt. Bhawaniprasad Tripathi, Shri H. V. Varma, Shri B. B. Varma, Shri C. L. Vasan, Shri S. S. Venkatappa, Shri J.
Venkateswara Rao, Shri N. Vero, Shri M. Vijaivargiya, Shri Gopikrishna Vyas, Shri Ramesh Chandra | Zaidi. Col. B. H.

NOES—10

Abdul Ghani, Shri Mani, Shri A. D. Mariswamy, Shri S. S. Misra, Shri Lokanath Patel, Shri Dahyabhai V. Patel, Shri Sundar Mani Ruthnaswamy, Shri M. Singh, Shri Devi Singh, Shri J. K. P. N. Singh Dev, Shri Sankar Pratap

The motion was adopted by a majority of th$_e$ total membership of the House and by a majority of not less than Uoo-thirds of the Members present and voting.

Clause 3 *was added to the Bill.*

Clause I, *the Enacting Formula and the* 7 i

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part ol the Bill."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes— 177; Noes—2.

AYES—177

Abdul Samad, Shri A. K. A.
Abdul Shakoor, Moulana
Abid Ali, Shri
Abraham, Shri P.
Ahmad, Shri Syed
Ammanna Raja, Shrimati C.
Anandan, Shri T. V.
Anis Kidwai, Shrimati
Annapurna Devi Thimmareddy, Shrimati Anwar, Shri N. M.
Arora, Shri Arjun Asthana, Shri L. D. Atwal, Shri Surjit Singh Baghel, Shri K. C.
Bnharul Islam, Shri
Bansi Lai, Shri
Barooah, Shri Lila Dhar
Bedavati Buragohain, Shrimati
Bhargava, Shri B. N.
Bhargava, Shri M. P.
Bhuwalka, Shri R. K.
Bobdey, Shri S. B.
Chaman Lall, Diwan
Chandra Shekhar. Shri
Chandrasekhar, Dr. S.
Chatterji, Shri J. C.
Chavda, Shri K. S.
Chengalvaroyan, Shri T.
Chetia, Shri P.
Chinai, Shri Babubhai M.
Damodaran, Shri K.
Das, Shri L. N. Das, Shri N. K.
Dasgupta, Shri T. M. Dass. Shri Mahabir Deb, Shri S. C. Deokinandan Narayan, Shri Desai, Shri D. B'.
Desai, Shri Khandubhai K. Desai, Shri Suresh J. Devaki Gopidas, Shrimati Dharia, Shri M. M. Dikshit, Shri Umashankar Diwakar, Shri R. R.
Doogar, Shri R. S.,, Dutt, Shri Krishan Gaikwad, Shri B. K. Ghosh, Shri Niren Ghosh, Shri Sudhir
Gilbert, Shri A. C. Gujral, Shri I. K.
Gupta, Shri Bhupesh Cupta, Shri
Gurudev Gurupada Swamy, Shri M. S.
Hathi, Shri Jaisukhlal Iyer, Shri N. Ramakrishna Jahanara Jaipal Singh, Shrimati Jairamdas Daulatram, Shri
Joshi, Shri J. H. Kakati, Shri R. N.
Karmarkar, Shri D. P. Kathju, Shri P. N. Khan, Shri Akbar Ali Khan, Shri M. Ajmal Khandekar, Shri R. S.
Kothari, Shri Shantilal Koya, Shri Palat Kunhi Kulkarni, Shri B. T.
Kumaran, Shri P. K.
Kumbha Ram, Shri
Kurre, Shri Dayaldas

Lai, Prof. M. B.
Mahanti, Shri B. K.
Mallik, Shri D. C.
Malviya, Shri Ratanlal Kishorilal
Mani, Shri A. D.
Maniben Vallabhbhai Pate], Kumari
Mary Naidu, Miss
Mathen, Shri Joseph
Mehta, Shri M. M.
Mehta, Shri Om
Mir, Shri G. M.
Mishra, Shri L. N.
Mishra, Shri S. N.
Misra, Shri M.
Mitra, Shri P. C.
Mohammad, Chaudhary A.
Mohinder Kaur, Shrimati
Moideen, Shri M. J. J.
Momin, Shri G. H. Valimohmed
Muhammad Ishaque, Shri
Nafisul Hasan, Shri
Nagpure, Shri V. T.
Nair, Shri C. K. Govindan
Nair, Shri M. N. Govindan
Nandini Satpathy, Shrimati
Nanjundaiya, Shri B. C.
Narasimha Rao, Dr. K. L,
Neki Ram, Shri
Pande, Shri C. D.
Pande, Shri T.
Panjhazari, Sardar Raghbir Singh
Parthasarathy, Prof. (Mrs.) G.
Pathak, Shri G. S.
Patil, Shri P. S.
Patil, Shri U. S.
Patra, Shri N.
Pattabiraman, Shri T. S.
Pawar, Shri D. Y.
Phulrenu Guha, Dr. Shrimati
Pillai, Shri J. S.
Poonacha, Shri C. M.
Prasad, Prof. B. N.
Punnaiah, Shri Kota
Puttappa, Shri Patil
Rajagopalan, Shri G.
Ramachandran, Shri G.
Ramaswamy, Shri K. S.
Ramaul, Shri Shiva Nand
Rao, Shri B. Ramakrishna
Rao, Shri V. C. Kesava
Ray, Dr. Nihar Ranjan
Ray, Shri Ramprasanna
Reddy, Shri M. Govinda
Reddy, Shri N. Narotham
Reddy, Shri N. Sri Rama
Sadiq Ali, Shri
Sahai, Shri Ram
Sail. Shri Ebrahim Sulaiman
Sanjivayya, Shri D.
Sapru, Shri P. N.
Sarla Bhadauria, Shrimati
Satyanarayana, Shri M,
Savnekar, Shri Baba Sahel*
Seeta Yudhvir, Shrimati
Sethi, Shri P. C.
Shah, Shri K. K.
Shah, Shri M, C.
Shakuntala Paranjpye, Shrimati
Shanta Vasisht, Kumari
Sharda Bhargava. Shrimati
Sharma, Shri L. Lalit Madhob
Sherkhan, Shri
Shcrvani, Shri M. *K*
Shukla, Shri M. P.
Shy am Kumari Khan, Shrimati
Siddhu, Dr. M. M. S.
Singh, Dr. Anup
Singh, Thakur Bhanu Pratap.
Singh, Dr. Gopal
Singh, Shri" Jogendra
Singh, Shri Mohan
Singh, Shri Santokh
Sinha, Shri B. K. P
Sinha, Shri Ganga Sharan'
Sinha, Shri R. B.
Sinha, Shri Rajendra Pratap-
Sinha, Shri R. P. N.
Sur, Shri M. M.
Syed Mahmud, Shri
Tankha, Pandit S. S. N.
Tapase, Shri G. D.
Tara Chand, Dr.
Tara Ramchandra Sathe. Shri)
Tariq, Shri A. M.
Thanglura, Shri A.
Tiwary, Pt. Bhawaniprasad
Tripathi, Shri H. V.
Varma, Shri B. B.
Varma, Shri C. L.
Vasan, Shri S. S.
Venkatappa, Shri J.
Venkateswara Rao, Shri N.
Vero. Shri M.
Vijaivargiya, Shri Gopikrishna
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Zaidi, Col. B. H.

NOES—2

Abdul Ghani, Shri
Singh Dev, Shri Sankar Pratap

The motion was adopted by a majority of the tota\ membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, *the Enacting Formula and* the *Title were added to the Bill.*

SHRI A. K. SEN: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Madam, will you allow me to say a few words?

We have listened patiently to what has been said from the other side. We have tried to regulate our speeches, to restrain ourselves in. the context of what has happened only a few days earlier. Unfortunately, my friend, Mr. Bhupesh Gupta, sitting next to me, is unrestrained and cannot be controlled even by his Congress friends because, as I havt said here in this House earlier, he wants to drive the Congress party, and he has tried to demonstrate that he is driving the Congress Party. The Congress Party has lost all life. It is Mr. Gupta who is driving it, it is his party which is driving the Congress Party.

(Interruptions)

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Unfortunately, today Mr. Gupta i_s not i_n that happy position in which he wa; two years ago. His party people do not know whether they are to look to Russia or to China for leadership. We know it very clearly. *(.Interruptions)* If you can read the newspapers, you should know that. And it is the friends of Mr. Gupta, who ar_e supplying it. If you want to read it, read it. If 3 on cannot read it, I cannot help you. Madam, Mr. Bhupesh Gupta was . . ,

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated) : Ma_v I ask him a question . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Will you kindly wait? I will answer your question after I finish my speech.

(.Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Mr. Bhupesh Gupta talked of the moral weaknesses of the case of the Opposition. *(Interruptions)* The moral weakness of the Communist Party—the violence and bloodshed that they have indulged in during all these years, this suppression of truth, the subversion of public opinion, the suppression of opposition, all things are well known all over the world. What is happening in China today? Doe_s anybody know?

SHRI P. N. SAPRU: How is the Communist Party of India responsible for what is happening in China?

(Interruptions) SHRI DAHYABHAI V. PATEL: 1 am grateful to the learned Dr. Sapru for reminding me but do we not know that there is a Communist Chinese wing in the Communist Party of India which finds that Mr. Gupta is getting pale and is not getting hard enough? Is not Dr. Sapru aware of it? *(Interruptions)* Otherwise, he would not have asked this question. A supporter of Mr. Bhupesh Gupta sitting behind me—I think his name is Mr. Damodaran—exhibited gross ignorance when he spoke that the *ryotwari* system was something that was made by the British. The history of the record of land revenue systems Tn India, if he takes a little trouble to read it. wil] show that the *ryotwari* system in India existed long before the British came. In fact, it was a system that the Moghuls respected, that the Mara. thas respected and the British respected because it was the system that worked, it w as the system that led to better production, it was the system that led to better cultivation and increase in the land revenue. That is history. But. of course, in Communist jargons neither history nor truth

has to be taken into account. The only thing to be taken into account is what comes from the leader.

Madam, we are told by the hon. the Law Minister to rely upon his word and intentions. Madam, my mind goes back to the days when Dr. Ambed-kar adorned the Chair of the Law Ministry and he gave an assurance, not only to the Constituent Assembly but to the whole country, as to the rights of the peasants. The rights of the peasants are in jeopardy, I repeat it. The Congress is misleading; it is speaking in terms of the Communist jargon.

. SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: My friends on the opposite if they only read what Dr. Ambedkar said, if they can and what this Bill says, if they can, they would not become so impatient. Dr Ambedkar says that it is never the intention of this legislation to deprive the small peasant of his land. Now, unfortunately, Dr. Ambedkar did not foresee the manner in which the Congress Party was going to be driven by the Communist friends, when the meaning of "small" is going to be made variable according to the sweet will and pleasure of the Chief Minister of every State. I grant that the measure will have to go to the State As-iemblies. That is perfectly true. But what happens in the State Assemblies is well known.

SHRI M. M. DHARIA: If a cei'ing is to be fixed or if it is to be changed, then it is the legislature that can do it and not the Chief Minister.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Madam, in theory, according to the law I am quite, agreeable to concede the points of my hon. friend but in practice we have seen how my friend opposite has displaced Mr. Sonusing Dhansing Patil just at the will of the Chief Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Patel ...

338 RSD—6

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: That is exactly what I am trying to point out. I am just trying to point out how it goes in practice, Madam, and if I was not interrupted I would not have given an explanation of this tJPe.

(Shri *G. Ramachandran stands* up in *his seat.)*

The hon. gentleman there was trying to interrupt me. I will answe» your question, if you like.

SHRI G. RAMACHANDRAN; You began by saying that you will speak with restraint; if this is the meaning of the word "restraint", we shall have to rewrite the English dictionary.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL; The hon. Member opposite is a newcomer to the House. I commend hJn to see my remarks and my speeches earlier, particularly the speech On the Third Five Year Plan. There I pointed out through the writings of the Prime Minister himself that he was taking us to communism. I refrain from uttering these words under the present circumstances. I could have quoted chapter and verse and repeated it. But I did not want to do it. That is what I meant by "restraint". It was in the same spirit, not with a view to shelving this Bi'l—I know this majority is not going to come to an end in a month or two months' time when the August Session comes—that I made the humble suggestion to the Government that they should set their house in order, not as Mr. Bhupesh Gupta was trying to misrepresent me. I made a humble suggestion to the Government that under the present circunrtances it would not be fair to the Government, to the country, to the House or to the Legislature to come before this House when there was no proper Prime Minister and a proper Cabi-net. Madam, only we saw an exhibition yesterday of what type of Cabi-

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

net there is. I need not say more about it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gaikwad wants to say something.

SHRI B. K. GAIKWAD; On a point of explanation. My hon. friend, Mr. Dahyabhai Patel referred to the name of Dr. Babasaheb Ambedkar. He said that Dr. Babasaheb Ambedkar was in favour of Swatantra Party's proposal. Let me explain what he has said because I know Dr. Babasaheb Ambedkar better than himself. Not only that I can even tell the House that Dr. Babasaheb Ambedkar was in favour of nationalisation of land and our party in his presidentship had passed resolutions to that effect.

SHRI BHUPESH GUPTA: Now, J think after this intervention has been made the Congress Party will do well to help him recover from the shock. Now, Madam Deputy Chairman, it was not my intention to speak at the third reading over a measure which is about to be passed with the agreement of the House. Madam, we reached a stage before he spoke when the Swatantra Party came down to 2 at the last stage of voting.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Again Communist misrepresentation, Madam.

SHRI BHUPESH GUPTA: I have sometimes known ranks retreating under heavy fire, but here I find that the rear guard was trying to maintain its fight when Mr. Dahyabhai Patel retreated by not voting against any more. It is a good thing. Now it is for the Swatantra Party to decide as to who is going to lead. They seem to be more loyal to the politics of the party.

SHRI LOKANATH MISRA: It is not like the Communist Party with Mr. Dange going one way and Mr. Bhu-pesh Gupta going the other way.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): It seems Mr. Lokanath Misra is coming up as the future leader of the Swatantra Party.

SHRI BHUPESH GUPTA; The Swatantra Party morale hai been weakened and it has been amply demonstrated at the last voting how weak it is. Stocks fell from 9 to 2.

SHRI LOKANATH MISRA: Last voting is coming.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, how flattering would it be for once to be told that a humble chap like me or a small party like ours are driving the Congress Party. I can only say here that it is not the Communist Party which is driving the Congress Party, it is the democratic public of the country, including the Congress which is good and robust, which is driving the Treasury Benches to this amendment. That is how I view it. We share in this act of wisdom. We are not partisan in this matter. If the Congress Party brings forward good measures, humble as we are, we get up to support them with all our force while Mr. Dahyabhai Patel gets up always to draw upon and exploit the anti-Communist prejudices of some people in the Congress Party so as to divide them, create confusion among them so that every time they come uo with this measure they are faced with this kind of opposition. Of course, he does not understand anything about Communism at all- None the less this is their logic and political tactics. But I know the Congress people there. While we may disagree with them, they are very very experienced, a party which is sixty years—and not six months oM like the Swatantra Party. Therefore he should at least realise that such a party which is old in «x-perience cannot be carried away or misled by this kind of infantile propaganda which he is making here I think that the Swatantra Party should learn. Therefore, I do not

feel flattered at all. I am very much sorry that again Swatantra intelligence is at a discount even in such matters.

Now, Madam, he needlessly brought in the question of China and Russia. We thought we were discussing in the Indian Parliament an Indian legislation, as we do in the various parties here. How China comes or Rursia comes or, for that matter, if you like and with your permission, the United States of America comes in this matter? Therefore these are all irrelevant things. And he had criticised my colleague Damodaran that he does not understand history. Well, a party of superannuated and ancient politicians need not teach us modern history. We understand it very well. My regret is this. The leader of the Swatantra Party has so understood the history they are very very experienced, a party to join not the Communist Party, but the Swatantra Party; from modern industrial Bombay he has travelled to Rajasthan, the land °f feudalism. That is his progress in history. We[1]!, I would like him to be saved from them, because the journey he has started is a backward journey and we want to prevent this journey being carried forward further.

SHRI LOKANATH MISRA: But if you travel from a democracy to a totalitarian dictatorship, what is the wrong in him?

SHRI BHUPESH GUPTA: As far as you are concerned, my deaf friend, you were standing on the wayside; you have by mischoice got into the wrong band wagon—that is about all—because I cannot imagine that you are of the same breed of the Maha-rani Gayatri Devi, or of the Maharaja of Jaipur. It is one of the wonders to me why a man of commonplace like me . . .

SHRI LOKANATH MISRA: Because I consider the communists extremely dangerous.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Bhupesh Gupta, please speak *on.* the motion for the passing of the Bill.

SHRI BHUPESH GUPTA: If you think the communists are extremely dangerous, and suffer from that psychological trouble, go to a, psychologist and have it treated for, as to why you have joined the Swatantra Party.

SHRI LOKANATH MISRA: I do not have an invitation from Russia to go to a doctor there and be examined by him.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think the treatment that you need is one that relates to the sphere of psychology, not of medicine. Now, therefore, I say Mr. Dahyabhai Patel is very, very consitent about it.

And finally I should like to say, it was very unfortunate . . .

SHRI G. RAMACHANDRAN: May I interrupt you for a moment? Madam Deputy Chairman, how long are we Members, On the floor of this House, to listen to this duet of hate between two parties?

SHRI BHUPESH GUPTA: As long as it is necessary, and the Swatantra Party is not thoroughly exposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta, please finish now.

SHRI BHUPESH GUPTA: Here he made a very uncharitable remark that I, on this sad occasion, spoke very vehemently without restraint. 1 do not think I spoke without restraint. I spoke with the vehemence and spirit of Jawaharlal Nehru today. This is what I spoke with as far as this Bill is concerned; this is what, I think, I spoke with—may be my language is not so good; of course not, but this is how I feel; I want to uphold the tradition? in him. Well, what is the use? You can smile a^d kill me. What does it matter if a man is killed

[Shri Bhupesh Gupta.] while you are killing him with a smile or otherwise—with a frown? Therefore restraint there is no good. Even so you have not exhibited any restraint towards the end. That is always true.

THE -DEPUTY CHAIRMAN: I think that will do Mr. Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefor, Madam, I do not wish to say very much. After the retreat the Swatantra has registered on the voting board, I think they will take a lesson and try to gradually reconcile themselves to the ways of democracy and progress.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

(The *House divided)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes-177; Noes—9.

AYES—177

Abdul Samad, Shri A. K. A
Abdul Shakoor, Moulana
Abid Ali, Shri
Abraham, Shri P.
Ahmad, Shri Syed.
Ammanna Ra.ia, Shrimati C.
Anandan, Shri T. V.
Anis Kidwai, Shrimati
Annapurna Devi Tbimmareddy, Shrimati Anwar, Shri N. M.
Arora, Shri Arjun Asthana, Shri L.
D. Atwal, Shri Surjit Singh Baghel, Shri K. C. Baharul Islam, Shri Bansi Lai, Shri Barooah, Shri Lila Dhar Bedavati Buragohain, Shrimati Bhargava, Shri B. N. Bhargava, Shri M. P. Bhuwalka, Shri R. K.
Bobdey, Shri S. B. Chagla, Shri M. C. Chaman Lall, Diwan
Chandra Shekhar, Shri
Chandrasekhar, Dr. S. Chatterji, Shri J. C. Chavda, Shri K. S. Chengalvaroyan, Shri T. Chetia, Shri P. Chinai, Shri Babubhai M. Damodaran, Shri K. Das, Shri L. N. Das, Shri N. K. Dasgupta, Shri T. M. Dass, Shri Mahabir Deb, Shri S. C. Deokiriandan Narayan, Shri Desai, Shri D. B. Desai, Shri Khandubhai K. Desai, Shri Suresh J. Devaki Gopidas, Shrimati Dharia, Shri M. M. Dikshit, Shri Umashankar Diwakar, Shri R. R. Doogar, Shri R. S. Dutt, Shri Krishan Gaikwad, Shri B. K. Ghosh, Shri Niren
Ghosh, Shri Sudhir
Gilbert, Shri A. C.
Gujral, Shri I. K.
Gupta, Shri Bhupesh
Gupta, Shri Gurudev
Gurupada Swamv, Shri M. S.
Hathi, Shri Jaisukhltl
Iver, Shri N. Ramakrishna
Jahanara Jaipal Singh, Shrimati
Jairamdas Daulatram, Shri
Joshi, Shri J. H.
Kakati, Shri R. N.
Karmarkar, Shri D. P.
Kathju, Shri P. N.
Khan, Shri Akbar Ali
Khan. Shri M. Aimal
Khandekar, Shri R. S.
Kothari. Shri Shantilal
Kova. Shri Palat Kunhl
Ku'karni, Shri B. T.
Kumaran, Shri P. K.
Kumbha Rsm. Shri
Kurre, Shri Davaldas
Lai. Prof. M. B.
Mahsnti, Shri B. K.
Mallik, Shri D. C.
Malviya. Shri Ratanlal Kishorilal
Mani Shri A. D.
Maniben Vallabhbhai Patel, Kumari
Marv Naidu, Miss
Mathen, Shri Joseph
Mehta, Shri M. M.
Mehta, Shri Om

Mir, Shri G. M.
Mishra, Shri L. N.
Mishra, Shri S. N.
Misra, Shri M.
Mitra, Shri P. C.
Mohammad, Chaudhary A.
Mohinder Kaur, Shrimati
Moideen, Shri M. J. J.
Momin, Shri G. H. Valimohmed
Muhammad Ishaque, Shri
Nafisul Hasan, Shri
Nagpure, Shri V. T.
Nair, Shri C. K. Govindan
Nair, Shri M. N. Govindan
Nandini Satpathy, Shrimati
Nanjundaiya, Shri B. C.
Narasimha Rao, Dr. K. L.
Neki Ram, Shri
Pande, Shri C. D.
Pande, Shri T.
Panjhazari, Sardar Raghbir Singh
Parthasarathy, Prof. (Mrs.) G.
Pathak, Shri G. S.
Patil, Shri P. S.
Patil, Shri U. S.
Patra, Shri N.
Pattabiraman, Shri T. S.
Pawar, Shri D. Y.
Phulrenu Guha, Dr. Shrimati
Pillai, Shri J. S. N
Poonacha, Shri C. M.
Prasad, Prof. B. N.
Punnaiah, Shri Kota
Puttappa, Shri Patil
Rajagonalan, Shri G.
Ramachandran, Shri G.
Ramaswamy, Shri K. S.
Ramaul, Shri Shiva Nand
Rao, Shri B. Ramakrishna
Rao, Shri V. C. Kesava
Ray, Dr. Nihar Ranjan
Rav, Shri Ramprasanna
Reddy, Shri M. Govinda
Reddy, Shri N. Narotham
Rpddv, Shri N. Sri Rama
Sadiq AH. Shri
Sqhai Shri Ram
Siit. Shri Ebrahim Sulaiman
Saniiwiv'a. Shri D.
S=mru, Shri P. N.
Satvanarayana. Shri M.
Savnekar. Shri Baba Saheb
Seeta Yudhvir. Shrimati
Se'hi, Shri P. C.
Shah, Shri K. K.
Shnh. Shri M. C.
Shakuntaia Paranjpye, Shrimati
Shanta Vasisht, Kumari
Sharda Bhargava, Shrimati
Sharma, Shri L. Lalit Madhob
Sherkhan, Shri
Shervani, Shri M. R.
Shukla, Shri M. P.
Shyam Kumari Khan, Shrimati
Siddhu, Dr. M. M. S.
Singh, Dr. Anup
Singh, Thakur Bhanu Pratap
Singh, Dr. Gopal
Singh, Shri Jogendra
Singh, Shri Mohan
Singh, Shri Santokh
Sinha, Shri B. K. P.
Sinha, Shri Ganga Sharan
Sinha, Shri R. B.
Sinha, Shri Rajendra Pratap
Sinha, Shri R. P. N.
Sur, Shri M. M.
Syed Mahmud, Shri
Tankha, Pandit S. S. N.
Tapase, Shri G. D.
Tara Chand, Dr.
Tara Ramchandra Sathe, Shrimati
Tariq, Shri A. M.
Thanglura, Shri A.
Tiwary, Pt. Bhawaniprasad
Tripathi, Shri H. V.
Varma, Shri B. B.
Varma, Shri C. L.
Vasan, Shri S. S.
Venkatappa, Shri J.
Venkateswara Rao, Shri N.
Vero, Shri M.
Vijaivargiva. Shri Gooikrishna
Vvas, Shri Ramesh Chandra
Zaidi, Col. B. H.

NOES—9

^bdul Ghani, Shri Mariswamv, Shri
S. S Misra. Shri Lokanath Pa+ei.
Shri Dahvabhai. V. Patel, Shri
Sundar Mani Ruthnaswamv, Shri M
Singh, Shri Devi Singh, Shri J. K. P.
N. Singh Dev, Shri Sankar Pratap

The motion was adopted bv a majority of the total membership of *the* I House *and by a* majority *of* not less

than two-thirds of t,he Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before we go to the next item on the order paper, Secretary will read out a Message.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE GOLD (CONTROL) BILL, 1963

SECRETARY: I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha: —

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on Friday, the 5th June, 1964, adopted the annexed motion in regard to the Gold (Control) Bill, **1963.**

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion and also the names of the members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this Houie."

MOTION

"That the Bill to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the production, supply, distribution, *use* and possession of, and business in, gold and ornaments and other articles of gold and for matters connected therewith, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30 from this House, namely:—

(1) Shri S. V. Krishnamoorthy Rao
(2) Shri D. Balarama Raju
(3) Shrimati Rehuka Devi Barkataki
(4) Shri Bali Ram Bhagat
(5) Shri Laxmi Narayan Bhanja Deo
(6) Shri B. L. Chandak
(7) Shri Tridib Kumar C'haudhuri
(8) Shri Yudhvir Singh Chaudhary
(9) Shri Homi F. Daji
(10) Shri M. M. Haq
(11) Shri Prabhat Kar
(12) Shri P. G. Karuthiruman
(13) Shri. Kindar Lai
(14) Shri H. V. Koujalgi
(15) Shrimati Sangam Laxmi Bai
(16) Shri Mathew Maniyangadan
(17) Shri M. R. Masani
(18) Shri Jashvant Mehta
(19) Sardar Gurmukh Singh Musafir
(20) Shri Chhotubhai M. Patel
(21) Shri T. Ram
(22) Shri Shivram Rango Rane
(23) Shri S. C. Samanta
(24) Shri Era Sezhiyan
(25) Shrj Sheo Narain
(26) Dr. L. M. Singhvi
(27) Shri Rameshwar Tantia
(28) Shri Balgovind Verma
(29) Shri Bhishma Prasad Yadava, and
(30) Shri T. T. Krishnamachari.

and 15 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations **and**